आर्थिक समीक्षा
Economic Review
1996-97

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

आर्थिक समीक्षा
Economic Review
1996-97

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन, राजस्थान, जयपुर
DIRECTORATE OF ECONOMICS & STATISTICS, YOJANA BHAVAN, RAJ., JAIPUR

प्रस्तावना

आर्थिक समीक्षा राज्य विधान सभा में राज्य बजट से पूर्व प्रस्तुत किये जाने वाला बजट से सम्बन्धित एक प्रलेख है। प्रस्तुत "आर्थिक समीक्षा 1996-97" जो कि इस श्रृंखला का तीसरा प्रकाशन है, में राज्य अर्थव्यवस्था के वृहद् परिदृश्य तथा राज्य में क्रियान्वित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों को रचनात्मक एवं तुलनात्मक ढंग से परिलक्षित करने का प्रयास किया गया है।

मैं आशा करता हूँ कि यह प्रकाशन जन प्रतिनिधियों, राजकीय विभागों, संगठनों, शिक्षाविदों एवं राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों के लिये उपयोगी सिद्ध होगा।

(भैरों सिंह शेखावत)
मुख्य मंत्री

Foreword

The Economic Review is Budget related document, presented in the Rajasthan Legislative Assembly in advance before the State's Budget. The present "Economic Review - 1996-97" is the 3rd edition in the series by which an attempt has been made to depict the macro level review of the economy as well as various programmes being implemented in the State in a dynamic and comparative framework.

I hope this publication will prove useful to public representatives, Government Departments, organisations, academicians and all those who are interested in Socio-Economic Development of the State.

(Bhairon Singh Shekhawat)
Chief Minister

भूमिका

आर्थिक समीक्षा, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा प्रतिवर्ष नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तुत "आर्थिक समीक्षा 1996-97" राज्य की अर्थ व्यवस्था के वृहद परिदृश्य, आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण सूचकों को रेखाचित्रों एवं मानचित्रों के द्वारा एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण गतिविधियों की प्रगति को प्रदर्शित करता है।

मैं उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होने इस प्रकाशन को समय पर तैयार करवाने में अपना योगदान दिया है।

मुझे विश्वास है कि यह प्रकाशन शोधकर्ताओं एवं उन सभी संस्थाओं जो राज्य के सामाजिक, आर्थिक विकास कार्य में संलग्न हैं, के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

(एम. के. खन्ना)
शासन सचिव,
आयोजना विभाग,
राजस्थान।

INTRODUCTION

The Economic Review is brought out by the Directorate of Economics & Statistics, Rajasthan, regularly every year. The present "Economic Review 1996-97" presents macro level overview of economy of the State, important indicators of economic growth along with charts and graphs and progress of important activities of various departments of the State.

I am grateful to all those who have made efforts in bringing out this publication in time.

I am sure this publication will be useful for research scholars and all those institutions engaged in the work of Socio-Economic Development of the State.

(M. K. Khanna)
Secretary to Government,
Planning Department,
Rajasthan.

विषय-सूची

CONTENTS

पृष्ठ संख्या
Page No.

I. आर्थिक समीक्षा
1996-97

	– आर्थिक विकास के मुख्य सूचक	i-v
1.	सामान्य पुनरावलोकन	1
	– वृहद् आर्थिक परिदृश्य	
2.	राज्य घरेलू उत्पाद एवं वित्त	7
	2.1 राज्य घरेलू उत्पाद	
	2.2 अष्टम् पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना 1996-97	
	2.3 बैंकिग	
3.	मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली	12
	3.1 थोक मूल्य सूचकांक	
	3.2 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	
	3.3 सार्वजनिक वितरण प्रणाली	
4.	उद्योग एवं खनिज	15
	4.1 उद्योग	
	4.2 खादी एवं ग्रामोद्योग	
	4.3 कारखाना एवं बॉयलर्स	
	4.4 खनिज	
	4.5 श्रम	
	4.6 रोजगार	
5.	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	21
	5.1 मानसून	
	5.2 कृषि उत्पादन	
	5.3 कृषि विस्तार एवं आदान प्रबन्धन	
	5.4 सिंचाई	
	5.5 पशु पालन	
	5.6 दुग्ध विकास	
	5.7 भेड़ पालन	
	5.8 मत्स्य पालन	
	5.9 वन	
	5.10 वन्य जीव संरक्षण	

	पृष्ठ संख्या **Page No.**
6. आधारभूत ढांचागत विकास	28
6.1 विद्युत	
6.2 गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत-रेडा	
6.3 परिवहन एवं संचार	
— सड़क	
— सड़क परिवहन	
7. सामाजिक आधारभूत विकास	32
7.1 मानव संसाधन विकास	
7.2 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
7.3 परिवार कल्याण	
7.4 जल-आपूर्ति	
7.5 आवास	
7.6 पिछड़ी जातियों का कल्याण	
7.7 समाज कल्याण	
7.8 महिला एवं बाल कल्याण	
8. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	39
8.1. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	
8.2 आधारभूत ढांचे का विकास एवं रोजगार सृजन के कार्यक्रम	
8.3. क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	
8.4 सिंचाई क्षमता सृजन एवं ऊर्जा विकास के कार्यक्रम	
9. अन्य कार्यक्रम	41
9.1 बीस सूत्री कार्यक्रम	
9.2 अकाल/ बाढ़ राहत	
9.3 अल्प बचत	
10. राजस्थान में किये गये आर्थिक सुधार	43
10.1 वाणिज्य कर	
10.2 अन्य कर	
10.3 ऊर्जा क्षेत्र	

II. आर्थिक स्थिति की तालिकाएं
TABLE OF ECONOMIC SITUATION

1. राजस्थान की राज्य आय औद्योगिक उद्भव प्रचलित कीमतों पर एवं प्रतिशत विभाजन State Income of Rajasthan by industrial origin at current prices and percentage distribution	46

पृष्ठ संख्या
Page No.

2.	राजस्थान की राज्य आय औद्योगिक उद्भव स्थिर (1980-81) कीमतों पर एवं प्रतिशत विभाजन State income of Rajasthan by industrial origin at constant (1980-81) prices and percentage distribution	48
3.	राजस्थान में कृषि उत्पादन का सूचकांक Index Numbers of Agricultural Production in Rajasthan	50
4.	औद्योगिक उत्पादन Industrial Production	54
5.	राजस्थान के थोक भाव सूचकांक Indices of Wholesale Prices in Rajasthan	56
6.	उपभोक्ता भाव सूचकांक Indices of Consumer Price	58
7.	राजस्थान में अकाल/अभाव स्थिति से हुई क्षति Loss due to Famine/Scarcity condition in Rajasthan	60
8.	राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक Statewise Important Economic Indicators	61

III. ECONOMIC REVIEW 1996-97

– Key Indicators of Economic Development 68

1. General Review 73
   – Macro Economic Overview
2. State Domestic Product and Finance 84
   - 2.1 State Domestic Product
   - 2.2 Eighth Five Year Plan and Annual Plan 1996-97
   - 2.3 Banking
3. Prices and Public Distribution System 92
   - 3.1 Wholesale Price Index Numbers
   - 3.2 Consumer Price Index Numbers
   - 3.3 Public Distribution System

		पृष्ठ संख्या **Page No.**
4.	Industries and Mines	96
	4.1 Industries	
	4.2 Khadi and Village Industries	
	4.3 Factories and Boilers	
	4.4 Mines and Minerals	
	4.5 Labour	
	4.6 Employment	
5.	Agriculture and Allied Sectors	107
	5.1 Monsoon	
	5.2 Agriculture Production	
	5.3. Agriculure Extension and Input Management	
	5.4 Irrigation	
	5.5 Animal Husbandry	
	5.6 Dairy Development	
	5.7 Sheep Husbandry	
	5.8 Fisheries	
	5.9 Forestry	
	5.10 Preservation of Wild Life	
6.	Basic Infrastructural Development	118
	6.1 Power	
	6.2 Non-conventional Sources of Energy - REDA	
	6.3 Transport and Communication	
	– Roads	
	– Road Transport	
7.	Social Infrastructural Development	123
	7.1 Human Resource Development	
	7.2. Medical and Health	
	7.3 Family Welfare	
	7.4 Water Supply	
	7.5 Housing	
	7.6 Welfare of Backward Classes	
	7.7 Social Welfare	
	7.8 Development of Women and Children	

	पृष्ठ संख्या Page No.
8. Rural Development and Panchayati Raj	135
8.1 Poverty Alleviation Programmes	
8.2 Development of Infrastructure and Generationa of Employment Programme	
8.3 Area Development Programme	
8.4 Irrigation Potential and Energy Development	
9. Other Programmes	139
9.1 Twenty Point Programmes	
9.2 Famine/ Flood Relief	
9.3 Small Savings	
10. Economic Reforms in Rajasthan	142
10.1 Commercial Taxes	
10.2 Other Taxes	
10.3 Power Sector	

❖ ❖ ❖

आर्थिक समीक्षा
1996-97

आर्थिक विकास के मुख्य सूचक

विवरण	इकाई	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97 (प्रावधानिक)
1	2	3	4	5	6
1. सकल घरेलू उत्पाद	करोड़ रू.				
(अ) प्रचलित कीमतों पर		28342	34978	38598	44881
(ब) स्थिर (1980-81) कीमतों पर		9492	11174	11273	12420
2. सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर आर्थिक वृद्धि दर	प्रतिशत				
(अ) प्रचलित कीमतों पर		4.08	23.41	10.35	16.28
(ब) स्थिर (1980-81) कीमतों पर		(-) 6.87	17.72	0.89	10.17
3. सकल राज्य घरेलू उत्पाद का स्थिर (1980-81) मूल्यों पर योगदान	प्रतिशत				
(अ) प्राथमिक		40.32	44.35	41.51	43.85
(ब) द्वितीयक		23.46	21.74	23.15	22.46
(स) अन्य सेवायें (तृतीयक)		36.22	33.91	35.34	33.69
4. शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद	करोड़ रु.				
(अ) प्रचलित कीमतों पर		24596	30641	33705	39460
(ब) स्थिर (1980-81) कीमतों पर		8329	9917	9936	11021
5. प्रति व्यक्ति आय	रुपये				
(अ) प्रचलित कीमतों पर		5287	6452	6958	7992
(ब) स्थिर (1980-81) कीमतों पर		1790	2088	2051	2232
6. कृषि उत्पादन सूचकांक आधार (1979-82=100)	सूचकांक	156.59	228.80	211.77	N.A.
7. कुल खाद्यान्न उत्पाद	लाख टन	70.55	117.10	95.66	127.02
8. औद्योगिक विनिर्माण उत्पाद सूचकांक (आधार 1970=100)	सूचकांक	309.86	316.44	327.03	निर्माणाधीन

चयनित मुख्य सूचक

सकल घरेलू उत्पाद

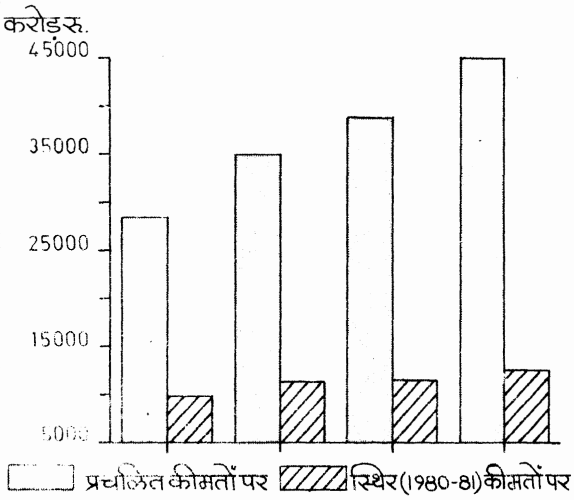

विद्युत उत्पादन

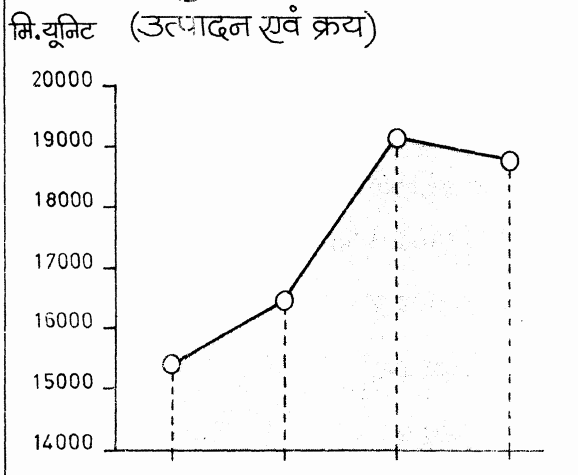

सकल घरेलू उत्पाद में वृहद् क्षेत्रों का प्रतिशत

स्थिर (1980-81) कीमतों पर

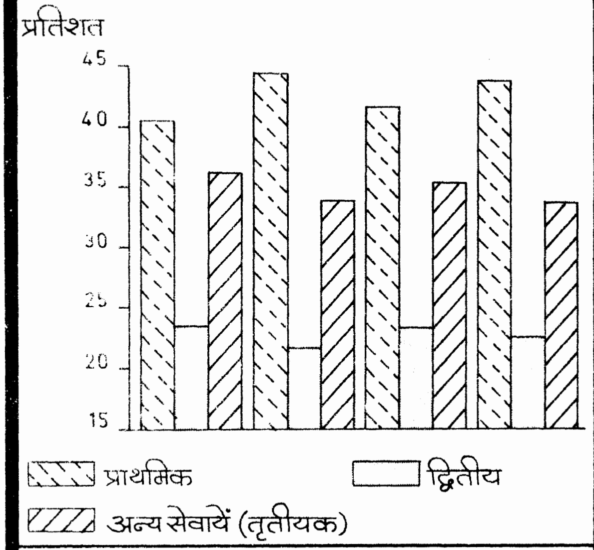

सामान्य थोक भाव सूचकांक

(आधार 1952-53 = 100)

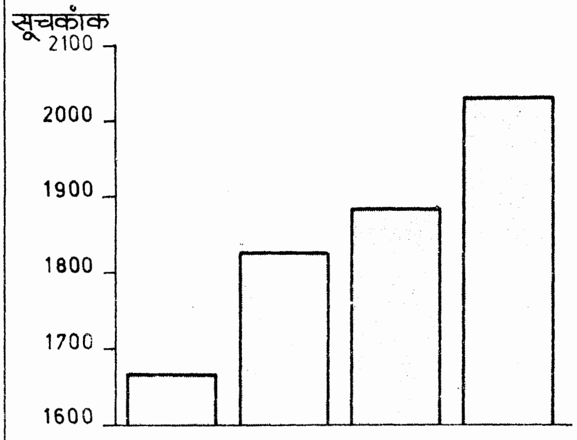

कुल खाद्यान्न उत्पादन

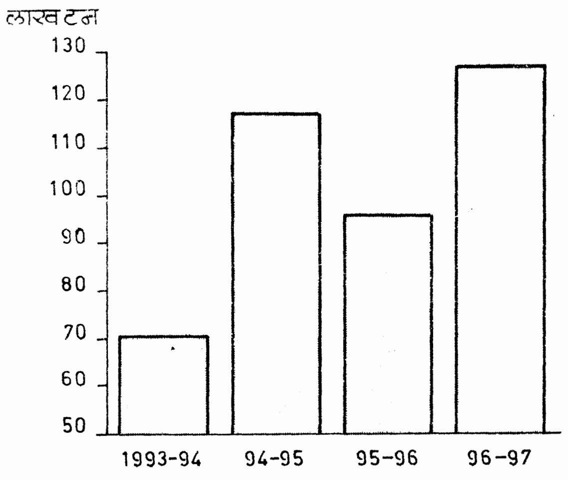

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक साख

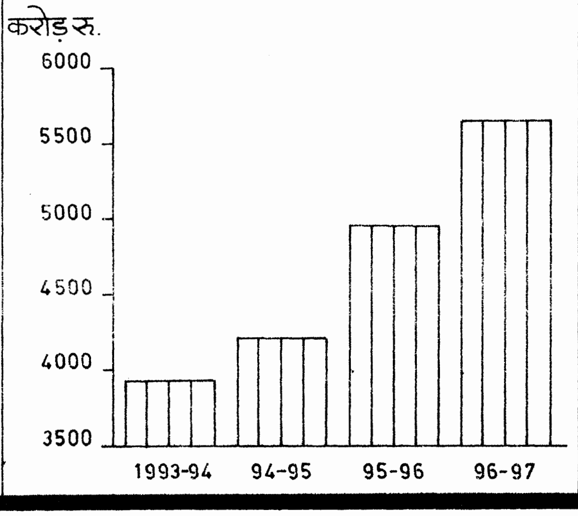

1		2	3	4	5	6
9.	सामान्य थोक भाव (आधार 1952-53=100)	सूचकांक				
	(अ) सूचकांक		1668.7	1827.61	1885.77	2038.82
	(ब) प्रतिशत वृद्धि		2.83	9.52	3.18	8.12
10.	औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामान्य उपभोक्ता सूचकांक (आधार 1982=100)	सूचकांक				
	(अ) जयपुर केन्द्र		245	269	291	321
	(ब) अजमेर केन्द्र		253	280	305	332
11.	विद्युत उत्पादन (उत्पादन+क्रय)	मिलियन यूनिट	15399.97	16423.50	19171.24	18727.65
	प्रतिशत वृद्धि	प्रतिशत	5.00	6.65	16.73	(-) 2.31
12.	वाणिज्यिक बैंक साख (सितम्बर तक)	करोड़ रु.	3912.00	4210.00	4955.00	5650.00
	प्रतिशत वृद्धि	प्रतिशत	11.55	7.62	17.70	14.03

\+ थोक भाव सूचकांक/उपभोक्ता सूचकांक कलैण्डर वर्ष पर आधारित है।

नोट :- सकल/शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एवं इस पर आधारित आर्थिक वृद्धि दर तथा स्थिर (1980-81) मूल्यों पर उसके प्रतिशत योगदान, से संबंधित समंक वर्ष 1993-94, 1994-95 (प्रावधानिक), 1995-96 के त्वरित एवं 1996-97 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर है।

प्रति व्यक्ति आय

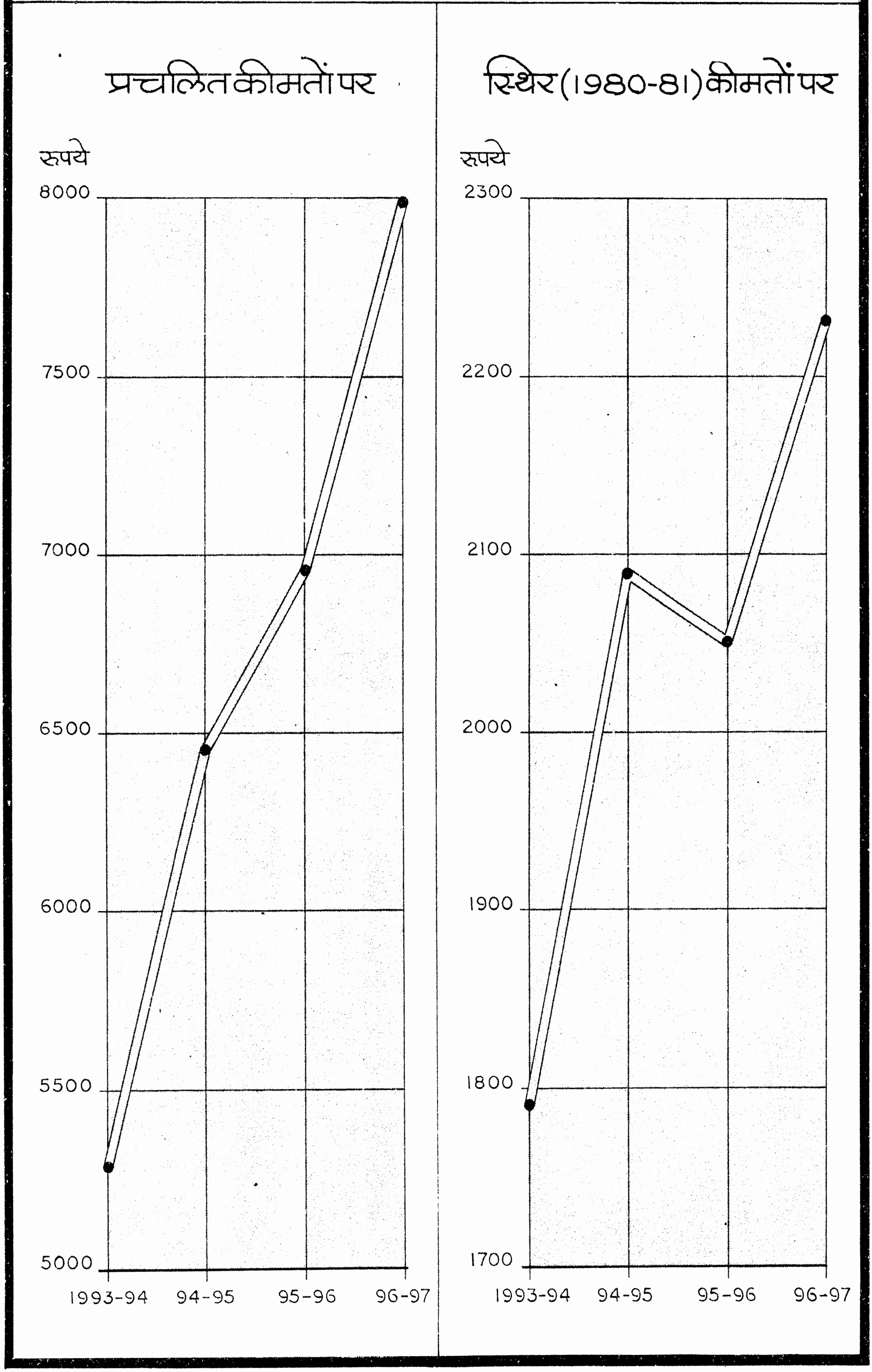
प्रचलित कीमतों पर
रुपये
8000
7500
7000
6500
6000
5500
5000
1993-94
94-95
95-96
96-97
स्थिर (1980-81) कीमतों पर
रुपये
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1993-94
94-95
95-96
96-97

1. सामान्य पुनरावलोकन 1996-97

वृहद आर्थिक परिदृश्य :

राजस्थान राज्य भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और इसकी भौगोलिक सीमाएं पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश व गुजरात राज्यों से जुड़ी हुई हैं। राज्य की एक लम्बी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। मध्यप्रदेश के बाद राजस्थान देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग कि.मी. है। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान राज्य 31 जिलों में विभाजित किया गया है तथा ये जिले पुन: 100 उपखण्डों तथा 229 तहसीलों में विभक्त हैं।

राजस्थान की प्रमुख विशेषताएं निम्न सारणी में दर्शायी गई हैं :-

तालिका 1.1

मद		वर्ष	इकाई	विवरण
1.	क्षेत्रफल	1991	लाख वर्ग कि.मी.	3.42
2.	जिले	1996	संख्या	31
3.	उपखण्ड	1996	संख्या	100
4.	तहसीलें	1996	संख्या	229
5.	जिला परिषदें	1996	संख्या	31
6.	पंचायत समितियां	1996	संख्या	237
7.	ग्राम पंचायतें	1996	संख्या	9185
8.	कुल गांव	1991	संख्या	39810
9.	कुल आबाद गांव	1991	संख्या	37889
10.	कुल कस्बे	1991	संख्या	222

राजस्थान की स्थलाकृति में विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला "अरावली" पहाड़ियों की प्रमुखता है। अरावली पर्वत राज्य के मुख्य भाग से होती हुई 692 कि.मी. तक फैली हुई है। इसके अलावा राज्य का एक बड़ा भू-भाग रेगिस्तानी है।

1991 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 4.40 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 5.20 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का क्रमश: 17.29 प्रतिशत व 12.44 प्रतिशत है, जबकि देश में इनका प्रतिशत क्रमश: 16.33 व 8.01 है।

राज्य की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है एवं देश की तुलना में राज्य में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक है। राज्य व राष्ट्र की जनसंख्या एवं उसमें हुई दशक वृद्धि दर की तुलनात्मक स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गई है।

तालिका 1.2

वर्ष	जनसंख्या (लाखों में)		दशक वृद्धि दर (प्रतिशत)	
	राजस्थान	भारत	राजस्थान	भारत
1951	160	3611	15.20	13.31
1961	202	4392	26.20	21.51
1971	258	5482	27.83	24.80
1981	343	6843	32.97	24.66
1991	440	8463	28.44	23.56

राज्य के जनसंख्या घनत्व में क्षेत्र दर क्षेत्र काफी भिन्नता है। राज्य का जनसंख्या घनत्व 129 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है, जबकि यह मरुथलीय क्षेत्र में 84 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. तथा अन्य क्षेत्रों में 203 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है।

राजस्थान विविधताओं वाला प्रदेश है। राज्य का पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी भाग जिसमें 11 जिले सम्मिलित हैं, यह कुल क्षेत्रफल का 61.11 प्रतिशत है तथा यह भाग भारत का महान् रेगिस्तान "थार" के नाम से जाना जाता है। राज्य के इस मरु भाग में 39.79 प्रतिशत आबादी निवास करती है। दक्षिण में 5.85 प्रतिशत क्षेत्रफल जो कि जनजातीय क्षेत्र है, उसमें 8 प्रतिशत व्यक्ति निवास करते हैं तथा शेष भाग जो कि 33.04 प्रतिशत है उसमें 52.21 प्रतिशत व्यक्ति निवास करते हैं।

सामान्य तौर पर देश के अन्य भागों की अपेक्षा राज्य की जलवायु शुष्क है। राज्य में वर्षा की कमी के कारण निरन्तर अकाल की स्थिति बनी रहती है। राज्य में वर्षा का औसत 58.64 से.मी. है, लेकिन शुष्क व अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में यह औसत और भी कम है।

राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की अर्थ व्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। कुल राज्य आय का 40 प्रतिशत से अधिक भाग कृषि एवं उससे संबद्ध कार्यकलापों से उपलब्ध होता है। कृषि उत्पादन में सिंचाई का सर्वाधिक महत्व है। राज्य में सतही जल स्रोतों की कमी है। वर्षा की अपर्याप्तता तथा विषम वितरण के कारण भूमिगत-जलस्तर नीचे जा रहा है। इससे कृषि में वर्षा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

वर्ष 1996 में वर्षा का आगमन कुछ विलम्ब से होने के बावजूद राज्य में अच्छी वर्षा हुई, जिससे खाद्यान्न व तिलहन उत्पादन में वर्ष 1996-97 के दौरान भारी वृद्धि की आशा है। वर्ष 1995-96 में 95.66 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में वर्ष 1996-97 में 127.02 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। वर्ष 1996-97 में तिलहन का उत्पादन 40.94 लाख टन होने का अनुमान है जो कि पूर्व वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है।

देश के कुल भू-भग में राज्य का भाग 10.40 प्रतिशत है, जबकि सतही जल का भाग देश के जल की तुलना में केवल 1.04 प्रतिशत ही है। इस दृष्टि से राज्य में जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। राज्य सरकार जल की उलपब्धता बढ़ाने हेतु भरसक प्रयत्न कर रही है। कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में जल बचत के साधन अपनाकर जल उपयोग में मितव्ययता एवं सदुपयोग पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का यह भी प्रयत्न है कि अन्तर्राज्यीय जल बंटवारे में राज्य को प्राप्त जल का समुचित उपयोग किया जावे।

इस समय श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों को इंदिरा गांधी नहर से पानी मिल रह है जबकि चंबल के पानी से कोटा, बारां, बूंदी एवं सवाई माधोपुर जिलों की जलापूर्ति होती है। माही बजाज सागर परियोजना के चालू होने से बांसवाड़ा जिले की जलापूर्ति में बढ़ोतरी हुई है। राज्य के पूर्वी भाग को जलापूर्ति अब यमुना जल से होने लगी है जबकि जालौर और बाड़मेर जिलों के क्षेत्र नर्मदा परियोजना से लाभान्वित होंगे।

राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों से उत्पन्न हुई औद्योगिक लहर ने एक नये औद्योगिक मार्ग को प्रशस्त किया है। राज्य सरकार ने एक "औद्योगिक नीति 1994" तैयार की है जिससे राज्य में निवेश का वातावरण बना है तथा राज्य में स्थापित होने वाले नये उद्योगों को आकर्षक प्रोत्साहन, सुविधाएं एवं रियायतें प्राप्त हुई हैं।

राज्य में औद्योगिक विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा नियमों एवं कार्यविधि में सुधार एवं सरलीकरण, त्वरित आदानों को सुनिश्चित करने, आधारभूत ढ़ाचें के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने, रोजगारोन्मुखी एवं ग्रामीण उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहन देने जैसे अनेक उपाय किये गये हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में 1920.38 करोड़ रुपये के निवेश से अब तक 1,82,828 लघु औद्योगिक एवं दस्तकार इकाईयां पंजीकृत हो चुकी हैं, तथा जिनमें 7.08 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो रहा है।

राजस्थान राज्य में औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको) राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगीकरण हेतु अहम् भूमिका अदा कर रहा है। रीको, औद्योगीक क्षेत्रों के विकास के अतिरिक्त उद्यमियों को सावधि ऋण सुविधा, सह भागीदारी एवं निवेश अनुदान आदि सहायता उपलब्ध करवाकर औद्योगीकरण को प्रोन्नत कर रहा है। जयपुर जिले में एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रीयल पार्क, इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर टैक्नोलोजी पार्क, सॉफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्क एवं ग्राम मानपुरा माचेड़ी (जयपुर) में लैदर कॉम्पलेक्स के विकास का कार्य

हाथ में लिया गया है। इसी प्रकार लैदर कॉम्पलेक्स भरतपुर एवं टैक्सटाईल शहर भीलवाड़ा आदि को भी विकसित किया जा रहा है। वर्ष 1996-97 में 2300 एकड़ भूमि अवाप्ति के लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर, 96 तक 2658 एकड़ भूमि अवाप्त की गई। इसके अतिरिक्त 1175 औद्योगिक प्लान्ट विकसित किये गये व दिसम्बर, 96 तक रीको द्वारा 456 औद्योगिक प्लाटों का आवंटन किया गया।

सरकार के सुधारवादी एवं नवीन उपायों से राज्य के औद्योगिक परिदृष्य में भारी बदलाव आया है। जिससे गत वर्षों की तुलना में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि ही नहीं अपितु उसमें विविधता भी आई है। इस समय राज्य सिंथेटिक-यार्न, सीमेन्ट, टी.वी. पिक्चर ट्यूब, रसायन एवं खाद यहां तक कि विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं आदि का बड़ा उत्पादक ही नहीं वरन् विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्यात भी करने लगा है।

राजस्थान ने खान एवं खनिज क्षेत्र में विशेष स्थान प्राप्त किया है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान खनिज भंडारों से सम्पन्न है। जिन महत्वपूर्ण खनिजों से राज्य का नाम बहुलता के साथ जुड़ा है, उनमें अलौह धातु (शीशा, जस्ता एवं तांबा) तथा लौह धातु जैसे टंगस्टन एवं अनेक औद्योगिक खनिज सम्मिलित हैं।

लघु खनिज मुख्यत: आयामी एवं सजावटी पत्थर जैसे मार्बल, कोटा स्टोन एवं सेंडस्टोन में राजस्थान का अपना विशेष स्थान है। देश के कुल लघु खनिज उत्पादन मूल्य में राजस्थान का लगभग 30 प्रतिशत योगदान है।

राज्य के जनजातीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकी से खनिज संपदा के त्वरित दोहन के लिये राज्य सरकार ने वर्ष 1994 में खनिज नीति लागू की है। नई खनिज नीति से विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों हेतु रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है।

राज्य का खान व भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम (आर.एस.एम.डी.सी.) एवं राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (आर.एस.एस.एम.) राज्य में त्वरित एवं वैज्ञानिक ढंग से खनिज दोहन के लिये कार्य कर रहे हैं।

ऊर्जा समस्त उत्पादक आर्थिक गतिविधियों के लिये अत्यंत आवश्यक आदान है। ऊर्जा के स्रोतों को विकसित करने हेतु गहन पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। इसी कारण राज्य के योजना मद में उर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में कुल योजना प्रावधान का लगभग 28.31 प्रतिशत राशि उर्जा क्षेत्र के लिये आवंटित की गई है।

प्रतिस्पर्द्धात्मक एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर आधारित खुले बाजार की अर्थव्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए उर्जा उत्पादन के क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा निजी क्षेत्र के निवेशकों के लिये राज्य के लिग्नाईट भंडारों को खोल दिया गया है।

दिसम्बर, 1996 तक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में 34015 गांवों (1991 की जनगणना के अनुसार) का विद्युतीकरण किया जा चुका है। विद्युतीकृत गांवों की यह संख्या कुल आबाद गांवों की संख्या का 89.77 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त 5.26 लाख कुओं को भी विद्युतीकृत किया जा चुका है।

राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण (रेडा) द्वारा राज्य में गैर परम्परागत स्रोतो के अन्तर्गत, सोलर पैक की स्थापना, एस पी वी स्ट्रीट लाइटों को सशक्त करना, एस पी वी पंपों की स्थापना, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम आदि का विकास किया जा रहा है। वर्ष 1996-97 के दौरान सोलर पावर पैक के माध्यम से 50 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य भी प्रारंभ किया गया है।

राज्य के त्वरित आर्थिक विकास हेतु यातायात एवं संचार माध्यमों का विकसित होना नितान्त आवश्यक है। यातायात एवं संचार की दृष्टि से राजस्थान एक अर्द्ध विकसित प्रदेश है। आंतरिक जलमार्गों की कमी एवं रेल प्रणाली के अपर्याप्त विस्तार के कारण सड़कें ही आवागमन का एक प्रमुख साधन हैं। सड़क संचार व्यवस्था के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में सड़क विकास नीति अपनाई गई है।

राज्य में वर्ष 1950-51 में सड़कों की कुल लंबाई 17339 कि.मी. थी जो कि वर्ष 1995-96 में बढ़कर 1,34,449 कि.मी. (अन्य विभागीय सड़कों सहित) हो गई तथा जिसके वर्ष 1996-97 के अन्त तक 1,37,949 कि.मी. हो जाने की संभावना है। राज्य का कुल सड़क घनत्व जो कि वर्ष 1995-96 के अंत में 39.29 कि.मी. प्रति 100 वर्ग कि.मी. था वह वर्ष 1996-97 में बढ़कर 40.31 कि.मी. (अन्य विभागीय सड़कों सहित) होने की संभावना है। यह अब भी राष्ट्रीय औसत 62.1 कि.मी. से काफी कम है।

राज्य के अनेक स्थानों पर छोटी रेल्वे लाईन को बड़ी लाईन में बदलने के वर्तमान में चल रहे कार्यों तथा प्रस्तावित भावी रेल्वे लाईनों के बदलने के कार्य में राज्य तत्परता से अग्रसर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर को मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता एवं चेन्नई से जोड़ दिया गया है तथा जोधपुर और बीकानेर भी बड़ी लाईन से जुड़ गये हैं। जिससे राज्य में औद्योगिक एवं खनिज विकास को काफी गति मिली है। राज्य में अनेक स्थानों पर छोटी लाईन को बड़ी लाईन में बदलने का कार्य प्रगति पर है।

भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये राजस्थान एक महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्र बनता जा रहा है। राजस्थान अपनी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सम्पन्नता व दुर्लभ वन्यजीव विशेषताओं के कारण, विश्व पर्यटन के मानचित्र पर अपना विशिष्ट स्थान बनाये हुए है। इन विशेष आकर्षणों के कारण, राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का विशेष महत्व है और इस क्षेत्र के विकास के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। राजस्थान में पर्यटकों की संख्या वर्ष 1983 में जो कि 33 लाख थी वह वर्ष 1995 में बढ़कर 57.82 लाख पहुंच गयी, जिसमें 5.34 लाख विदेशी पर्यटक सम्मिलित हैं।

विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन का राज्य की अर्थव्यवस्था एवं जन जीवन दोनों पर प्रभाव पड़ता है। निश्चित अन्तराल में थोक एवं खुदरा मूल्य स्तर में परिवर्तन औद्योगिक श्रमिकों के थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से परिलक्षित होता है। राज्य में वर्ष 1996 में थोक एवं खुदरा मूल्यों में 1995 की तुलना में वृद्धि का रुख रहा। थोक मूल्य सूचकांक (आधार 1952 = 100) जो वर्ष 1995 में 1885.77 था बढ़कर वर्ष 1996 में 2038.82 हो गया है, जो 8.12 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

राज्य की आठवीं पंचवर्षीय योजना का आकार 11500 करोड़ रुपये का है, जो कि सांतवीं पंचवर्षीय योजना से 283 प्रतिशत अधिक है। यह उद्व्यय गुजरात राज्य के लगभग बराबर तथा पंजाब, उड़ीसा, मध्यप्रदेश एवं तमिलनाडु से अधिक है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति योजना उद्व्यय सातवीं योजना के 875 रुपये प्रति व्यक्ति से बढ़कर 2614 रुपये हो गया है। राजस्थान की आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति योजना उद्व्यय तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश एवं मध्यप्रदेश राज्यों से अधिक है।

आठवीं योजना के प्रथम चार वर्षों (1992-93 से 1995-96) में 8728.28 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। 1996-97 की वार्षिक योजना के लिये संभावित व्यय 3310.49 करोड़ रुपये हैं। इस प्रकार आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कुल व्यय 12000 करोड़ रु. से अधिक होने की संभावना है, जबकि योजना का आकार 11500 करोड़ रुपये था।

बैंकों द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली साख सुविधा विनियोजन एवं विकास का एक संसाधन है। नेहरू रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना एवं अनुसूचित जाति विकास निगम के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में बैंकों का सक्रिय योगदान है। बैंक शाखाओं के विस्तार विशेषत: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विस्तार से विभिन्न ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में मदद मिली है। वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में सितम्बर 1996 में एक बैंक कार्यालय 13677 व्यक्तियों को सेवायें प्रदान कर रहा था तथा 106 कि.मी. क्षेत्र में एक बैंक कार्यालय कार्यरत था।

राज्य आय एवं प्रतिव्यक्ति आय अर्थव्यवस्था की सम्पूर्ण स्थिति को दर्शाती है। राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि अधिकांशत: कृषि उत्पादन पर निर्भर करती है, क्योंकि कृषि उत्पादन राज्य घरेलू उत्पादन का सबसे बड़ा अंशदायी है, अत: राज्य आय में मानसून के उतार-चढ़ाव की स्थिति का व्यापक प्रभाव पड़ता है।

वर्ष 1991-92 से आगे के वर्षों के लिये शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय स्थिर (1980-81) व चालू मूल्यों पर निम्न तालिका में दर्शायी गयी है :-

तालिका 1.4

वर्ष	**स्थिर मूल्यों पर**		**चालू मूल्यों पर**	
	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रु.)	**प्रति व्यक्ति आय (रुपये)**	**शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रु.)**	**प्रति व्यक्ति आय (रु.)**
1991-92	7850	1761	20044	4497
1992-93	9078	1993	23944	5257
1993-94*	8329	1790	24596	5287
1994-95(प्रा)	9917	2088	30641	6452
1995-96(त्व)	9936	2051	33705	6958
1996-97 (अग्रिम)	11021	2232	39460	7992

*** सूखा वर्ष, प्रा-प्रावधानिक, त्व-त्वरित।**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो प्राय: राज्य आय के नाम से जाना जाता है, में वर्ष दर वर्ष (वर्ष 1993-94 को छोड़कर जो कि सूखा वर्ष था) निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति रही है, किन्तु राज्य में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ने शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि के अधिकतर प्रभावों को निष्फल कर दिया है। परिणामस्वरुप प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से कम रही है।

अग्रिम अनुमानों के आधार पर वर्ष 1996-97 में स्थिर (1980-81) कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 11021.40 करोड़ रुपये अनुमानित हैं, जो कि वर्ष 1995-96 में 9935.97 करोड़ रुपये था। इस प्रकार यह 10.92 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। स्थिर कीमतों पर वर्ष 1996-97 में प्रति व्यक्ति आय 2232 रुपये अनुमानित की गई, जो कि वर्ष 1995-96 में 2051 रुपये थी। इस प्रकार यह 8.83 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है।

वर्ष 1996-97 में प्रचलित कीमतों पर अग्रिम अनुमानों के आधार पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 39460.24 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है, जबकि 1995-96 में यह 33705.33 करोड़ रुपये था। यह 17.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1995-96 में 6958 रुपये थी, जिसके वर्ष 1996-97 में बढ़कर 7992 रुपये होने का अनुमान है जो कि 14.86 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती है।

राज्य में शैक्षणिक विकास हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। महिला शिक्षा पर अधिक ध्यान देने के साथ ही शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार व प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण को वर्ष 1996-97 में प्राथमिकता दी गई है। राज्य में महाविद्यालय स्तर तक बालिकाओं को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार का प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय वर्ष 1990 से महत्वपूर्ण रणनीति के रुप में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के दिशा-निर्देशों के अधीन सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम का संचालन कर रहा है।

वर्ष 1996-97 में पहली से बारहवीं कक्षा तक राजकीय विद्यालयों के नियमित विद्यार्थियों के लिये छात्र सुरक्षा बीमा योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना को लागू करने में राजस्थान देश का दूसरा राज्य है तथा राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करने वाल प्रथम राज्य है।

प्राथमिक शिक्षा को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा में समन्वय स्थापित करने हेतु राज्य में लोक जुम्बिश, शिक्षा कर्मी और गुरु मित्र योजना/परियोजनाएं चलायी जा रही हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु शिक्षित महिलाओं के द्वारा सरस्वती योजना लागू की गई है।

प्राथमिक शिक्षा के लिये बच्चों के प्रवेश में वृद्धि एवं उन्हें अध्ययनरत बनाये रखने हेतु राज्य में लड़कियों के लिये कक्षा एक से आठवीं तक तथा लड़कों के लिये कक्षा एक से पांच तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरणकी योजना लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में 58.50 लाख विद्यार्थियों को पुस्तकें वितरित की जा चुकी हैं।

सन् 2000 ई. तक "स्वास्थ्य सबके लिए कार्यक्रम" के अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य में विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप राज्य की जनता के स्वास्थ्य में सुधार आया है। जीवन प्रत्याशा (वर्ष 1995-96) लगभग 61 वर्ष हो गई है जो कि वर्ष 1961 में 46.8 वर्ष थी। जन्म दर एवं मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। राज्य में चेचक का पूर्ण उन्मूलन हो चुका है तथा अन्य महामारियों एवं छूत की बीमारियों को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है।

राज्य के ग्रामीण एवं शहरी दोनों की क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु समन्वित प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य के कुल आबाद 37889 गांवों में से 37274 गांवों को 1995-96 के अन्त तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा चुका है। वर्ष 1996-97 (दिसम्बर 1996 तक) की अवधि में 92 मुख्य हेबिटेशन, 2690 अन्य हेबिटेशन को सुरक्षित पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई गई। इसके अतिरिक्त 553 आंशिक रुप से लाभान्वित ग्रामों में पूर्ण रुप से पेयजल उपलब्ध करवाया गया।

राज्य की लगभग 77 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं। गरीबी, कुपोषण, अपर्याप्त रोजगार एवं मूलभूत सुविधाओं की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों की विशेष समस्याएं हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के द्वारा संचालित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, मरु विकास एवं सूखा संभाव्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना एवं अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं का सृजन करते हुए रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करवाकर ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी को समाप्त करने हेतु सतत् प्रयास जारी हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु अपना गांव अपना काम, तीस जिला तीस काम और द्वाकरा आदि विभिन्न कार्यक्रम भी लागू किये जा रहे हैं।

वर्ष 1996-97 में दिसम्बर 1996 के अन्त तक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 28437 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है और 2261 ग्रामीण युवाओं को ट्राईसम योजनान्तर्गत स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित किया गया।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 1996 तक 79.82 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राज्य के ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। राज्य में दिसम्बर 1996 के अन्त तक कुल 17963 उचित मूल्य की दुकानें कार्यरत थीं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत राज्य में उपभोक्ता हितों के संरक्षण हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण मंच कार्यरत है।

❖ ❖ ❖

2. राज्य घरेलू उत्पाद एवं वित्त

2.1 राज्य घरेलू उत्पाद :

राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान राज्य के आर्थिक विकास को नापने के महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकों में से एक है। प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद, अर्थव्यवस्था की स्थिति को वास्तविक एवं तुलनात्मक रुप से मापने हेतु काम में लिया जाता है। इसे क्षेत्रीय विषमताओं को मापने का भी एक महत्वपूर्ण उपकरण माना गया है। इसका उपयोग नीति निर्धारकों यथा योजना आयोग एवं वित्त आयोग द्वारा योजनाओं के संसाधनों के आवंटन एवं करों को राज्यों में वितरण के लिये किया जाता है।

वर्तमान विश्लेषण में प्रचलित एवं स्थिर (1980-81) दोनों कीमतों पर राज्य घरेलू उत्पादन के अनुमान सम्मिलित किये गये हैं। स्थिर कीमतों के राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा उत्पादन का प्रभाव प्रदर्शित होता है, जबकि प्रचलित कीमतों के अनुमान, उत्पादन व कीमतों के सम्मिलित प्रभाव को दर्शाती हैं। वर्ष 1996-97 के राज्य आय अनुमान अग्रिम एवं सम्भावित हैं जो अर्थ व्यवस्था के अनुभागों में संभावित उत्पादन, अर्थ व्यवस्था की प्रवृत्ति एवं पूर्वानुमान पर आधारित हैं। अतः इनका उपयोग पूर्ण सावधानी से किया जाना चाहिये।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद :

एक निश्चित समय में बिना ह्रास (सीएफसी) का प्रावधान किये हुए राज्य की समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है।

अर्थ व्यवस्था के वृहद् क्षेत्रों के अनुसार स्थिर कीमतों (1980-81) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 1992-93 व आगामी वर्षों के लिये निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं।

तालिका 2.1.1

स्थिर (1980-81) कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद **(करोड़ रुपये में)**

वर्ष	प्राथमिक		द्वितीयक		तृतीयक	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (3+5+6)
	कृषि (पशु पालन सहित)	योग	विनिर्माण	योग		
1	2	3	4	5	6	7
1992-93	4293.27	4692.69	1162.90	2094.23	3405.46	10192.38
	(42.12)	(46.04)	(11.41)	(20.55)	(33.41)	(100.00)
1993-94	3385.56	3826.91	1198.32	2226.43	3438.24	9491.58
	(35.67)	(40.32)	(12.62)	(23.46)	(36.22)	(100.00)
1994-95 (प्रा.)	4435.81	4956.02	1326.13	2429.73	3788.71	11174.46
	(39.70)	(44.35)	(11.87)	(21.74)	(33.91)	(100.00)
1995-96 (त्व)	4202.29	4679.39	1409.89	2610.11	3983.95	11273.95
	(37.28)	(41.51)	(12.51)	(23.15)	(35.34)	(100.00)
1996-97(अ)	4945.66	5445.79	1519.87	2789.23	4184.84	12419.86
	(39.82)	(43.85)	(12.24)	(22.46)	(33.69)	(100.00)

प्रा. - प्रावधानिक, त्व-त्वरित, अ-अग्रिम

उपरोक्त तालिका से यह विदित होता है कि वर्ष 1993-94 को छोड़कर राज्य के वास्तविक कीमतों पर ज्ञात सकल घरेलू उत्पाद में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 1993-94 सूखा ग्रस्त था जिसका कृषि के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

अग्रिम अनुमानों के आधार पर वर्ष 1996-97 में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 12419.86 करोड़ रुपये अनुमानित है जो वर्ष 1995-96 के 11273.45 करोड़ रुपये की तुलना में 10.17 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद :

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में से (सी.एफ.सी.) के मूल्य का समायोजन करने के पश्चात् शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है।

प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो कि वर्ष 1994-95 में 30641.03 करोड़ रुपये था, बढ़कर वर्ष 1995-96 में 33705.33 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार इसमें 10.00 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अग्रिम अनुमानों के आधार पर वर्ष 1996-97 में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 39460.24 करोड़ रुपये है जो पिछले वर्ष से ~~14.86~~ 17.07 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है।

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (1980-81) कीमतों पर वर्ष 1994-95 में 9916.86 करोड़ रुपये था जो बढ़कर 1995-96 में 9935.97 करोड़ हो गया। अग्रिम अनुमानों के आधार पर वर्ष 1996-97 में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 11021.40 करोड़ रुपये अनुमानित है जो पूर्व वर्ष से 10.92 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

क्षेत्रीय संरचना :

राज्य अर्थव्यवस्था के वृहद् क्षेत्रानुसार स्थिर (1980-81) कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 1992-93 से निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं

तालिका 2.1.2

स्थिर मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद **(करोड़ रु. में)**

वर्ष	प्राथमिक		द्वितीयक		तृतीयक	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (3+4+6)
	कृषि (पशु पालन सहित)	योग	विनिर्माण	योग		
1	2	3	4	5	6	7
1992-93	4027.10	4354.31	945.50	1683.97	3039.95	9078.23
	(44.36)	(47.96)	(10.42)	(18.55)	(33.49)	(100.00)
1993-94	3112.76	3472.08	970.78	1790.52	3065.98	8328.58
	(37.37)	(41.69)	(11.66)	(21.50)	(36.81)	(100.00)
1994-95 (प्रा.)	4156.21	4573.07	1075.74	1956.60	3387.19	9916.86
	(41.91)	(46.11)	(10.85)	(19.73)	(34.16)	(100.00)
1995-96 (त्व)	3915.73	4289.02	1143.74	2087.24	3559.71	9935.97
	(39.41)	(43.17)	(11.51)	(21.01)	(35.82)	(100.00)
1996-97 (अ)	4651.96	5041.62	1234.27	2249.01	3730.77	11021.40
	(42.21)	(45.74)	(11.20)	(20.41)	(33.85)	(100.00)

प्रा. - प्रावधानिक, त्व-त्वरित, अ-अग्रिम

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1993-94 को छोड़कर जो अकाल ग्रस्त था, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 1991-92 से लगातार वृद्धि की ओर अग्रसर है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की विशेषता निम्नानुसार है :-

(i) प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य एवं खनन सम्मिलित हैं जो अभी भी राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रमुखता बनाये हुए हैं। इसका राज्य घरेलू उत्पाद में 42 से 48 प्रतिशत योगदान रहता है। कृषि एवं पशुपालन अनुभाग का प्राथमिक क्षेत्र में सृजित आय का 90 प्रतिशत योगदान है।

(ii) द्वितीय क्षेत्र जिसमें विनिर्माण, विद्युत, गैस व जल आपूर्ति एवं निर्माण अनुभाग सम्मिलित हैं, का राज्य घरेलू उत्पाद में 19 से 21 प्रतिशत के बीच में योगदान रहता है।

(iii) तृतीय क्षेत्र जिसमें यातायात, संचार, व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, बैंक एवं बीमा, स्थावर सम्पदा, आवासीय स्वामित्व, व्यावसायिक सेवायें, सार्वजनिक सेवायें तथा अन्य सेवायें सम्मिलित हैं, का राज्य घरेलू उत्पाद में 33 से 37 प्रतिशत के बीच योगदान रहता है।

प्रति व्यक्ति आय :

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में जनसंख्या का भाग देकर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है।

प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय जो वर्ष 1995-96 में 6958 रुपये थी, अग्रिम अनुमान के आधार पर वर्ष 1996-97 में 7992 रुपये अनुमानित की गई हैं जो पिछले वर्ष से 14.86 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती है।

स्थिर (1980-81) कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय जो वर्ष 1995-96 में 2051 थीं, बढ़कर वर्ष 1996-97 में 2232 रुपये हो गई, जो 8.83 प्रतिशत वृद्धि दर्शाती है।

2.2 आठवीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना 1996-97

आठवीं पंचवर्षीय योजना में 11500 करोड़ रुपये के कुल आवंटन के विरुद्ध योजना के प्रथम चार वर्षों (1992-93 से 1995-96) में 8728.28 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है तथा योजना के वर्ष 1996-97 मे संभावित व्यय 3310.49 करोड़ रूपये हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 1992-93 से 1995-96 तक व्यय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2.1

योजना उद्व्यय एवं व्यय

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	**क्षेत्र**	**आठवीं योजना का उद्व्यय (1992-97)**	**व्यय**			
			1992-93	**1993-94**	**1994-95**	**1995-96**
1	2	3	4	5	6	7
1.	कृषि एवं संबंद्ध सेवायें	1286.92 (11.19)	128.24 (9.12)	161.00 (9.23)	240.21 (9.94)	306.75 (9.70)
2.	ग्रामीण विकास	1021.75 (8.88)	100.80 (7.17)	116.67 (6.69)	180.54 (7.47)	242.00 (7.65)
3.	विशिष्ठ क्षेत्रीय योजना	84.00 (0.73)	1.10 (0.08)	1.52 (0.09)	3.45 (0.14)	4.54 (0.14)

1 2	3	4	5	6	7
4. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1919.99 (16.70)	263.00 (18.70)	288.34 (16.54)	381.13 (15.78)	441.18 (13.95)
5. उर्जा	3255.49 (28.31)	395.60 (28.12)	499.60 (28.66)	651.39 (26.97)	816.77 (25.83)
6. उद्योग एवं खनिज	536.02 (4.66)	82.15 (5.84)	88.12 (5.05)	127.64 (5.28)	161.78 (5.12)
7. यातायात	783.97 (6.82)	80.39 (5.71)	142.60 (8.18)	178.62 (7.40)	254.84 (8.06)
8. वैज्ञानिक सेवायें एवं अनुसंधान	19.96 (0.17)	2.93 (0.21)	3.31 (0.19)	3.91 (0.16)	3.54 (0.11)
9. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें	2461.62 (21.41)	330.89 (23.52)	412.81 (23.68)	206.51 (25.11)	867.54 (27.43)
10. आर्थिक सेवायें	71.72 (0.62)	8.87 (0.63)	11.54 (0.66)	17.72 (0.73)	20.93 (0.66)
11. सामान्य सेवायें	58.56 (0.51)	12.70 (0.90)	17.93 (1.03)	24.63 (1.02)	42.55 (1.35)
योग	**11500.00 (100.00)**	**1406.67 (100.00)**	**1743.44 (100.00)**	**2415.75 (100.00)**	**3162.42 (100.00)**

प्राथमिक न्यूनतम सेवाओं के प्रावधान को सम्मिलित करते हुए वर्ष 1996-97 का वार्षिक योजना व्यय 3310.49 करोड़ रु. है। इस प्रकार पंचवर्षीय योजना अवधि में 11500 करोड़ रु. के प्रावधान के विरुद्ध कुल व्यय 12000 करोड़ रु. से अधिक होगा।

2.3 बैंकिंग :

तीव्र आर्थिक विकास के फलस्वरूप अधिकांश जनसाधारण के जीवन स्तर में सुधार आया है लेकिन फिर भी गरीबी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसकी ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों ने विकास की गति को प्रभावित किया है। राज्य के सीमित संसाधनों से जनता की बढ़ती हुई आकांक्षाओं को पूरा करना कठिन है। अत: समग्र विकास हेतु संस्थागत वित्त एवं ऋण आदि अन्य उपाय भी नितान्त आवश्यक हैं।

राज्य सरकार योजनाबद्ध विकास के माध्यम से ढांचागत विकास एवं मानव संसाधन के विकास हेतु प्रयत्नशील है, फिर भी राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर की औसत प्रति व्यक्ति आय में अन्तर बना हुआ है। अत: राज्य में विकास को गति प्रदान करने के लिये अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों एवं व्यक्तियों की आय बढ़ाने हेतु संसाधन जुटाने में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

बैंकों द्वारा ऋण वितरण राज्य के विकास एंव विनियोजन के लिये एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत है। एन.आर.वाई, पी.एम.आर.वाई., आई.आर.डी.पी., एस.यू.एम. योजना, एस.सी./एस.टी. विकास एवं अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बैंकों की सहायता से राज्य में चलाये जा रहे हैं। विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बैंक शाखाओं के विस्तार से गरीबी की रेखा से नीचे जीवन

यापन करने वाले वर्गों के उत्थान के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहायता मिली है। बैंक शाखाओं की जमा राशि एवं ऋण वितरण की तुलनात्मक स्थिति राज्य एवं भारतीय स्तर पर माह सितम्बर, 96 तक निम्न तालिका में दर्शाई गई है।

तालिका 2.3.1

(सितम्बर तक)

क्र.सं.	मद	राजस्थान		भारत	
		1995	1996	1995	1996
1.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक				
	(अ) कार्यालयों की संख्या	1069	1070	14528	14508
	(ब) जमा (करोड़ रु.)	727	908	11542	18055
	(स) ऋण (करोड़ रु.)	302	355	6565	8967
2.	अन्य अनुसूचित व्यापारिक बैंक				
	(अ) कार्यालयों की संख्या	2114	2147	48095	48689
	(ब) जमा (करोड़ रु.)	10387	12129	380269	439659
	(स) ऋण (करोड़ रु.)	4653	5295	228700	254189
3.	योग				
	(अ) कार्यालयों की संख्या	3183	3217	62623	63197
	(ब) जमा (करोड़ रु.)	11114	13037	391811	457714
	(स) ऋण (करोड़ रु.)	4955	5650	235265	263156

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सितम्बर, 96 में सितम्बर, 95 की तुलना में बैंक जमा राशि व ऋण दोनों में वृद्धि हुई है। राजस्थान में जमा राशि में वर्ष 1995 की तुलना में वर्ष 1996 में 17.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 16.82 प्रतिशत रही। राजस्थान में ऋण का जमा राशि से अनुपात सितम्बर, 1996 में 43.34 प्रतिशत रहा, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात 57.49 प्रतिशत था। सितम्बर, 95 में यह अनुपात राजस्थान व राष्ट्रीय स्तर पर क्रमश: 44.50 व 60.04 प्रतिशत था। राजस्थान में वर्ष 1995 की तुलना में वर्ष 1996 में कुल ऋण 14.02 प्रतिशत बढ़ा जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 11.85 प्रतिशत रही।

वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर सितम्बर 1996 में एक बैंक कार्यालय औसतन 13677 व्यक्तियों को सेवायें प्रदान कर रहा था तथा 106 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक बैंक कार्यालय स्थापित था।

❖ ❖ ❖

3. मूल्य स्थिति एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली

विकास कार्यों के लाभों का उचित वितरण एवं विकास की गति को सुनिश्चित करने के लिये मूल्यों में स्थिरता आवश्यक है। मुद्रा स्फीति गरीबों को अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि उनकी आय, मूल्यों के अनुरूप नहीं बढ़ पाती है। अर्थ व्यवस्था पर मुद्रा स्फीति का दबाव थोक मूल्य एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से प्रदर्शित होता है।

3.1 थोक भाव सूचकांक (आधार वर्ष 1952-53 = 100)

वर्ष 1996 में राजस्थान का सामान्य थोक भाव मूल्य सूचकांक 2038.82 रहा, जो वर्ष 1995 के सूचकांक 1885.77 से 8.12 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 1996 में थोक भाव सूचकांक के "ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक वर्ग" में सर्वाधिक वृद्धि 22.38 प्रतिशत रही। इसके पश्चात् "खाद्य पदार्थ वर्ग" में 7.90 प्रतिशत, "विनिर्मित पदार्थ वर्ग" में 6.02 प्रतिशत एवं औद्योगिक कच्चे माल वर्ग में 4.32 प्रतिशत वृद्धि रही।

माह जनवरी व दिसम्बर 96 के अतिरिक्त शेष पूरे वर्ष 1996 में थोक भाव सूचकांक में वृद्धि का रुख रहा। इन दोनों महीनों में पिछले महीनों से क्रमशः 2.12 व, 1.10 प्रतिशत की कमी रही है। वर्ष 1996 तथा 1995 में प्रमुख वर्गों के थोक भाव सूचकांक में पिछले वर्षों से प्रतिशत विचलन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1.1

थोक भाव सूचकांक (आधार वर्ष 1952-53=100)

क्र.सं.	वृहद् वर्ग	वार्षिक औसत			पिछले वर्ष से प्रतिशत विचलन	
		1994	1995	1996	1995	1996
1.	खाद्य पदार्थ वर्ग	1771.80	1803.71	1946.26	1.80	7.90
2.	औद्योगिक कच्चा माल वर्ग	1660.80	1888.73	1970.26	13.72	4.32
3.	ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक वर्ग	3160.91	3314.23	4055.94	4.85	22.38
4.	विनिर्मित पदार्थ वर्ग	1889.93	1979.56	2098.64	4.74	6.02
5.	सामान्य सूचकांक	1827.61	1885.77	2038.82	3.18	8.12

3.2 औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1982=100)

औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा तैयार किये जाते हैं जिसमें राज्य के जयपुर एवं अजमेर केन्द्र सम्मिलित हैं। वर्ष 1996 में खुदरा मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति पूरे वर्ष निरन्तर बनी रही।

वर्ष 1996 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 1995 की तुलना में, जयपुर केन्द्र पर 10.31 प्रतिशत और अजमेर केन्द्र पर 8.85 प्रतिशत की दर से बढ़ा। वृद्धि की यह दर वर्ष 1995 में पिछले वर्ष की तुलना में जयपुर केन्द्र के लिये 8.18 प्रतिशत वृद्धि से अधिक है जबकि अजमेर केन्द्र के लिये सूचकांक में पिछले वर्ष की तुलना में कमी रही।

जयपुर एवं अजमेर केन्द्र के पिछले तीन वर्षों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्गानुसार तालिका में प्रदर्शित किये गये हैं :-

तालिका 3.2.1

औद्योगिक श्रमिकों के लिये वर्गानुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

जयपुर केन्द्र **(आधार वर्ष 1982=100)**

वर्ग	सूचकांक			प्रतिशत विचलन	
	1994	**1995**	**1996**	**1996 का 1995 से**	**1995 का 1994 से**
1	2	3	4	5	6
1. खाद्य	295	323	355	9.91	9.49
2. पान, सुपारी, तम्बाकु एवं मादक पदार्थ	356	365	378	3.56	2.53
3. ईंधन, शक्ति एवं प्रकाश	219	228	268	17.54	4.11
4. आवास	154	159	158	(-) 0.63	3.25
5. वस्त्र, बिस्तर तथा जूते	210	236	283	19.91	12.38
6. विविध	297	320	354	10.62	7.74
7. सामान्य	269	291	321	10.31	8.18

अजमेर केन्द्र

वर्ग	सूचकांक			प्रतिशत विचलन	
	1994	**1995**	**1996**	**1996 का 1995 से**	**1995 का 1994 से**
1	2	3	4	5	6
1. खाद्य	287	318	344	8.18	10.80
2. पान, सुपारी, तम्बाकु एवं मादक पदार्थ	337	347	360	3.75	2.97
3. ईंधन, शक्ति एवं प्रकाश	239	238	248	4.20	(-) 0.42
4. आवास	314	318	382	20.13	1.27
5. वस्त्र, बिस्तर तथा जूते	248	274	296	8.03	10.48
6. विविध	255	281	304	8.18	10.20
7. सामान्य	280	305	332	8.85	8.93

उक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1996 के दौरान जयपुर व अजमेर केन्द्रों के सभी वर्गों के सूचकांक में वृद्धि हुई है। केवल जयपुर केन्द्र में आवास वर्ग में कमी हुई है।

जयपुर, अजमेर एवं अखिल भारतीय स्तर के पिछले पांच वर्षों के औसत सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982=100) निम्नलिखित तालिका में दर्शाये गये हैं :-

तालिका 3.2.2

औद्योगिक श्रमिकों के लिये सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1982=100)

वर्ष	जयपुर केन्द्र		अजमेर केन्द्र		अखिल भारतीय	
	सूचकांक	प्रतिशत विचलन गत वर्ष की तुलना में	सूचकांक	प्रतिशत विचलन गत वर्ष की तुलना में	सूचकांक	प्रतिशत विचलन गत वर्ष की तुलना में
1992	228	8.57	243	11.98	237	11.79
1993	245	7.46	253	4.11	252	6.33
1994	269	9.80	280	10.67	278	10.32
1995	291	8.18	305	8.93	306	10.07
1996	321	10.31	332	8.85	334	9.15

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि सर्वाधिक वृद्धि दर वर्ष 1996 में जयपुर केन्द्र (10.31 प्रतिशत) उसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर (9.15 प्रतिशत) व अजमेर केन्द्र (8.85 प्रतिशत) रहीं।

3.3 सार्वजनिक वितरण प्रणाली :

सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर आवश्यक वस्तुयें निश्चित मात्रा में उपलब्ध करवाने हेतु राज्य में उचित मूल्यों की दुकानों के तंत्र द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किया जा रहा है। माह दिसम्बर, 1996 के अन्त तक राज्य में कुल 17963 उचित मूल्य की दुकानें कार्य कर रही थीं इनमें से 13517 ग्रामीण क्षेत्रों में थी। इन दुकानों के माध्यम से माह अप्रेल से दिसम्बर, 1996 तक की अवधि में 7.80 लाख मै.टन गेहूं, 0.13 लाख मै. टन चावल, 1.80 लाख मै. टन चीनी एवं 3.33 लाख किलो लीटर केरोसीन तेल वितरित किया गया। माह जनवरी 1992 से राज्य के जनजातीय, मरुस्थलीय एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियान्वित हैं। 22 जिलों के 122 चयनित खण्डों में आर.पी.डी.एस. सार्वजनिक वितरण प्रणाली समावेशित हैं जिनमें गेहूं और चावल 60 रु. प्रति क्विंटल अनुदानित मूल्यों पर वितरित किया जाता है।

❖ ❖ ❖

4. उद्योग एवं खनिज

4.1 उद्योग :

नई औद्योगिक नीति वर्ष 1994 जिसका उद्देश्य, त्वरित औद्योगिकरण है, के तहत उद्योग विभाग, राजस्थान औद्योगिक एवं विनियोजन निगम (रीको) राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम, राज्य वित्त निगम, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, औद्योगिक संवर्द्धन ब्यूरो आदि के समन्वित प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में स्वस्थ औद्योगिक वातावरण सृजित हुआ है। इस औद्योगिक नीति के फलस्वरूप विनियोजन में वृद्धि के साथ उच्च तकनीकी एवं आधुनिक तकनीकी आधारित गैर परम्परागत उद्योगों की स्थापना निरंतर रुप से बढ़ रही है।

राज्य का उद्योग विभाग, लघु औद्योगिक एवं हस्तशिल्प इकाईयों के त्वरित विकास हेतु प्रयत्नशील है। वित्तीय वर्ष 1996-97 में (दिसम्बर, 96 तक) 5221 लघु औद्योगिक इकाईयों का पंजीयन किया गया एवं इन ईकाईयों में 162.10 करोड़ रूपये का विनियोजन हुआ तथा 21784 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। हस्तकर्घा विकास की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 257 करधा घर स्वीकृत किये गये तथा हैल्थ पैकेज योजना के तहत बुनकरों को लाभान्वित किया गया।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत बेरोजगार युवकों को अपने स्वयं का उद्योग, सेवा एवं व्यापार स्थापित करने हेतु एक लाख रुपये तक का ऋण/अनुदान दिया जाता है। चालू वर्ष में माह दिसम्बर, 96 तक इस योजना में 5884 प्रकरणों में ऋण स्वीकृत किया गया तथा इसमें 3922 को प्रशिक्षण दिया गया तथा प्रशिक्षण के पश्चात् 864 युवकों को ऋण वितरित किया गया।

गृह उद्योग योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में माह दिसम्बर, 96 तक 34 स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से 24 जिलों में शहरी क्षेत्र की 3310 गरीब महिलाओं को कशीदाकारी, बुनाई, दरी-पट्टी, आरी-तारी एवं सिलाई आदि के कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया।

राज्य में औद्योगिक उत्पादों के विपणन में सहायता हेतु "उद्यम प्रोत्साहन संस्थान (यू.पी.एस.)" का गठन किया गया। यू.पी.एस. का उद्देश्य राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक प्रदर्शनियां आयोजित करना है। यू.पी.एस. ने प्रदर्शनियों के आयोजन के अलावा दिनांक 3.9.96 को आर्टिजन डवलपमेन्ट सोसायटी, अलवर के साथ हस्त-औजार क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया है।

उद्योग निदेशालय में एक निर्यात प्रोत्साहन प्रकोष्ठ कार्यरत है जो अन्य गतिविधियों के साथ निर्यातकों के लिए निर्यात निर्देशिका प्रकाशित करता है। वर्ष 1996-97 में निर्यातकों को पुरस्कृत करने हेतु 3.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। गत वर्ष निर्यात प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 22 उत्तम निर्यातकों को पुरस्कृत किया गया।

राज्य में माह दिसम्बर, 96 तक 213 औद्योगिक क्षेत्रों में राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको) द्वारा आवश्यक आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन क्षेत्रों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। वर्ष 1996-97 में 1175 औद्योगिक भूखण्डों को विकसित किया गया है तथा माह दिसम्बर, 96 तक 456 भूखण्डों का आवंटन किया गया है। रीको द्वारा वृहद् तथा मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 1996-97 में माह दिसम्बर तक 58.08 करोड़ रूपये के सावधि ऋण स्वीकृत किये गये तथा 35.24 करोड़ रुपये वितरित किये गये।

वर्ष 1996-97 में माह दिसम्बर, 96 तक केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत चार औद्योगिक विकास केन्द्रों (ग्रोथ सेन्टर्स) यथा बीकानेर, धौलपुर, झालावाड़ एवं आबूरोड़ पर 22.92 करोड़ रुपये खर्च किये गये। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा जोधपुर में एक लघु विकास केन्द्र स्वीकृत किया गया तथा माह दिसम्बर, 96 तक इसके क्रियान्वयन पर 1.57 करोड़ रूपये खर्च किये गये। इस वर्ष जयपुर जिले में एक्पोर्ट प्रमोशन इण्डस्ट्रीयल पार्क (ई.पी.आई.पी.), इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर टैक्नोलोजी पार्क एवं सोफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्क के विकास का काम हाथ में लिया गया है। इसके अलावा गांव मानुपर माचेड़ी (जिला जयपुर) में एक लैदर कॉम्पलेक्स का कार्य भी प्रगति पर है।

राजस्थान लघु उद्योग निगम (राजसीको) लघु उद्योगों तथा शिल्पकारों को उचित कीमत पर कच्चा माल एवं उनके उत्पादों के विपणन के लिये सुविधाओं की सहायतार्थ कार्यरत है। राजस्थान के हस्तशिल्प को लोकप्रिय बनाने एवं उनके विपणन हेतु अनेक एम्पोरियम कार्यरत हैं। हस्तशिल्प के विकास हेतु निगम द्वारा प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। वर्ष 1996-97 में माह दिसम्बर 96 तक 5.18 करोड़ रुपये के हस्तशिल्प सामान की बिक्री की गई। माह नवम्बर 96 तक सांगानेर व जोधपुर में इनलैण्ड कन्टेनर डिपो तथा सांगानेर में एयर कारगो कॉम्पलेक्स द्वारा 596 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया।

राजस्थान वित्त निगम :

राजस्थान वित्त निगम मुख्यरूप से राज्य में उद्योगों की स्थापना, विस्तार एवं नवीनीकरण हेतु सावधि ऋण उपलब्ध कराता है। निगम ने राज्य में उद्योगों की स्थापना हेतु 2.40 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये हैं। उदारीकरण एवं सरलीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप निगम ने वर्ष 1995-96 के दौरान 163.44 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये तथा 131.66 करोड़ रुपये वितरित किये। चालू वर्ष में माह नवम्बर 96 तक 66.68 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये हैं तथा 72.28 करोड़ रुपये वितरित किये जा चुके हैं। राजस्थान वित्त निगम, राज्य विनियोजन अनुदान और ब्याज रहित ऋण योजनाओं को क्रियान्वित करने में राज्य के अभिकर्ता के रुप में कार्य कर रहा है। चालू वर्ष में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को सामान्य से 2 प्रतिशत कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा छोटे उद्यमियों को राहत प्रदान करने के लिए अप्रेल 1996 से 2 लाख रु. तक के ऋण की नियमित अदायगी न करने पर दण्डित ब्याज वसूल नहीं किया जा रहा है।

ऋण की वसूली को गतिशील बनाने के लिए वर्ष 1996-97 में यह महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया गया कि बकाया ऋण राशि का निपटारा करवाने पर रियायत दी जावे। इसके फलस्वरूप माह नवम्बर, 96 तक 90.52 करोड़ रुपये की वसूली हुई है जो कि निर्धारित लक्ष्य का 46.42 प्रतिशत है तथा गत वर्ष इस अवधि में जो वसूली हुई थी उससे 5.35 प्रतिशत अधिक है।

वित्त निगम ने हाल ही में एक स्वर्ण कार्ड (गोल्ड कार्ड) योजना शुरु की है जिसके तहत नियमित ऋण अदायगी कर्ताओं को कार्यशील पूंजी तथा अतिरिक्त परिसम्पत्ति हेतु 30 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। लघु उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी। वर्ष 1995-96 में राजस्थान वित्त निगम द्वारा स्वीकृत किये गये ऋणों में से लघु उद्योगों को 89.79 प्रतिशत ऋण दिया गया। वर्ष 1996-97 में भी इस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गयी, जो कि निम्न तालिका से प्रदर्शित होता है।

तालिका 4.1.1

(रुपये करोड़ों में)

उद्यम का प्रकार	1995-96		1996-97 (माह नवम्बर 96)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1. लघु ट्रांसपोर्ट	105	3.71	40	1.35
2. लघु औद्योगिक इकाई	1643	146.76	555	60.29
3. अन्य	22	12.97	7	5.04

औद्योगिक उत्पादन

राज्य में चयनित महत्वपूर्ण वस्तुओं के वर्ष 1995 एवं 1996 के उत्पादन की तुलनात्मक स्थिति निम्नांकित सारणी में दर्शाई गई है।

चयनित मदों का औद्योगिक उत्पादन

तालिका 4.1.2

क्र.सं.	मद	इकाई	उत्पादन 1995	उत्पादन 1996 वर्ष (प्रावधानिक)	1995 की तुलना में 1996 में प्रतिशत वृद्धि/कमी
1		2	3	4	5 6
1.	शक्कर	टन	24717	30987	25.37
2.	स्प्रिट (सभी प्रकार)	000 लीटर	17600	21406	21.62
3.	वनस्पति घी	टन	28402	30133	6.09
4.	नमक	लाख टन	15	11	(-) 26.67
5.	यूरिया	''000 टन	392	388	(-) 1.02
6.	सुपर फास्फेट	''000 टन	36	35	(-) 2.78
7.	सीमेन्ट	''000 टन	6469	6596	1.96
8.	अभ्रक की ईटें	''000 संख्या	1265	1051	(-) 16.92
9.	जस्ते की छड़ें	''000 टन	91	94	3.30
10.	कैडिमियम अंतिम उत्पादन	टन	156	161	3.20
11.	रेल्वे बैगन	संख्या	590	1107	87.63
12.	बाल बियरिंग लाख	संख्या	216	231	6.94
13.	पानी के मीटर	संख्या	40704	41326	1.53
14.	रेडियेटर्स	संख्या	2912	4234	48.83
15.	लेपित एवं पुन: लेपित पत्थर	''000 वर्ग-मीटर	212	242	14.15
16.	बिजली के मीटर	संख्या	732513	711238	(-) 2.90
17.	नायलोन धागा	टन	3998	3628	(-) 9.25
18.	पोलियेस्टर धागा	टन	14590	11462	(-) 21.44
19.	कॉस्टिक सोड़ा	टन	33711	39566	17.37
20.	कैलशियम कार्बाइड	टन	50073	44358	(-) 11.41
21.	पी.वी.सी. रेजिन	टन	31789	31231	(-) 1.76
22.	पी.वी.सी. कम्पाउण्ड	टन	5282	5279	(-) 0.06
23.	सल्फ्यूरिक एसिड	''000 टन	240	206	(-) 14.17
24.	कॉपर ''कैथोड्स''	टन	30513	21630	(-) 29.11
25.	सूती कपड़ा	लाख मीटर	411	457	11.19
26.	सूती धागा	''000 टन	54	57	5.56

उपरोक्त सारणी से प्रकट होता है कि गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1996 में चयनित वस्तुओं के उत्पादन में मिश्रित प्रवृत्ति रही। वर्ष 1996 में 26 चयनित मदों में से 14 मदों के उत्पादन में वृद्धि दृष्टिगत हुई है जबकि 12 मदों के उत्पादन में कमी रही। इन मदों के उत्पादन में विचलन की सीमा इस प्रकार है।

तालिका 4.1.3

वर्ष 1996 में गत वर्ष से विचलन	मद
1.1 10 प्रतिशत तक वृद्धि	वनस्पति घी, जस्ते की छड़ें, कैडिमियम (अंतिम उत्पादन) पानी के मीटर, बाल बियरिंग, सूती धागा।
1.2 10 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि	लेपित एवं पुनः लेपित पत्थर, कॉस्टिक सोड, सूती कपड़ा।
1.3 20 से 50 प्रतिशत तक वृद्धि	शक्कर, स्प्रिट (सभी प्रकार), रेडियेटर्स।
1.4 50 से 100 प्रतिशत तक वृद्धि	रेल्व वैगन।
1.5 100 प्रतिशत से अधिक वृद्धि	शून्य
2.1 10 प्रतिशत तक कमी	यूरिया, सुपर फास्फेट, बिजली के मीटर, नायलोन धागा, पी.वी.सी. रेजिन, पी.वी.सी. कम्पाउण्ड।
2.2 10 से 20 प्रतिशत तक कमी	अभ्रक की ईटे, कैल्शियम कारबाईड, सल्फ्यूरिक एसिड
2.3 20 से 50 प्रतिशत तक कमी	नमक, पोलिस्टर धागा, कॉपर केथोड्स
2.4 50 से 100 प्रतिशत तक कमी	शून्य

4.2 खादी एवं ग्रामोद्योग :-

खादी एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से पूर्णकालीन एवं अंशकालीन रोजगार उपलब्ध करवाकर ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा रहा है। वर्ष 1995-96 में 3713 औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई तथा चालू वित्तीय वर्ष में माह नवम्बर, 96 तक 1458 ईकाईयों को सहायता उपलब्ध करवाई गई है।

वर्ष 1995-96 के दौरान खादी उद्योगों में 39.41 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ जो वित्तीय वर्ष के अंत तक बढ़कर 50 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसी प्रकार ग्रामोद्योग का उत्पादन वर्ष 1995-96 में 260.48 करोड़ रुपये कीमत का था जो वर्ष 1996-97 तक बढ़कर 278.00 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है। वर्ष 1996-97 में 33,000 व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जायेंगे जबकि 1995-96 में 30732 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया था। परम्परागत चर्खों के स्थान पर अम्बर चर्खों का उपयोग करते हुए ऊनी तथा सूती खादी की गुणवत्ता में सुधार तथा उत्पादन में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं।

उद्यमियों को एक ही स्थान पर सुविधायें प्रदान करने के लिए औद्योगिक संवर्धन ब्यूरो (बी.आई.पी.) प्रयत्नशील है। औद्योगिक संवर्धन ब्यूरो (बी.आई.पी.) निवेशकों को राजस्थान में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित करने में प्रयासरत है। इसके लिए विभिन्न वृहद् एवं मध्यम कम्पनियों/औद्योगिक समूहों से सम्पर्क स्थापित किया गया।

4.3 कारखाना एवं बायलर्स :-

मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स, पंजीकृत निर्माणियों एवं बायलर्स के लिये राज्य के लिये राज्य का प्राधिकृत अधिकारी है। मुख्य रुप से यह विभाग कारखाना अधिनियम 1948, भारतीय बायलर्स अधिनियम 1923 एवं वेतन भुगतान अधिनियम 1936 को लागू करने के लिये, औद्योगिक कामगारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण को सुनिश्चित करने के लिये है।

चालू वर्ष में माह दिसम्बर, 96 तक 279 नई निर्माणियों का पंजीयन किया गया तथा 7246 श्रमिकों को रोजगार मिला है। विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र में सुपरवाईजरों एवं श्रमिकों के लिए 26 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। इन कार्यक्रमों से 359 श्रमिक एवं सुपरवाईजरों को लाभान्वित किया गया। औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला द्वारा विभिन्न रासायनिक कारखानों में से हानिकारक रसायनों के 161 नमूने एकत्रित किये गये।

विभाग के कार्यों को गति प्रदान करने के लिए कारखानों के नक्शों के अनुमोदन एवं लाईसेन्स नवीनीकरण के अधिकार उप मुख्य निरीक्षकों कारखाना एवं बायलर्स को विकेन्द्रित किये गये हैं। आंकड़ों के संधारण हेतु कम्प्यूटर लगाये गये हैं।

4.4 खनिज :

राज्य खान एवं भू-विज्ञान विभाग नई खनिज नीति 1994 के मुख्य उद्देश्यों की प्राप्त हेतु सघन प्रयास कर रहा है तथा खनिज भण्डारों की खोज हेतु राज्य के विभिन्न भागों में सर्वेक्षण कार्य कर रहा है वर्ष 1996-97 में खनिज सर्वेक्षण एवं प्रोस्पेक्टिंग योजना के अन्तर्गत 76 परियोजनाओं का कार्य हाथ में लिया गया है।

माह दिसम्बर, 96 तक निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धियां निम्न तालिका में दर्शाये गयी हैं :-

तालिका 4.1.4

कार्य		इकाई	लक्ष्य 1996-97	उपलब्धि (दिसम्बर, 96 तक)	प्रतिशत उपलब्धि
1.	आर.एम.एस.	वर्ग कि.मी.	5200	3778	72.65
2.	आर.जी.एम.	वर्ग कि.मी.	490	328	66.93
3.	डी.जी.एम.	वर्ग कि.मी.	20	12.35	61.75
4.	डेलीनिएशन	वर्ग कि.मी.	31.50	23.60	74.92
5.	ड्रीलिंग	मीटर	16750	7100.05	42.38

इमारती व सजावटी पत्थरों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए मार्बल व ग्रेनाईट के भण्डारों की खोज एवं सीमांकन पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके फलस्वरूप ग्रेनाईट के 43 प्लॉट्स तथा मार्बल के 11 प्लॉट्स विभिन्न जिलों में सीमांकित किये गये तथा आवंटन हेतु अधिसूचना भी जारी की गई। जयपुर जिले के आंधी क्षेत्र तथा चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू तहसील में मार्बल भण्डारों की खोज का कार्य प्रगति पर है।

एस.एम.एस. ग्रेड लाईम स्टोन की खोज हेतु चालू वर्ष में छिद्रण कार्य जैसलमेर जिले में किया जा रहा है, तथा वहां पर लगभग 10 मिलियन टन एस.एम.एस. ग्रेड एवं 170 मिलियन टन सीमेन्ट ग्रेड, लाईम स्टोन के भण्डार होने का अनुमान है। इसी तरह नागौर जिले में टाकला एवं डेहरू क्षेत्र में लाईम स्टोन के भण्डार पाये गये हैं तथा इसका 15.50 मै. टन भण्डार होने का अनुमान है।

अन्य औद्योगिक खनिजों की खोज के दौरान भरतपुर जिले की कामां तहसील में अच्छी किस्म का क्वार्टजाइट खनिज भी पाया गया है। नागौर एवं बीकानेर जिलों में लिग्नाईट की खोज का कार्य लगातार जारी है एवं इसके छिद्रण का कार्य प्रगति पर है। बीकानेर जिले के हाडला क्षेत्र में 15 से 16 मीटर मोटाई की लिग्नाईट पट्टी को विभक्त किया गया है। बांसवाड़ा जिले के सादड़ी-उदयवाला-खेमरा क्षेत्र में सोने की खोज का कार्य प्रगति पर है तथा उत्साहवर्धक परिणाम पाये गये हैं तथा एक से आठ ग्राम सोना प्रति टन रॉक पर 172.30 मीटर से 182.30 मीटर तक की गहराई पर पाया गया है।

राजस्थान राज्य खनिज निगम स्वयं अथवा संयुक्त क्षेत्र के खनिज आधारित उद्योगों, परियोजनाओं एवं उपक्रमों को प्रोन्नत करने, उनका विकास करने एवं संचालित करने में कार्यरत है। निगम खनन कार्य के अतिरिक्त खानों के विकास एवं खनिज आधारित उद्योग स्थापित करने हेतु परामर्श भी देता है। निगम राज्य के 13 जिलों में विभिन्न स्थानों पर खानों का व्यावसायिक आधार पर संचालन कर रहा है।

निगम राज्य में उद्यमियों को उनकी कम्पनी के प्रबन्ध में तथा अंश पूंजी में योगदान करता है तथा उनके उपयोग के लिए खनिज क्षेत्रों के आवंटन का कार्य भी करता है। निगम ने संयुक्त/सहयोगी क्षेत्र की कम्पनियों की अंश पूंजी में 92.15 लाख रुपयों का विनियोजन किया है। वर्ष 1996-97 में स्टील प्लान्टों की बढ़ती हुए मांग की पूर्ति हेतु लाइम स्टोन के उत्पादन का लक्ष्य 17.95 लाख मैट्रिक टन रखा गया है।

वर्ष 1995-96 के दौरान निगम ने रायल्टी के भुगतान, भूमि कर, बिक्री कर एवं जैसलमेर, बांसवाड़ा और कोटपूतली में लाइमस्टोन की गतिविधियों से हुए लाभ में से हिस्सा देकर और जिप्सम पर लेवी के भुगतान के रुप में कुल 13.42 करोड़ रुपयों का राज्य के राजस्व में योगदान दिया है।

4.5 श्रम :

औद्योगिक संबंध :- राज्य का श्रम विभाग, औद्योगिक शांति तथा श्रमिकों के कल्याण हेतु विभिन्न श्रम कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु कटिबद्ध है। विभाग श्रमिकों की समस्याओं के समाधान हेतु स्पष्ट, तर्कसंगत तथा निश्चित दृष्टिकोण अपनाकर विभिन्न श्रम कानूनों को सतर्कता से लागू कर औद्योगिक शांति बनाये रखने में प्रयत्नशील रहा है।

हड़तालों एवं तालाबन्दी की रोकथाम के लिए प्रयास किये गये। माह दिसम्बर, 96 तक 7054 शिकायतों में से 4163 शिकायतों का निस्तारण किया गया। वर्ष 1996-97 के दौरान माह दिसम्बर, 96 तक राज्य में 32 हड़ताले एवं तालाबन्दी हुई जिससे 19548 श्रमिक प्रभावित हुए तथा 4.66 लाख मानव दिवसों का नुकसान हुआ जबकि वर्ष 1995-96 में 51 हड़तालें एवं तालाबन्दी की घटनायें हुई जिसमें 26950 श्रमिक प्रभावित हुए थे तथा 5.02 लाख मानव दिवसों का नुकसान हुआ था।

वर्ष 1996-97 के आरम्भ में राज्य में 3110 पंजीकृत श्रमिक संगठन थे, जिनके सदस्यों की संख्या 5022 लाख थीं। अक्टूबर, 96 तक 71 नये श्रमिक संगठनों का पंजीकरण हुआ जिनके सदस्यों की संख्या 0.09 लाख है।

4.6 रोजगार :

रोजगार अवसरों का सृजन नियोजित विकास का एक मुख्य उद्देश्य है इसलिये रोजगार के अवसरों एवं विभिन्न वर्गों के बेरोजगारों की सूचना रखना आवश्यक है। राजस्थान में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में अनुमानित रोजगार की स्थिति निम्न तालिका में दी गई है :-

तालिका संख्या 4.6.1

(संख्या लाखों में)

वर्ष	**राजस्थान**		
	सार्वजनिक क्षेत्र	**निजी क्षेत्र**	**योग**
1	2	3	4
1992	9.73	2.31	12.04
1993	9.77	2.32	12.09
1994	10.05	2.43	12.48
1995	10.09	2.55	12.64
1996 (जून 96 तक)	10.10	2.56	12.66

जनवरी से दिसम्बर 1996 तक की अवधि में विभिन्न रोजगार कार्यालयों में 2,94,164 बेरोजगार व्यक्ति पंजीकृत थे जिनमें 40629 अनूसूचित जाति तथा 20195 अनु. जनजाति के व्यक्ति थे। उक्त अवधि में 20380 रिक्त पद विज्ञापित किये गये जिसके विरुद्ध 211969 प्रार्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये तथा 11,483 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

❖ ❖ ❖

5. कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र

5.1 मानसून :

राज्य में कृषि की स्थिति मुख्य रुप से वर्षा के समय पर आगमन पर निर्भर करती है, विशेष रुप से खरीफ मौसम में जहां फसलों का उत्पादन व उत्पादकता न केवल वर्षा की मात्रा पर अपितु वर्षा के उचित वितरण के साथ-साथ इसके सही समय पर आवश्कतानुसार होने पर निर्भर है।

राजस्थान में मानसून की प्रकृति साधारत: अनियमित व अनिश्चित है। वर्ष 1996-97 में मानसून के विलम्ब से आने के बावजूद भी सम्पूर्ण राज्य में संतोषप्रद वर्षा हुई। माह जून से सितम्बर, 96 के मध्य 72.63 से.मी. वर्षा रिकार्ड की गई, जो कि इस अवधि की सामान्य वर्षा से 39 प्रतिशत अधिक है।

5.2. कृषि उत्पादन :

राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है तथा राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है, जहां शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (राज्य आय) का 40 प्रतिशत से अधिक भाग कृषि एवं संबद्ध सेवाओं से सृजित होता है।

गत तीन वर्षों के प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल एवं उत्पादन निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :-

तालिका 5.2.1

फसल	क्षेत्रफल (लाख हैक्टेयर में)			उत्पादन (लाख टनों में)		
	1994-95 संशोधित	1995-96 अंतिम	1996-97 संभावित	1994-95 संशोधित	1995-96 अंतिम	1996-97 संभावित
1	2	3	4	5	6	7
अनाज	93.23	83.09	88.34	97.45	81.03	105.90
खरीफ	67.65	59.16	62.56	36.95	22.20	35.93
रबी	25.58	23.93	25.78	60.50	58.83	69.97
दलहन	36.02	35.74	37.16	19.65	14.63	21.12
खरीफ	19.77	19.14	20.63	5.45	3.29	5.97
रबी	16.25	16.60	16.53	14.20	11.34	15.15
खाद्यान्न	129.25	118.83	125.50	117.10	95.66	127.02
खरीफ	87.42	78.30	83.19	42.40	25.49	41.90
रबी	41.83	40.53	42.31	74.70	70.17	85.12
तिलहन	34.89	38.39	40.43	28.34	30.68	40.94
खरीफ	10.87	10.10	12.41	7.53	6.42	8.95
रबी	24.02	28.29	28.02	20.81	24.26	31.99
गन्ना	0.22	0.28	0.22	9.87	13.85	10.21
कपास*	4.86	6.06	5.89	8.75	13.38	12.95

* उत्पादन लाख गांठों में (प्रत्येक गांठ में 170 कि.ग्रा.)

वर्ष 1996-97 में खरीफ खाद्यान्न के अन्तर्गत अनुमानित 83.19 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में बुवाई हुई, जबकि वर्ष 1995-96 में खरीफ खाद्यान्न का क्षेत्रफल 78.30 लाख हैक्टेयर था। वर्ष 1996-97 में खरीफ खाद्यान्न का कुल उत्पादन 41.90 लाख टन होने का अनुमान है, जो कि वर्ष 1995-96 में 25.49 लाख टन था। इस प्रकार चालू वर्ष 1996-97 में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में 64.38 प्रतिशत बढ़ोतरी होने की संभावना है। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान बाजरा व मक्का की फसलों का रहता है। वर्ष 1996-97 में बाजरा का उत्पादन 21.00 लाख टन होना अनुमानित है, जो कि वर्ष 1995-96 में 11.52 लाख टन था, जो 82.29 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 1995-96 में मक्का का उत्पादन 8.08 लाख टन था, जिसके बढ़कर वर्ष 1996-97 में 10.16 लाख टन होने का अनुमान है। इस प्रकार मक्का के उत्पादन में 25.74 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

वर्ष 1996-97 के रबी के मौसम में खाद्यान्नों का उत्पादन 85.12 लाख टन होने की संभावना है, जो कि वर्ष 1995-96 में 70.17 लाख टन था, जो 21.31 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाता है। रबी के खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान गैहूं की फसल का रहता है। वर्ष 1996-97 में गैहूं का उत्पादन 64.81 लाख टन होना अनुमानित है, जबकि वर्ष 1995-96 में 54.93 लाख टन था, जो 17.99 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाता है। आलोच्य अवधि के दौरान जौ का उत्पादन 5.16 लाख टन होना अनुमानित है, जो कि वर्ष 1995-96 में 3.90 लाख टन था।

उर्जा एवं खनिज लवणों की आपूर्ति एवं भोजन में प्रोटीन की कमी की पूर्ति करने के लिये दलहन आहार का विशेष महत्व है। खरीफ दालों का उत्पादन वर्ष 1995-96 के 3.29 लाख टन की तुलना में वर्ष 1996-97 में 5.97 लाख टन होना संभावित है, जो कि 81.46 प्रतिशत अधिक है। चने की फसल का उत्पादन जो वर्ष 1995-96 में 10.90 लाख टन था, बढ़कर वर्ष 1996-97 में 14.83 लाख टन होने की संभावना है, यह गत वर्ष की तुलना में 36.06 प्रतिशत अधिक है।

खरीफ मौसम के तिलहन के उत्पादन में मूंगफली, तिल, सोयाबीन व अरण्डी तथा रबी मौसम में राई-सरसों, तारामीरा व अलसी सम्मिलित है। वर्ष 1996-97 के दौरान तिलहन का उत्पादन पूर्व के समस्त रिकार्ड को पार कर 40.94 लाख टन होना अनुमानित है, जो कि वर्ष 1995-96 में 30.68 लाख टन था, यह गत वर्ष से 33.44 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार वर्ष 1996-97 में खरीफ तिलहन का उत्पादन 8.95 लाख टन होना अनुमानित है जो कि वर्ष 1995-96 के 6.42 लाख टन उत्पादन से 39.41 प्रतिशत अधिक है। रबी में तिलहन उत्पादन वर्ष 1996-97 में 31.99 लाख टन होना अनुमानित है, जो कि वर्ष 1995-96 में 24.26 लाख टन था, यह 31.86 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 1996-97 में राई-सरसों का उत्पादन 31.06 लाख टन होने की संभावना है जबकि वर्ष 1995-96 में 23.68 लाख टन था, यह 31.17 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 1995-96 में गन्ना का उत्पादन 13.85 लाख टन था, जो कि घटकर वर्ष 1996-97 में 10.21 लाख टन रह जाने की संभावना है।

कपास एक महत्वपूर्ण नगदी फसल है, जो कि राज्य के गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में अधिकता से बोयी जाती है। वर्ष 1996-97 में कपास का उत्पादन 12.95 लाख गांठे होना संभावित है जबकि वर्ष 1995-96 में यह 13.38 लाख गांठे था, जो 3.21 प्रतिशत कमी दर्शाता है।

5.3 कृषि विस्तार एवं आदान प्रबन्धन :

अधिक उत्पादन की प्राप्ति हेतु अच्छे बीजों की उपलब्धता आवश्यक है। तदानुसार राज्य में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हेतु "उन्नत बीज कार्यक्रम" अपनाया गया है। फसल की उपज में संतुलित वृद्धि के लिये उर्वरकों का संतुलित उपयोग भी एक मुख्य भूमिका प्रदान करता है।

राज्य में अनियमित मानसून व मौसम की विपरीत स्थितियों के, कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा कृषि विस्तार एवं आदान प्रबन्धन कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं। कृषि विस्तार एवं आदान प्रबन्धन कार्यक्रम की वर्ष 1995-96 व 1996-97 की उपलब्धियां निम्न तालिका में दर्शाई गई हैं :-

तालिका 5.3.1

क्र.सं.	मद	मौसम	इकाई	1995-96 की उपलब्धियां	1996-97 लक्ष्य	1996-97 संभावित उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	अधिक उपज वाली फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल	खरीफ	लाख	16.77	17.00	14.50
		रबी (गेहूं)	हैक्टेयर	16.40	17.00	17.25
2.	अधिक उपज वाली किस्मों के बीजों का वितरण	खरीफ	''000	53.34	53.00	52.14
		रबी (गेहूं)	क्विंटल	169.67	150.00	197.00
3.	अन्य अन्नत बीजों का वितरण	खरीफ	''	71.15	60.30	79.88
		रबी		50.17	46.50	57.48
4.	उर्वरकों का वितरण	खरीफ	''000 मै.टन	299.90	309.00	279.12
		रबी	'' ''	342.65	418.60	424.46
5.	जीवाणु कल्चर पैकेट्स का वितरण	खरीफ	पैकेट्स लाख	2.93	10.50	4.00
		रबी	संख्या में	4.32	9.50	4.00
6.	पौध संरक्षण उपायों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	खरीफ	लाख हैक्टे. में	47.81	37.00	48.71
		रबी	''	40.00	35.00	36.00

5.4 सिंचाई :

राज्य में कुल बोये गये क्षेत्रफल का केवल 29.00 प्रतिशत (औसतन) सिंचित क्षेत्र है। सिंचाई के चार प्रमुख स्रोतों में नहरें, तालाब, कुएं एवं नलकूप हैं। वर्ष 1994-95 के दौरान राज्य में कुल सिंचित क्षेत्रफल का 60.24 प्रतिशत कुओं व नलकूपों से, 34.31 प्रतिशत नहरों से तथा 5.45 प्रतिशत तालाबों व अन्य स्रोतों से सिंचित किया गया।

वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक सिंचित क्षेत्रफल की स्थिति निम्न तालिका में दी गई है :-

तालिका 5.4.1 (क्षेत्रफल ''000 हैक्टेयर में)

सिंचाई के स्रोत	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल			कुल सिंचित क्षेत्रफल		
	1992-93	1993-94	1994-95	1992-93	1993-94	1994-95
1. नहरें	1428	1373	1427	1990	1835	1995
2. तालाब	207	170	247	230	189	265
3. कुएं एवं नलकूप	2803	3009	3134	3231	3523	3503
4. अन्य	33	45	50	35	48	52
कुल	4471	4597	4858	5486	5595	5815

राज्य में उपलब्ध सतही जल क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग हेतु राज्य का सिंचाई विभाग विभिन्न वृहद् मध्यम व लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण में प्रयासरत है। वर्ष 1996-97 के दौरान सिंचाई क्षेत्र में (इंदिरा गांधी नहर परियोजना को छोड़कर) 264.45 करोड रुपये का प्रावधान रखा गया है, जिसमें से माही बजाज सागर परियोजना पर 30.00 करोड़ रुपये, बीसलपुर परियोजना पर 15.00 करोड़ रुपये, सिद्धमुख नोहर परियोजना पर 45.00 करोड़ रुपये एवं अन्य वृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण व बाढ़ राहत के उपायों के लिए 174.45 करोड़ रुपये रखे गये हैं, जिसमें घग्घर बाढ़ से राहत के कार्य भी सम्मिलित हैं।

वर्ष 1996-97 (माह नवम्बर, 96 तक) के दौरान लगभग 38.50 करोड़ रुपये की लागत के 26 नवीन लघु सिंचाई कार्य स्वीकृत किये गये, जिससे राज्य में 15160 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होगी।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत जिला चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर एवं बाड़मेर में, रावी एंव व्यास नदियों से राजस्थान को आवंटित 8.6 एम.ए.एफ. जल में से 7.59 एम.ए.एफ. जल का उपयोग करने हेतु कार्य किया जा रहा है। प्रशासनिक सुविधा को मध्यनजर रखते हुए, इस परियोजना को दो चरणों में लिया गया है।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में वर्ष 1996-97 हेतु 13.00 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इससे 4 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त वर्ष 1996-97 के दौरान द्वितीय चरण में 280 कि.मी. वितरण प्रणाली को पूर्ण कर 41000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया जावेगा।

सिंचाई एवं पेयजल की दृष्टि से भू-जल ही एक मुख्य स्रोत है। राज्य का भू-जल विभाग एवं राजस्थान जल विकास निगम प्रदेश में जल के सुव्यवस्थित दोहन एवं शोधन हेतु प्रयासरत है। वर्ष 1996-97 (माह दिसम्बर, 96 तक) के दौरान भू-जल विभाग द्वारा 371 नलकूप एवं 238 हैंडपंप स्थापित किये गये। इसके अतिरिक्त आलोच्य अवधि में विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत 1805 कुओं को ड्रीलिंग एवं ब्लास्टिंग द्वारा गहरा किया गया है।

5.5 पशुपालन :

राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन की अहम् भूमिका है। लघु एवं सीमांत काश्तकार, कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण निर्धन लोगों की बहुत बड़ी संख्या लाभप्रद रोजगार हेतु पशुधन पर आश्रित है। वर्ष 1992 की पशुगणनानुसार राज्य में 484.46 लाख पशुधन तथा 30.13 लाख कुक्कुट सम्पदा है। राज्य के पश्चिमी जिले स्वदेशी पशुधन के लिए प्रसिद्ध हैं।

वर्तमान में राज्य में 1468 पशु चिकित्सालय एवं जिला स्तरीय बहुउद्देशीय चिकित्सालय कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त पशु पालकों को समीपस्थ पशु चिकित्सा सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु 53 भ्रमणशील पशु चिकित्सा इकाईयां कार्यशील हैं। इसके अलावा राज्य में 45 खण्ड-स्तरीय भ्रमणशील पशु चिकित्सा इकाईयां एवं 29 पशु स्वास्थ्य जांच प्रयोगशाला कार्यरत हैं। प्रदेश में 15766 गौ-वंश इकाईयों पर औसतन एक पशु चिकित्सा संस्था कार्यरत है।

एकीकृत पशु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पशु स्वास्थ्य जांच हेतु जयपर, बीकानेर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभागों में स्थापित संस्थाओं का पुनर्गठन कर 749 उपकेन्द्र स्थापित किये हुए हैं। यह कार्यक्रम 5 से 8 कि.मी. की परिधि क्षेत्र में पशु स्वास्थ्य सेवायें उलपब्ध कराने हेतु राज्य के 21 जिलों में लागू है। राज्य के दक्षिणी व पूर्वी भागो के 12 जिलों की 40 चयनित पंचायत समितियों में "गोपाल कार्यक्रम" के अन्तर्गत सघन पशु विकास कार्य जारी है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 572 "गोपाल" कार्यरत हैं। राज्य में अश्व नस्ल सुधार हेतु 10 अश्व विकास केन्द्र कार्यरत हैं। अजमेर जिले के रामसर गांव में बकरियों के विकास एवं उनके चारा उत्पादन हेतु एक बकरी प्रजनन केन्द्र कार्यरत है।

शूकर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अलवर जिले में विदेशी नस्ल के "शूकर पालन फार्म" स्थापित हैं। राज्य में कुक्कुट विकास को गति देने हेतु एक नवीन पद्धति 'केज सिस्टम" राज्य कुक्कुट फार्म जयपुर पर विकसित की जा रही है। राज्य में 6 कुक्कुट फार्म एवं 17 सघन कुक्कुट विकास खण्ड कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त "फीड एवं फौडर" कार्यक्रम के अन्तर्गत इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के मोहनगढ़ गांव में एक चारा बीज उत्पादन फार्म स्थापित है।

5.6 डेयरी विकास :

यह कार्यक्रम मूल रूप से ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को शहरी उपभोक्ताओं से सम्बद्ध करने का कार्यक्रम है। दुग्ध सहकारी समितियों की गतिविधियां स्वयं किसानों के द्वारा संचालित एवं प्रबंधित की जाती हैं। इन समितियों का प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म का दूध एवं दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराना, पशु स्वास्थ्य रखरखाव एवं दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाया जाना सुनिश्चित कराना है। राज्य में माह दिसम्बर, 96 तक लगभग 9 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध संग्रहण क्षमता के 10 संयत्र एवं 4.7 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध ठंडा करने की क्षमता के 24 चीलिंग संयंत्र कार्यरत हैं।

राज्य में समस्त जिलों में 15 दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के माध्यम से एकीकृत दुग्ध विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 1996-97 में माह दिसम्बर 1996 तक 70 नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां गठित की गई तथा 105 बन्द समितियों को पुनर्जीवित किया गया। दिसम्बर, 1996 के अंत तक कुल कार्यशील समितियों की संख्या 3231 थी, जिनकी कुल सदस्य संख्या 3.76 लाख थी। वर्ष 96-97 में दिसम्बर, 96 तक औसतन 4.96 लाख लीटर दूध प्रतिदिन एकत्रित किया गया।

राज्य में 4 पशु आहार संयंत्रों के माध्यम से दुग्ध सहकारी संघ पशुओं को पोषक आहार उपलब्ध करवा रहा है। वर्ष 1996-97 में दिसम्बर, 96तक इन संयंत्रों द्वारा 47535 टन पशु आहार का उत्पादन एवं वितरण किया गया।

5.7 भेड़ पालन

राज्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भेड़ पालन तेजी से एक महत्वपूर्ण घटक बनता जा रहा है। यह व्यवसाय राज्य की जनसंख्या के बहुत बड़े भाग विशेषत: समाज के कमजोर वर्गों को अतिरिक्त आय एवं रोजगार के अवसर प्रदान करता है। राज्य के पश्चिमी व उत्तरी पश्चिमी भागों में कमजोर वर्गो के लिए भेड़ पालन उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। वर्ष 1992 की पशुगणना के अनुसार राज्य में 124.91 लाख भेड़ें थीं, जो कि देश में भेड़ों की कुल संख्या का लगभग 25 प्रतिशत है। उपलब्ध समंकों के अनुसार, राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 170 लाख कि.ग्रा. ऊन का उत्पादन होता है, जो कि देश के ऊन उत्पादन का 40 प्रतिशत है। भेड़पालन व्यवसाय में 2 लाख से अधिक परिवार लगे हुए हैं। भेड़ों में बीमारियों की रोकथाम हेतु दवाईयों की खुराकें, छिड़काव एवं टीकाकरण आदि कार्यक्रम बड़े पैमान पर चलाये जा रहे हैं। अच्छी किस्म के ऊन उत्पादन के लिए उन्नत भेड़ें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चयनित एवं वर्ण संकर नस्लों के प्रजनन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम भी राज्य में चलाये जा रहे हैं। पानी व चारे की कमी के कारण भेड़ें पश्चिमी राजस्थान से, राज्य की सीमा से जुड़े राज्यों जैसे मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश एवं गुजरात में चली जाती हैं, भेड़ों के ठहराव के दौरान उचित एवं तुरंत उपचार हेतु 41 स्थाई निगरानी चौकियां स्थापित हैं।

5.8 मत्स्य पालन :

राजस्थान में मत्स्य विकास हेतु 3.30 लाख हैक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें से 1.20 लाख हैक्टेयर वृहद् एवं मध्यम जलाशयों, 1.80 लाख हैक्टेयर छोटे तालाबों एवं 0.30 लाख हैक्टेयर नदियों/नहरों के रुप में हैं। ये स्रोत मत्स्य पालन के विकास में महत्व के हैं। मत्स्यपालन विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अच्छे मत्स्य बीजों का उत्पादन एवं भण्डारण के द्वारा मत्स्य उत्पादन बढ़ाना, मत्स्य पालकों को मत्स्य फार्म विकास अभिकरण द्वारा प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रदान करना है।

1996-97 में (दिसम्बर, 1996 तक) मत्स्य उत्पादन 4500 टन हुआ है। राज्य में 15 मस्त्य फार्म विकास अभिकरण कार्यरत हैं, इनमें से प्रत्येक को एक-एक हैक्टेयर जल क्षेत्र आवंटित किया गया है। इन अभिकरणों द्वारा मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वर्ष 1996-97 में माह दिसम्बर, 96 तक 8243 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया एवं उन्हें 4834 हैक्टेयर जल क्षेत्र आंवटित किया गया।

वर्ष 1996-97 में (दिसम्बर, 96 तक) 131 मिलीयन फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन हुआ। निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 1991 से एक योजना मत्स्य बीज सेवन (हेचरीज) प्रारंभ की गई। इस योजनान्तर्गत मत्स्य पालकों को

पूंजी लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम एक लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रुप में दिया जा रहा है। जनजाति क्षेत्र के लाभान्वितों को पूंजी लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 2 लाख रुपये अनुदान के रुप में दिया जा रहा है। प्रदेश में अब तक ऐसे स्वीकृत 10 मत्स्य बीज सेवन केन्द्रों में से 5 केन्द्र कार्यशील हैं।

5.9 वन :

पर्यावरण संरक्षण तथा जैविक वनस्पति संतुलन बनाये रखने के लिये वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है।

राजस्थान देश का द्वितीय बड़ा प्रदेश है तथा राज्य के कुल भू-भाग के 9 प्रतिशत क्षेत्र ही वन आच्छादित हैं, जबकि राष्ट्रीय वन नीति में कुल क्षेत्रफल के 33.33 प्रतिशत क्षेत्र में वनों की सिफारिश की गई है। इसलिये वनों का अनवरत विकास राज्य के लिये एक विचारणीय पहलू है। राज्य में वर्ष 1995-96 के अन्त तक 31753.57 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र था, जिसमें से 12272.71 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन, 16116.97 वर्ग किलोमीटर रक्षित वन एवं 3363.89 वर्ग किलोमीटर में अवर्गीकृत वन क्षेत्र था।

राज्य में वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास के कार्य को गति प्रदान करने के दृष्टिकोण से विशिष्ठ परियोजनाओं के अंतर्गत कार्य किये जा रहे हैं। वर्तमान में वन विभाग द्वारा ओ.ई.सी.एफ. जापान की वित्तीय सहायता से तीन वृहद वृक्षारोपण परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र बीकानेर एवं जैसलमेर में वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास की परियोजना के तहत 107.65 करोड़ रुपये की राशि वर्ष 1990-91 में स्वीकृत की गई थी। वर्ष 1995-96 के अंत तक 34045 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा चुका है। वर्ष 1996-97 के दौरान माह दिसम्बर, 96 तक 7563 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। इसके अतिरिक्त 13850 हैक्टेयर क्षेत्र में एडवांस सोइल का कार्य प्रगति पर है।

अरावली क्षेत्र वृक्षारोपण परियोजना वर्ष 1992-93 में राज्य के 10 जिलों में प्रारंभ की गई। इस परियोजना के अंतर्गत 176.69 करोड़ रुपये की लागत से 1.15 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जावेगा। वर्ष 1995-96 के अंत तक 77440 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर, 96 तक 34045 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। 5900 हैक्टेयर क्षेत्र में एडवांस सोइल कार्य प्रगति पर था। औ.आई.सी.एफ. जापान की वित्तीय सहायता से वर्ष 1995-96 में एक और वृहद् वृक्षारोपण परियोजना राज्य के 14 जिलों में स्वीकृत की गई। इस परियोजना के अन्तर्गत 139.18 करोड़ रुपये की लागत से 55000 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जावेगा।

वर्ष 1995-96 की अवधि में केवल 15000 हैक्टेयर क्षेत्र में एडवांस सोइल कार्य संपन्न हुआ। वर्ष 1996-97 में 15000 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करने हेतु प्रावधित राशि 26.00 करोड़ रुपये के विरुद्ध 10.21 करोड़ रुपये का उपयोग माह दिसम्बर, 96 तक किया गया।

इसके अतिरिक्त वन विभाग द्वारा राज्य योजना/केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास के कार्य क्रियान्वित किये जा रहे हैं। विभिन्न योजनाओं के संसाधनों से वर्ष 1996-97 में माह दिसम्बर, 96 तक 82343 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया गया तथा सामाजिक वानिकी के तहत 365.07 लाख पौधे वितरित किये गये।

वन विभाग का मुख्य उद्देश्य जलाऊ लकड़ी, पशु चारा व इमारती लकड़ी के उत्पादन में वृद्धि करना है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र की बढ़ती मांग को पूरा किया सके तथा जलाऊ लकड़ी व पशु चारा की मांग व पूर्ति के बीच बढ़ती खाई को कम किया जा सके।

वन व पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल से आकाशीय अनुमान आधारित ''वन स्थिति प्रतिवेदन (फोरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट)'' प्रकाशित की जाती है। वर्ष 1991, 1993 व 1995 में प्रकाशित इस प्रतिवेदन में राजस्थान राज्य में वनों के क्षेत्र में क्रमश: 5 वर्ग कि.मी., 210 वर्ग कि.मी. व 181 वर्ग कि.मी. की वृद्धि होना दर्शाया गया है। फलत: 6 वर्षों की अवधि में वन क्षेत्र में कुल 396 वर्ग कि.मी. की वृद्धि हुई।

5.10 वन्य जीवन संरक्षण

वन्य जीव सम्पदा की दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध राज्य है। आकार व भौगोलिक स्थिति के कारण राज्य विभिन्न दुर्लभ पशु व पक्षियों जैसे भारतीय वस्टर्ड, चीता, तेंदुआ, चिंकारा, बारासिंगा, भेड़िया, सारस, बतख आदि की संरक्षण स्थली है।

वर्तमान में राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान व 23 अभ्यारण्य लगभग 9282 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.8 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त 32 निषेध क्षेत्र हैं, जो 1.48 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं।

राजस्थान के भरतपुर जिले में विश्व का अद्वितीय पक्षी अभयारण्ड है, जो कि जल पक्षियों का स्वर्ग है।

राज्य में वन्य जीव संरक्षण एवं इसके प्रबन्ध के अन्तर्गत निवास सुधार कार्य, जल संसाधनों का विकास, अग्नि शमन उपाय एवं खरपतवार निवारण आदि कार्य संपन्न किये जा रहे हैं।

❖ ❖ ❖

6. आधारभूत ढाँचागत विकास

6.1 विद्युत :

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल विभिन्न बिजली परियोजनाओं की खोज, स्थापना एवं उनके क्रियान्वयन तथा विद्युत संवहन एवं वितरण के कार्यों में संलग्न हैं। कोटा ताप बिजलीघर, माही जल विद्युत परियोजना, व्यास, चम्बल एवं सतपुड़ा परियोजना राज्य में विद्युत आपूर्ति के प्रमुख स्रोत हैं। इनके अतिरिक्त केन्द्रीय क्षेत्र के राजस्थान अणु शक्ति सिंगरोली ताप विद्युत परियोजना, रिहन्द, अंता, औरैया, नरौरा एवं दादरी गैस, ऊंचाहार ताप विद्युत एवं टनकपुर परियोजना राज्य की विद्युत आपूर्ति में योगदान करते हैं। वर्ष 1995-96 के अन्त में राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता 3049 मेगावाट थी। वर्ष 1996-97 में इसमें 4.335 मेगावाट उत्पादन क्षमता की वृद्धि होना संभावित है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में 4034.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता हेतु कार्यवाही आरंभ की जा चुकी है।

राज्य में विद्युत उत्पादन, क्रय एवं उपभोग की गत तीन वर्षों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

तालिका 6.1.1

(मि.यू. मे)

मद	वर्ष		
	1994-95	**1995-96**	**1996-97 (अनुमानित)**
1	2	3	4
1. उत्पादन (शुद्ध)	8150.63	9185.68	9830.15
2. क्रय	8272.87	9985.56	8897.50
योग (1+2)	16423.50	19171.24	18727.65
3. उपभोग			
(अ) अन्य राज्यों/व्यवस्थाओं	284.87	442.82	250.00
(ब) कॉमनपूल (भाखड़ा एवं व्यास)	147.85	165.57	165.00
(उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा उपभोग)			
(स) राजस्थान के उपभोक्ता	11853.09	13079.73	14213.43
(1) घरेलू	1658.88	1948.39	2063.10
(2) गैर घरेलू	598.20	685.04	676.21
(3) औद्योगिक	4827.25	4985.60	5854.79
(4) कृषि	3738.65	4362.66	4377.45
(5) सार्वजनिक जल प्रदाय	478.29	526.10	557.00
(6) पथ प्रकाश	60.76	72.38	68.91
(7) अन्य	491.03	499.76	615.92
(8) ग्रिड उप चौकियों व 33 के.वी. उप चौकियों में ऊर्जा उपभोग	37.33	40.68	41.00

वर्ष 1996-97 में दिसंबर 1996 तक राज्य में विभिन्न स्रोतों से 13568 मिलियन यूनिट विद्युत उपलब्ध कराई गई जो गत वर्ष की इसी अवधि की विद्युत उपलब्धता से 6.63 प्रतिशत अधिक है। यद्यपि राज्य को लगातार विद्युत की कमी का सामना करना पड़ा फिर भी कृषि कार्यों हेतु अप्रेल से नवंबर 1996 तक औसतन आठ घण्टे प्रतिदिन व दिसंबर 1996 में छ: घण्टे प्रतिदिन विद्युत उपलब्ध कराई गई।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 के अंत तक राज्य में 33827(1991 की जनसंख्या के अनुसार) ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका था। इनके अतिरिक्त वर्ष 1996-97 में (दिसंबर 96 तक) 188 ग्रामों का और विद्युतीकरण किया गया। इस प्रकार दिसम्बर, 96 तक कुल 34015 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। वर्ष 1996-97 में (दिसम्बर 96 तक) 23535 कुओं को विद्युतीकृत किया गया तथा अब तक राज्य में कुल 5.26 लाख कुओं को विद्युतीकृत किया जा चुका है।

वर्ष 1995-96 में 13079.73 मिलियन यूनिट विद्युत उपभोग की तुलना में वर्ष 1996-97 में 14213.43 मिलियन यूनिट विद्युत उपभोग होने की संभावना है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग पिछले वर्ष 265 यूनिट की तुलना में वर्ष 1996-97 में 281 यूनिट होने का अनुमान है।

6.2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत - रेडा :

राज्य में राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण (रेडा) के माध्यम से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की विभिन्न योजनाऐं जैसे सोलर पावर पैक की स्थापना, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पानी गर्म करने का सोलर संयंत्र, सोलर डिस्टीलेशन प्लांट आदि के द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 1996-97 के लिये इस कार्यक्रम के तहत 200.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त 50 गांवों का सौर ऊर्जा द्वारा विद्युतीकरण करने के लिए 649.38 लाख रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई है।

वर्ष 1996-97 में (दिसम्बर 1996 तक) 76.29 के.वी. के सोलर पावर पॉवर पैक व 18 एस.पी.वी. पंपों के स्थापन का कार्य किया गया। 491 एस.पी.वी. लाइटों के सुदृढ़ीकरण का कार्य भी किया गया। इसके अतिरिक्त 547 सोलर कुकर विक्रय हेतु अनुदान व 552 सोलर लालटेन उपलब्ध कराने का कार्य रेडा द्वारा किया गया।

बायो गैस विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 (दिसम्बर 1996 तक) में 857 बायोगैस संयंत्र स्थापित किये गये। इसके अतिरिक्त 221 संयंत्रों का कार्य प्रगति पर है।

6.3 परिवहन एवं संचार :

सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास का मुख्य आधार होती हैं। अत: राज्य की पंचवर्षीय योजनाओं में प्रारंभ से ही इस ओर समुचित ध्यान दिया गया है। राजस्थान भारत के उन कुछ राज्यों में से एक है, जहां सड़कों की लम्बाई राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। वर्ष 1996-97 के अन्त तक राज्य में सड़कों की लंबाई प्रति 100 वर्ग कि.मी. पर 40.31 कि.मी. होने का अनुमान है। वर्ष 1995-96 के अंत में यह 39.29 कि.मी. थी, जो कि राष्ट्रीय औसत 62.1 कि.मी. प्रति 100 वर्ग कि.मी. से बहुत कम है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नियंत्रित सड़कों की कुल लंबाई जो वर्ष 1995-96 में 70229 कि.मी. थी, वर्ष 1996-97 में बढ़कर 73729 कि.मी. होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों/अभिकरणों द्वारा भी 64220 कि.मी. सड़कों का निर्माण किया गया है।

वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक राज्य में विभिन्न प्रकार की सड़कों की लम्बाई निम्न प्रकार है :-

तालिका 6.3.1

(किलोमीटर में)

सड़कों के प्रकार	1994-95			1995-96			1996-97 (संभावित)		
	पक्की	कच्ची	योग	पक्की	कच्ची	योग	पक्की	कच्ची	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अ-सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कें :									
1. राष्ट्रीय राजमार्ग	2846	-	2846	2846	-	2846	2846	-	2846
2. राज्य राजमार्ग	9734	76	9810	9920	86	10006	9946	60	10006
3. मुख्य जिला सड़कें	5372	177	5549	5533	174	5707	5557	150	5707
4. अन्य जिला सड़कें	10254	1889	12143	10860	1755	12615	10980	1635	12615
5. ग्रामीण सड़कें	24460	8640	33100	26998	9818	36816	28728	11588	40316
6. सीमावर्ती सड़कें	2239	-	2239	2239	-	2239	2239	-	2239
योग अ	54905	10782	65687	58396	11833	70229	60296	13433	73729
ब- अन्य विभागों द्वारा निर्मित सड़कें :			46438			64220			64220
योग (अ+ब)			112125			134449			137949

राज्य में सड़कों के विकास पर अधिक ध्यान देने के लिये "सड़क विकास नीति" को लागू किया गया।

वित्तीय संस्थानों के माध्यम से हुडको द्वारा 10 पुलों, चार बाइपासों और एक सुरंग के निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी की गई। इनमें से 6 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया व शेष चार पुलों का कार्य प्रगति पर है।

विश्व बैंक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के दो उच्च मार्गों को चौड़ा करने एवं उनका दर्जा बढ़ाने का कार्य क्रमशः उदयपुर, डबोक-चित्तौड़गढ़ और सिरोही-माउण्ट आबू के कार्य को पूरा किया गया। राज्य के दो उच्च मार्गों अलवर, भिवाड़ी मडंरायल और अजमेर चित्तौड़गढ़ का कार्य प्रगति पर है जिसके मार्च 1997 तक पूरा होने की संभावना है।

जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग संख्या आठ पर चार लेन का कार्य प्रगति पर है। बाईस गोदाम, जयपुर के ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा उसे यातायात के लिए खोल दिया गया है।

सड़क परिवहन :

वर्ष 1995 में कुल 17.20 लाख पंजीकृत मोटर वाहनों की तुलना में वर्ष 1996 में यह संख्या बढ़कर 19.23 लाख हो गई है जो कि 12.06 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती है। तीन वर्षों (1994 से 1996 तक) राज्य में परिवहन विभाग में पंजीकृत विभिन्न प्रकार के मोटर वाहनों की संख्या निम्न तालिका में दर्शायी गई है।

तालिका 6.3.2

(संख्या)

परिवहन साधनों का प्रकार	वर्ष में वाहनों की संचयी संख्या			वर्ष 1995 की तुलना में 1996 की प्रतिशत वृद्धि
	1994	1995	1996	
1	2	3	4	5
1. मोटर रिक्शा	90	90	90	-
2. दो पहिया वाहन	1020054	1145295	1288411	12.50
3. ऑटो रिक्शा	23168	25218	28272	12.11
4. टैम्पों				
(1) सामान ढोने वाले	1371	1791	2258	26.07
(2) यात्री वाहन	4182	4513	5057	12.05
5. कार एवं स्टेशन वैगन	68881	76940	88746	15.34
6. जीप	55822	62272	71095	14.17
7. ट्रेक्टर	197386	217115	241009	11.01
8. ट्रेलर	42701	43561	45613	4.71
9. टैक्सी	12171	13083	14192	8.48
10. बस व मिनी बस	30870	33302	35627	6.98
11. ट्रक एवं अन्य सामान ढोने वाले वाहन	87232	95039	105285	10.78
12. अन्य	2667	2771	2872	3.64
योग :	1546595	1720990	1928527	12.06

वर्ष 1996-97 में (अप्रेल से दिसंबर, 1996 तक) 13689 सामान ढ़ोने वाले वाहन, 2446 स्टेज कैरिजेज एवं 4583 अनुबंधित वाहनों को स्थायी अनुज्ञा पत्र जारी किये गये। चालू वर्ष में 120.5 कि.मी. क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए 4 नये मार्ग खोले गये हैं।

❖ ❖ ❖

7. सामाजिक आधारभूत विकास

7.1 मानव संसाधन विकास :

शैक्षणिक दृष्टि से राजस्थान एक पिछड़ा हुआ राज्य है। राज्य में कुल साक्षरता का प्रतिशत 38.55 है। इसमें 54.99 प्रतिशत पुरुष तथा 20.44 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। महिला साक्षरता की स्थिति विशेष रुप से गंभीर है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र तथा पुरुष एवं महिला साक्षरता की दर के बीच बड़ा अन्तर है।

राज्य में शिक्षा के विकास के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक उपाय किये गये हैं।

14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकीकरण राज्य का मुख्य लक्ष्य है। इसके महत्व को स्वीकारते हुए प्राथमिक शिक्षा को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। सुव्यवस्थित शिक्षा एवं प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण को दृष्टि में रखते हुए, प्राथमिक शिक्षा के लिये एक पृथक निदेशालय की स्थापना का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

इस वर्ष 500 नये प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत किये गये, जिनमें से 182 प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके हैं। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए 600 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण के अन्तर्गत प्रभावी उपलब्धियों के लिए तथा प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने हेतु दो बाह्य सहायता परियोजनायें "शिक्षाकर्मी" तथा "लोक जुम्बिश" राज्य में क्रियान्वित की जा रही हैं। लोक जुम्बिश योजना राज्य के 122 कलस्टर एवं 58 खण्डों में चलाई जा रही है। शिक्षाकर्मी योजना के अन्तर्गत 1877 महिला विद्यालय तथा 3520 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में प्रारंभ किये जा चुके हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षाकर्मी विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर 6 से 14 आयु वर्ग की 83 प्रतिशत लड़कियों का नामांकन किया जा चुका है तथा इनमें 80.20 प्रतिशत औसत हाजरी रही।

वर्ष 1996-97 के दौरान प्रदेश में कार्यरत विद्यालयों की स्थिति निम्नानुसार है।

तालिका 7.1.1

संस्थाऐं	संख्या
1. प्राथमिक विद्यालय	33801
2. उच्च प्राथमिक विद्यालय	12692
3. माध्यमिक विद्यालय	3501
4. सीनियर माध्यमिक विद्यालय	1404

प्राथमिक शिक्षा के लिये बच्चों के प्रवेश में वृद्धि एवं उन्हें अध्ययनरत बनाये रखने हेतु राज्य में लड़कियों के लिये कक्षा एक से आठवीं तक तथा लड़कों के लिये कक्षा एक से पांच तक नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरण की योजना राज्य में क्रियान्वित की जा रही हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में 58.50 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित महिलाओं के माध्यम से बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए "सरस्वती योजना" क्रियान्वित की जा रही है। इस वर्ष 1996 में 1000 सरस्वती केन्द्र खोलने के लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर, 96 तक 650 सरस्वती केन्द्र खोले जा चुके हैं। अब यह योजना राज्य के समस्त जिलों में लागू कर दी गई है।

गुरू मित्र योजना राज्य के 10 जिलों में शिक्षकों को प्राथमिक स्तर पर प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से क्रियान्वित की जा रही है।

वर्ष 1996-97 में पहली से बाहरवीं कक्षा तक के नियमित विद्यार्थियों के लिए ''विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना'' राज्य में वर्ष 1996 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 22.50 लाख रुपये बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में जमा कराये जा चुके हैं। विद्यार्थियों से इस हेतु कोई प्रीमियम नहीं लिया जावेगा।

पर्याप्त प्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में 39 शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय कार्यरत हैं जिनमें इस वर्ष 7241 विद्यार्थियों को शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इनमें 2851 महिला प्रशिक्षणार्थी थीं। इसके अतिरिक्त राज्य में सेवा पूर्व एवं सेवारत शिक्षकों के लिए 27 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाऐं कार्यरत हैं। राज्य के 156 सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की योजना क्रियान्वित की जा रही है।

संस्कृत एवं संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का सम्पूर्ण-इतिहास तथा भारतीय आध्यात्मवाद एवं ज्ञान विज्ञान सभी कुछ संस्कृत में विद्यमान है। इन सबके संरक्षण एवं संवर्धन को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा संस्कृत शिक्षा के विकास के निरंतर प्रयत्न किये जा रहे हैं। राज्य में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना का एक प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

इस वर्ष संस्कृत निदेशालय के नवीन भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया। माह दिसम्बर, 96 तक 30 नवीन संस्कृत प्राथमिक विद्यालय भी खोले गये। इसके अतिरिक्त 2 शास्त्रीय विद्यालय, 4 उपाध्याय विद्यालय तथा 10 प्रवेशिका विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया।

राज्य सरकार का प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हुए सम्पूर्ण राज्य में अनौपचारिक शिक्षा प्रदान कर रहा है। सम्पूर्ण साक्षरता अभियान को एक महत्वपूर्ण रणनीति के रुप में अपनाया गया है। वर्तमान में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान राज्य के समस्त जिलों में विभिन्न चरणों में हैं। राज्य के सात जिलों (अजमेर, डूंगरपुर, भरतपुर, पाली, टोंक, बांसवाड़ा एवं सीकर) में उत्तर साक्षरता अभियान क्रियान्वित किया जा रहा है।

इस वर्ष 52 लाख पंजीकरण के लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर, 1996 तक सम्पूर्ण साक्षरता/उत्तर साक्षरता अभियान के अन्तर्गत 46.98 लाख अशिक्षित व्यक्तियों का पंजीयन कराया जा चुका है। इनमें से 8.23 लाख उत्तर साक्षरता अभियान के अन्तर्गत तथा 38.75 लाख व्यक्ति सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजीयन किये गये हैं। अब तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 9.10 लाख अनुसूचित जाति के व्यक्ति 11.13 लाख अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति लाभान्वित किये जा चुके हैं।

अनौपचारिक शिक्षा के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो अपनी आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य परिस्थितियों वश औपचारिक शिक्षा के लिए विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा के लिये जाने की स्थिति में नहीं हैं उनके लिए राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्ष 1996-97 में दिसम्बर के अन्त तक 17,207 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र कार्यरत थे। इस वर्ष अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत 5.65 लाख बच्चों के पंजीयन लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर, 1996 तक 5.02 लाख बच्चों का पंजीयन किया जा चुका है जिसमें 2.18 लाख लड़के तथा 2.84 लाख लड़कियां हैं।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में 6 विश्वविद्यालय (कृषि विश्वविद्यालय को सम्मिलित करते हुए), 4 विश्वविद्यालय समकक्ष संस्थाऐं, 211 महाविद्यालय/अनुसंधान संस्थाऐं (83 स्नातकोत्तर महाविद्यालय, 128 स्नातक स्तर के महाविद्यालय) राज्य में कार्यरत हैं।

इस वर्ष 3 महिला महाविद्यालय (दौसा, सवाई माधोपुर व डुंगरपुर) व 2 सहशिक्षा महाविद्यालय (नोखा व मेड़ता सिटी) में खोले गये हैं। राजकीय महाविद्यालय नीम का थाना को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया गया। स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर पर 14 नये विषय आरंभ किये गये।

शिक्षा सत्र 1995-96 में उच्च शिक्षा के अन्तर्गत 1,45,000 छात्रों ने शिक्षा प्राप्त की थी। वर्ष 1996-97 में यह संख्या बढ़कर लगभग 1,71,500 लाख हो गयी है। छात्राओं की संख्या जो वर्ष 1995-96 में 44,000 थी वह वर्ष 1996-97 में बढ़कर 52,800 हो गयी जो कि अध्ययनरत छात्राओं की संख्या में 20 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

राज्य का तकनीकी शिक्षा निदेशालय प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं पोलिटेक्निक विद्यालयों के माध्यम से तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवा रहा है।

7.2 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

राज्य का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग छूत एवं अन्य बीमारियों पर नियंत्रण एवं उनके उन्मूलन तथा उपचारात्मक एवं निरोधात्मक सेवायें उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है। राज्य में कार्यरत ऐलोपैथिक चिकित्सा संस्थाओं का विवरण निम्न प्रकार है:

तालिका 7.2.1

क्र.सं.	संस्थायें	संख्या
1.	चिकित्सालय	219
2.	औषधालय	278
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1616
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	261
5.	मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र	118
6.	सहायता केन्द्र (शहरी)	13
7.	उप केन्द्र	9400
8.	अन्तर्रोगी शैयायें	36702

वर्ष 1996-97 के दौरान "कुष्टता निवारण कार्यक्रम" के अन्तर्गत निर्धारित 700 लक्ष्यों के विरुद्ध 598 रोगियों की पहचान की गई। "क्षय रोग निवारण" कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 1996 के अन्त तक 45,000 क्षय रोगियों की पहचान के लक्ष्य के विरुद्ध 51749 नये रोगियों की पहचान की गई। "अन्धता निवारण कार्यक्रम" के अन्तर्गत जनवरी, 1996 तक 92961 व्यक्तियों की आंखों के ऑपरेशन किये गये। "मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम" के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 के दौरान 44 लाख रक्त पट्टिकाओं के संकलन एवं परीक्षण के लक्ष्यों के विरुद्ध (माह दिसम्बर, 96 तक) 65.91 लाख रक्त पट्टिकाओं का संकलन एवं परीक्षण किये गये हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 96 तक 82591 व्यक्तियों के रक्त की जांच की गई।

शिशु मृत्यु दर पर नियंत्रण रखने एवं गंभीर रोगों से बचाव हेतु राज्य में एक "सघन बाल टीकाकरण कार्यक्रम" चलाया जा रहा है, जिसकी प्रगति निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गई है।

तालिका 7.2.2

मद		लक्ष्य	उपलब्धि (माह जनवरी, 1997 के अन्त तक)
1.	डी.पी.टी. टीकाकरण	15,66,100	10,64,214
2.	बी.सी.जी. टीकाकरण	15,66,100	11,51,793
3.	खसरा टीकाकरण	15,66,100	9,88,814
4.	टिटनस इन्जेक्शन	17,47,200	10,58,422

पोलियो के सम्पूर्ण उन्मूलन जो कि राष्ट्रीय उद्देश्य है, की प्राप्ति हेतु चालू वर्ष के दौरान "पल्स पोलियो" के विशेष अभियान दो चरणों में क्रमशः 7 दिसम्बर, 1996 एवं 18 जनवरी 1997 को चलाया गया।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना (स्कीम) के अन्तर्गत, राज्य के विभिन्न उद्योगों एवं फैक्ट्रियों में कार्यरत मजदूरों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु जयपुर, कोटा एवं जोधपुर में तीन अस्पताल तथा विभिन्न स्थानों पर 60 औषधालय एवं एक होम्योपैथिक डिस्पेंसरी कार्यरत है। वर्ष 1996-97 में माह नवम्बर, 96 तक 15.81 लाख बहिरंग तथा 7846 अन्तरंग रोगियों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया (प्रदान) कराई गयी।

आयुर्वेद :

वर्तमान में आयुर्वेद विभाग के अन्तर्गत 3705 अस्पताल/डिस्पेंसरी कार्यरत हैं। चिकित्सा पद्धतिवार एवं श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार हैं।

तालिका 7.2.3

चिकित्सा पद्धति	अ श्रेणी चिकित्सालय		अ श्रेणी औषधालय		बी श्रेणी औषधालय		योग		महा योग
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	
1. आयुर्वेद	22	56	493	70	2784	86	3299	212	3511
2. होम्योपैथी	-	2	-	7	54	47	54	56	110
3. यूनानी	-	3	3	6	36	32	39	41	80
4. प्राकृतिक चिकित्सालय	-	2	-	-	1	1	1	3	4

इसके अतिरिक्त 5 चल आयुर्वेदिक चिकित्सा इकाईयां कोटा, बांसवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर तथा बीकानेर जिलों में कार्यरत हैं। आयुर्वेद विभाग में एक 200 शैयाओं युक्त चल शल्य चिकित्सा इकाई, अजमेर, मुख्यालय पर ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के विशिष्ट बीमारियों के उपचार हेतु कार्यरत हैं।

राज्य में 4 आयुर्वेदिक रसायन शालायें अजमेर, जोधपुर, भरतपुर एवं उदयपुर में कार्यरत हैं। जहां औषधियों का निर्माण कर उन्हें आयुर्वेदिक, यूनानी एवं प्राकृतिक अस्पतालों/औषधालयों को उपलब्ध करवाया जाता है।

7.3 परिवार कल्याण :

छोटे परिवार के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण राज्य में सघन परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में लक्ष्य विहिन नवीन पद्धति को अपनाया गया है। माह दिसम्बर, 1996 के अन्त तक 73,071 नसबन्दी, 1,15,670 लूप प्रविष्टि का कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त 3,40,486 गर्भ निरोधक गोलियां वितरित की गई तथा 5,24,152 निरोध वितरित कियें गये, जिससे संरक्षित दंपत्तियों की संख्या में आशातीत वृद्धि होगी।

जन्म दर पर नियंत्रण हेतु परिवार नियोजन के साधन प्रत्येक उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, औषधालय व चिकित्सालय पर उपलब्ध करवाये गये हैं व इसी के साथ प्रत्येक गांव में गर्भ निरोधक वितरण केन्द्र भी खोले जा रहे हैं। गर्भ निरोधकों के सामाजिक विपणन एवं सामुदायिक आधार पर गर्भ निरोधकों के वितरण की योजना पर विशेष बल दिया जा रहा है। "जनमंगल" योजना का राज्य के समस्त जिलों में विस्तार किया जा चुका है। राज्य में अपनायी गई परिवार कल्याण की नवीन पद्धति जन्म दर एवं शिशु मृत्यु दर की कमी में सहायक होगी।

राजलक्ष्मी बॉण्ड स्कीम का माह जून, 96 से सरलीकरण किया गया है जिसमें पति-पत्नी की निर्धारित आयु की सीमा को समाप्त कर दिया गया है एवं उसके लिए बॉण्ड की राशि 1500/- रुपये निर्धारित कर दी गई है। इस योजना के तहत वर्ष 1992-93 से 48,229 परिवारों को लाभान्वित किया गया। राज्य के दो जिलों टोंक एवं दौसा में परिवार कल्याण कार्यक्रम को नई दिशा देने हेतु "विकल्प" योजना चालू की गई है।

7.4 जल आपूर्ति :

भौगोलिक विषमताएं एवं भू-जल तथा सतही जल की सीमित उपलब्धता के कारण राज्य में सुरक्षित पेयजल की विकट समस्या है। राज्य सरकार जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दे रही हैं।

वर्ष 1996-97 में राज्य में पेयजल आपूर्ति हेतु राज्य योजनान्तर्गत 301.80 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से 157.30 करोड़ रुपये शहरी क्षेत्रों एवं 144.50 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित किये गये हैं।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिये अथक प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 1995-96 तक जल आपूर्ति के विभिन्न साधनों जैसे ट्यूबवेल, हैण्डपम्प आदि तथा परम्परागत जल स्रोतों एवं जल आपूर्ति योजनाओं के माध्यम से 37274 गांवों को सुरक्षित पेयजल योजना के अन्तर्गत लिया गया है। वर्ष 1996-97 में 500 आबादी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लक्ष्यों के विरुद्ध माह दिसम्बर, 1996 तक 92 घनी आबादी क्षेत्रों, 2690 अन्य आबादी क्षेत्रों एवं 553 आंशिक पेयजल सुविधा वाले गांवों में पूर्ण रुप से पेयजल आपूर्ति करवा दी गई है।

7.5 आवास :

जनसंख्या में तेजी से वृद्धि व उपलब्ध सीमित साधनों के कारण आवास की समस्या राज्य में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस समस्या के समाधान हेतु राजस्थान आवसन मण्डल राज्य के कमजोर वर्गों, कम आय वर्ग व मध्यम आय वर्ग को मकान उपलब्ध करवा रहा है। आवासन मण्डल की स्थापना से नवम्बर, 96 तक राजस्थान आवासन मण्डल में पंजीकृत आवेदकों की संख्या 207,538 थी। राजस्थान आवासन मण्डल की गतिविधियों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :

तालिका 7.5.1

गतिविधियां	प्रारम्भ से 30.11.96 तक की उपलब्ध	वर्ष 1996-97	
		लक्ष्य	उपलब्धियों 30.11.96 तक
1. निर्माण कार्य प्रारम्भ किये गये मकान	143612	9525	1141
2. पूर्ण निर्मित मकान	137996	5933	850
3. आवंटित मकान	133114	-	1867
4. मकानों का कब्जा दिया	118572	9050	2573
5. निर्माणाधीन मकान (नवम्बर 96)	5616	-	-

7.6 पिछड़ी जातियों का कल्याण :

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक विकास के लिये नि:शुल्क छात्रावास, छात्रवृत्ति, बुक बैंक योजना एवं क्षतिपूर्ति भत्ता आदि की सुविधा से लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य में इन वर्गों के लिये विभाग द्वारा कुल 611 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं जिसमें वर्ष 1996-97 में 20 नये खोले गये छात्रावास भी सम्मिलित है। इनके माध्यम से राज्य के 21298 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 1996-97 में 67 सम्बल गांवों में आधारभूत सुविधायें विकसित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा 50 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है। बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत "अनुसूचित जाति को न्याय" के तहत वर्ष 1996-97 में 1.95 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों के लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर, 1996 के अन्त तक 110774 अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है।

राज्य में जनजातीय क्षेत्रीय विकास एवं अन्य विभागों द्वारा जनजातियों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिये विभिन्न विकास योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, उदयपुर और सिरोही जिलों की 23 पंचायत समितियों को मिलाकर जनजाति उपयोजना क्षेत्र घोषित किया गया है। वर्ष 1991 की जनगणनानुसार राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या 54.75 लाख है, जिसमें से 24.01 लाख जनसंख्या जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में निवास करती है।

अनुसूचित जनजाति के कल्याण एवं विकास के लिए 1996-97 में कुल 45671.80 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है इसमें से 34221.67 लाख रुपये राज्य योजना में, 2040.30 लाख रुपये विशेष केन्द्रीय सहायता 1290.72 लाख रुपये संस्थागत वित्त एवं 8119.11 लाख रुपये केन्द्र प्रवर्तित योजना अन्तर्गत रखे गये है।

वर्ष 1996-97 में 45671.80 लाख रुपये के वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर, 1996 तक 20966.81 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। वर्ष 1996-97 में माह दिसम्बर, 1996 तक जनजाति उपयोजना क्षेत्र में विभिन्न मदों पर आवंटित एवं व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है।

तालिका 7.6.1

(लाख रुपये)

मद	आवंटन	व्यय (दिसम्बर 1996 तक)
1. कृषि एवं संबद्ध सेवायें	4993.13	1624.56
2. ग्रामीण विकास	8619.82	2896.31
3. सिंचाई	6789.46	4389.14
4. विद्युत	9228.85	4707.40
5. उद्योग एवं खनिज	1378.23	489.30
6. परिवहन एवं संचार	2175.74	750.46
7. वैज्ञानिक सेवायें	42.98	9.73
8. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें	12165.53	6030.46
9. आर्थिक सेवायें	155.13	29.97
10. सामान्य सेवायें	122.93	39.52
योग :	**45671.80**	**20966.85**

7.7 समाज कल्याण :

समाज कल्याण विभाग द्वारा महिला, बालकों एवं विकलांगों के कल्याण, वृद्धावस्था एवं अपाहिज पेंशन, परीवीक्षा सेवायें एवं किशोर बाल अधिनियम संबंधी विभिन्न योजनायें एवं कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

विकलांगों के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास हेतु विभिन्न आर्थिक सहायता सहित विभिन्न सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को सुविधायें प्रदान करने हेतु उनको चिन्हित कर परिचय पत्र जारी करने का कार्य प्रारंभ किया गया है। प्रायोगिक तौर पर जयपुर जिले के विकलांगों को परिचय पत्र वितरण करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

समाज के कमजोर वर्ग जैसे - बच्चे, महिलाऐं एवं विकलांग के जीवन स्तर को सुधारने के लिये विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

7.8 महिला एवं बाल कल्याण :

समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के समस्त 31 जिलों में 191 ग्रामीण एवं शहरी बाल विकास परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से 5 बाल विकास परियोजना संचालित की जा रही हैं। पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निम्नानुसार है।

तालिका 7.8.1

(लाख रुपये)

क्र.सं.	योजना मद	प्रावधान 1996-97	व्यय (दिसम्बर 1996 तक)
1.	केन्द्र प्रवर्तित योजना	3749.11	2005.73
2.	राज्य आयोजना	1650.00	654.30

वर्ष 1996-97 में माह दिसम्बर तक पोषाहार कार्यक्रम के तहत 11.42 लाख बच्चों एवं शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत 5.93 लाख बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

महिलाओं के कल्याण हेतु राज्य में विभिन्न योजनाऐं यथा महिला मण्डल, किशोर बालिका योजना तथा द्वाकरा आदि क्रियान्वित की जा रही हैं।

❖ ❖ ❖

8. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की निर्धनता का उन्मूलन करना, अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करना और अधिक राशि का ग्रामीण क्षेत्रों में विनियोजन कर ग्रामीणों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को बेहतर बनाना है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वर्ष 1996-97 में भी राज्य में विभिन्न राज्य/केन्द्र प्रवर्तित योजनायें/कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

8.1 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम :

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्राइसम और जीवनधारा प्रमुख हैं।

"एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम" के अन्तर्गत गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रति परिवार पूंजी निवेश जो वर्ष 1995-96 में 14500/- रुपये था उसे बढ़ाकर वर्ष 1996-97 में 20,000 रुपये तक करने का लक्ष्य रखा गया है। आलोच्य वर्ष में माह दिसम्बर, 96 तक 28437 परिवारों को 17.87 करोड़ रुपये का अनुदान एवं 53.06 करोड़ रुपये की ऋण सहायता उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया गया है।

"ट्राइसम योजना" के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 96 तक 1.26 करोड़ रुपये के व्यय से 2261 युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित किया गया एवं 4194 युवक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। युवाओं को प्रशिक्षण स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप व स्वरोजगार की बढ़ती संभावनाओं को मद्देनजर रखकर दिया जाता है।

पूर्व में जवाहर रोजगार योजना की उप योजना के रुप में क्रियान्वित की जा रही "इन्दिरा आवास योजना" ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1996-97 से स्वतंत्र रुप से क्रियान्वित की जा रही है। माह दिसम्बर, 96 तक 20455 आवास पूर्ण कराये गये हैं एवं 26917 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

"जीवनधारा योजना" का भी वर्ष 1996-97 से स्वतंत्र रुप से क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया है। इस योजनान्तर्गत गरीब परिवारों के लघु एवं सीमांत कृषकों को सिंचाई कुओं के निर्माण हेतु शत-प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है। आलोच्य वर्ष में माह दिसम्बर, 96 तक 1422 कुओं का निर्माण कराया गया एवं 6249 कुओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

8.2 आधारभूत ढांचे का विकास एवं रोजगार सृजन के कार्यक्रम :

इन कार्यक्रमों में प्रमुख रुप से जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, तीस जिला तीस काम, निर्बन्ध राशि, अपना गांव अपना काम और ग्रामीण विकास केन्द्र योजना आदि हैं।

"जवाहर रोजगार योजना" का मूलभूत उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न निर्माण कार्यों द्वारा बेरोजगार एवं अर्द्ध बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करवाना तथा सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है। इस योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में दिसम्बर, 1996तक 41.52 करोड़ रुपये के व्यय से 79.82 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया गया है।

"सुनिश्चित रोजगार योजना" वर्ष 1993-94 में 122 पंचायत समितियों में लागू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को कम से कम प्रति परिवार दो सदस्यों को वर्ष में 100 दिन के लिये रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में यह योजना राज्यों की 204 पंचायत समितियों में क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 1996-97 में दिसम्बर 96 तक योजनान्तर्गत 75.99 करोड़ रुपये के व्यय से 159.67 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया गया।

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु वर्ष 1991 से "अपना गांव-अपना काम" योजना लागू की गई थी। वर्ष 1996-97 में माह दिसम्बर, 96 तक 20.66 करोड़ रुपये (जन सहयोग की राशि सहित) व्यय कर 1390 कार्य पूर्ण कराये गये। इसके अतिरिक्त 2678 कार्य प्रगति पर हैं।

"तीस जिला तीस काम योजना" वर्ष 1991-92 में राज्य के सभी जिलों में चलाई जा रही है। चालू वर्ष 1996-97 में दिसम्बर, 96 तक 16.11 करोड़ रुपये पेयजल सुविधाओं पर व्यय किये गये।

"निर्बन्ध राशि योजना" के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 96 तक 17.31 करोड़ रुपये व्यय किये गये। इस योजनान्तर्गत विधायकों द्वारा पांच लाख रुपये तक की लागत के कार्य जैसे पेयजल, सम्पर्क सड़क, पुलिया, सुलभ शौचालय, पाठशालायें एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य भवन आदि अपने-अपने क्षेत्र में प्रतिवर्ष करवाये जा सकते हैं।

राज्य में "ग्रामीण विकास केन्द्र योजना" वर्ष 1995-96 से क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 1996-97 में दिसम्बर माह तक 3.54 करोड़ रुपये व्यय कर 1185 चयनित ग्रामीण विकास केन्द्रों में आधारभूत विकास कार्य किये गये।

8.3 क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम :

क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों में प्रमुख रुप से मरु विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्रीय कार्यक्रम, मेवात विकास, डांग विकास एवं सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम सम्मिलित है।

"मरु विकास कार्यक्रम" वर्ष 1977-78 से राज्य में मरु क्षेत्र के रेगिस्तान के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में यह कार्यक्रम राज्य के 16 जिलों के 85 विकास खण्डों में क्रियान्वित किया जा रहा है। चालू वर्ष 1996-97 में दिसम्बर 96 तक 14.46 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

"सूखा संभावित क्षेत्र" कार्यक्रम राज्य में वर्ष 1974-75 से प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में यह कार्यक्रम 10 सूखा ग्रस्त जिलों के 32 खण्डों में क्रियान्वित किया जा रहा है। समीक्षाधीन वर्ष में माह दिसम्बर, 96 तक 1.35 करोड़ रु. के विभिन्न जलग्रहण विकास कार्यों पर व्यय किये जा चुके हैं।

"मेवात क्षेत्रीय विकास" कार्यक्रम के अन्तर्गत अलवर एवं भरतपुर जिलों में मेव क्षेत्र के विकास हेतु रखे गये 2.00 करोड़ रुपयों के प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर, 96 तक सड़कों के निर्माण, पेयजल आपूर्ति, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थाओं के विकास हेतु 1.19 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं।

"डांग क्षेत्रीय विकास योजना" राज्य के 7 जिलों के 332 ग्राम पंचायतों में वर्ष 1995-96 से क्रियान्वित की जा रही है। चालू वर्ष में माह दिसम्बर 96 तक 3.13 करोड़ रुपये विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय किये गये हैं।

राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित चार जिलों (बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं गंगानगर) के 13 विकास खण्डों में वर्ष 1993-94 से "संशोधित सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम" क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में सुरक्षा, कानून व व्यवस्था के कार्यों के लिये इस कार्यक्रम में इन जिलों को सम्पूर्ण रुप से सम्मिलित किया गया है। वर्ष 1996-97 में माह दिसम्बर, 96 तक 9.09 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

8.4 सिंचाई क्षमता सृजन एवं ऊर्जा विकास के कार्यक्रम :

राज्य में "मैसिव कार्यक्रम" सभी जिलों में वर्ष 1991-92 से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों के कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु लघु सिंचाई कार्यों के लिय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1996-97 में माह दिसम्बर, 96 तक 1.66 करोड़ रुपये व्यय कर 2210 लघु एवं सीमांत कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है। राज्य में विश्व बैंक की सहायता से "सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना" भी क्रियान्वित की जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों के विकास हेतु वर्ष 1981-82 से "बायोगैस विकास कार्यक्रम" प्रारंभ किया गया था। योजना के अन्तर्गत बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिये अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। वर्ष 1996-97 में माह दिसम्बर 96 तक 857 संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं एवं 221 संयंत्र निर्माणाधीन हैं।

पंचायती राज्य के पुनर्गठन (खण्ड स्तरीय प्रशासन) एवं ग्रामीण स्वच्छता, जिला परिषदों के आधुनिकीकरण, पंचायत समिति के भवनों, पंचायत भवन (चौपाल), ग्रामीण सेवकों के प्रशिक्षण केन्द्र खोलने, कम्प्यूटर स्थापित करने, पंचायत राज संस्थाओं (दसवां वित्त आयोग) हेतु विकास अनुदान, पंचायत राज संस्थाओं को (राज्य वित्त आयोग) अनुदान एवं सूचना, संचार एवं शिक्षा आदि के लिए वर्ष 1996-97 में 120.43 करोड़ रु. सामुदायिक विकास एवं पंचायतों को आवंटित किये गये। इसके अतिरिक्त ग्रामीण मकानों के लिये 10 करोड़ रुपये भी आवंटित किये गये।

❖ ❖ ❖

9. अन्य कार्यक्रम

9.1 बीस सूत्री कार्यक्रम :

योजनाबद्ध विकास का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों का जीवन स्तर सुधारना है। गरीबी उन्मूलन एवं जीवन स्तर सुधारने के लिये वर्ष 1975 से 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की वर्ष 1982 व 1986 में पुन: संरचना की गयी।

बदलते हुए आर्थिक परिदृश्य में योजनाओं के विकेन्द्रीकरण एवं बाजारी शक्तियों की स्वतंत्रता को दृष्टिगत रखते हुए 20 सूत्री कार्यक्रम 1986 में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए अधिक आवश्यक सुरक्षा प्रदान की गई है। अत: बीस सूत्री कार्यक्रम का समानता एवं सामाजिक न्याय वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान है।

राज्य सरकार ने इस बहुआयामी कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं उसके परीवीक्षण के लिये एक सुदृढ़ रीति अपनायी है जिसमें कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु योजना कोष से आवंटन तदनुसार भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण तथा विभिन्न स्तरों पर जवाब देही निश्चित की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर तक प्रगति की सूचना प्रेषित करने हेतु सुव्यवस्थित प्रणाली विकसित की गई है।

9.2 अकाल/बाढ़ राहत :

वर्ष 1995-96 में वर्षा के देर से आगमन व असमान वितरण तथा प्रतिकूल मौसम स्थिति के फलस्वरूप 29 जिलों के 25478 गांव अभाव ग्रस्त घोषित किये गये थे। वर्ष 1995-96 के दौरान शुरु किये गये राहत कार्य जुलाई 96 तक चालू रहे। वर्ष 1996-97 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत रोजगार, पीने का पानी और चारे की व्यवस्था हेतु सम्बन्धित विभागों को 210.03 करोड़ रुपये आवंटित किये गये।

यद्यपि राजस्थान में मानसून की प्रवृति साधारणत: अनियमित व अनिश्चित रहती है, किन्तु वर्ष 1996-97 वर्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा वर्ष रहा, यहां तक कि राज्य के कुछ भागों में भारी एवं असामान्य वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी। चालू वर्ष 1996-97 में बाढ़ राहत कार्यों पर संबंधित जिला कलेक्टरों एवं विभिन्न विभागों को 33.12 करोड़ रुपये बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को राहत एवं पुनर्निमाण हेतु उपलब्ध कराये गये।

9.3 अल्प बचत :

राज्य की आर्थिक स्थिति में अल्प बचत की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि संकलित राशि का 75 प्रतिशत भाग भारत सरकार से दीर्घकालीन ऋण के रुप में वापिस लिया जा सकता है। अत: अल्प बचतों का राज्य के वित्तीय संसाधनों में ठोस योगदान रहता है। राज्य सरकार ने अल्प बचत का वातावरण तैयार करने हेतु विभिन्न प्रोत्साहनों की घोषणा की है, जिसके फलस्वरूप अल्प बचत संकलन में सराहनीय वृद्धि हुई है। परिवारों, व्यक्तियों, निगमों एवं संस्थाओं की बचत को संकलित कर राज्य के आर्थिक विकास में विनियोजित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिये अल्प बचत द्वारा 719 करोड़ रुपये की राशि संकलित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 1996 तक 419.88 करोड़ रुपये संकलित किये जा चुके हैं जो लक्ष्य का 58.40 प्रतिशत है। आशा की जाती है कि मार्च, 97 के अन्त तक शत प्रतिशत वार्षिक लक्ष्य अर्थात् 719 करोड़ रुपये का शुद्ध संकलन प्राप्त कर लिया जावेगा।

वर्ष 1996-97 के बजट अनुमानों में 550 करोड़ रुपये के अल्प बचत के लक्ष्यों के विरुद्ध दिसम्बर, 96 तक के शुद्ध संकलन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा 563.64 करोड़ की राशि ऋण के रुप में केन्द्र सरकार से प्राप्त कर ली गई है।

वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में अल्प बचत की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत संकलन की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है।

तालिका 9.3.1

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	अल्प बचत प्रतिभूतियां	1995-96 सकल	1995-96 शुद्ध	1996-97 (दिस.,96 तक) सकल	1996-97 (दिस.,96 तक) शुद्ध
1.	डाकघर बचत बैंक खाता	24386.29	1580.88	20720.05	2681.75
2.	आवर्ती जमा	30090.59	13387.80	26791.30	10172.89
3.	संचयी सावधि जमा	7.94	(-) 81.73	3.81	(-) 14.05
4.	डाकघर सावधि जमा	4452.34	(-) 5384.24	2775.18	(-) 1057.07
5.	मासिक आय योजना	7391.01	4855.91	4697.78	2792.45
6.	राष्ट्रीय बचत पत्र	743.68	(-) 4982.68	442.77	(-) 2014.19
7.	सेवा निवृत कर्मचारी जमा योजना	-	-	21.34	21.34
8.	इंदिरा विकास पत्र	16532.22	5278.06	12531.51	6176.02
9.	किसान विकास पत्र	35623.15	24708.32	24340.10	15183.92
10.	राष्ट्रीय बचत पत्र 8वां निर्गम	18762.78	16431.85	7114.51	4698.44
11.	पुराने बचत पत्र	-	(-) 1801.67	-	(-) 306.53
12.	लोक भविष्य निधि	11341.58	9092.80	5759.98	3652.79
योग :		**149331.58**	**63085.30**	**105198.33**	**41987.76**

उक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि डाकघर बचत खाता, आवर्ती जमा, किसान विकास पत्र एवं इन्दिरा विकास पत्र आदि बचत योजनाएं सर्वाधिक लोकप्रिय योजनाएं रही हैं। वर्ष 1995-96 में इन चार योजनाओं में कुल संकलन का 71.04 प्रतिशत राशि जमा हुई थी तथा वर्ष 1996-97 में माह दिसम्बर तक 80.21 प्रतिशत संकलन हुआ है।

❖ ❖ ❖

10. राज्य में प्रारंभ किये गये आर्थिक सुधार

राजकोषीय बाधाओं के होते हुए भी विकास की गतिविधियों में विनियोजन बढ़ाने हेतु राज्य निरंतर प्रयत्नशील है। इस हेतु बजट के माध्यम से कुशल राजकोषीय प्रबन्धन एवं विभिन्न ढांचागत आर्थिक सुधारों को राज्य में लागू किया गया है। परिणामस्वरूप राजस्व घाटे में इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 48 प्रतिशत का सुधार हुआ है। राज्य के वित्तीय संसाधनों में तीव्र गति से वृद्धि हुई है जो कि पिछले पांच वर्षों में कर राजस्व में हुई 124.46 प्रतिशत वृद्धिसे प्रतिबिंबित होता है। वर्ष 1990-91 में कर राजस्व 1216.50 करोड़ रुपये था, जो बढ़कर वर्ष 1995-96 में 2730.60 करोड़ रुपये हो गया। इसी प्रकार कुल राजस्व जो वर्ष 1990-91 में 3647.89 करोड़ रुपये था, वर्ष 1995-96 में बढ़कर 7629.69 करोड़ रुपये हो गया, तथा यह पिछले पांच वर्षों में राजस्व में 109.15 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

10.1 वाणिज्य कर :

राज्य बिक्री कर को अधिक तर्कसंगत बनाने हेतु जटिल बहुस्तरीय व्यस्था का सरलीकरण कर बिक्री कर व्यवस्था में ढांचागत परिवर्तन का कार्य आरम्भ किया गया है। कर के स्लेबों की संख्या में कमी की गई है। राज्य में बिक्री कर अधिनियम को संशोधित कर एक अक्टूबर 1995 से नया सरल व पारदर्शी "बिक्री कर अधिनियम 1994" लागू किया जा चुका है।

वाणिज्य कर व भूमि एवं भवन कर दोनों ही मामलों में स्व-कर निर्धारण योजनाएं शुरु की गई हैं। ईंट भट्टा, सर्राफा, लघु सीमेंट संयंत्र एवं जलपान गृहों के मामलों में बिक्री कर हेतु "कम्पाउन्डेड लेवी" के लिए ग्रीन चैनल योजना शुरु की गई है। वर्ष 1995 में राज्य में पहली बार स्व-कर निर्धारण की व्यवस्था प्रारम्भ की गई जो कि देश में एक अनूठी योजना है। मूल्य संवर्धित कर (वेट) व्यवस्था भी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

राज्य में वाणिज्य एवं व्यापार के निर्बाध प्रवाह हेतु एक मई 1995 से वाणिज्यिक कर एवं परिवहन विभाग की समस्त चैक पोस्ट समाप्त कर दी गई हैं। वाणिज्य कर विभाग में कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रगति पर है।

10.2 अन्य कर :

मोटर वाहन कर के अंतर्गत यातायात कर से संबंधित कर कानूनों के सरलीकरण एवं राज्य यातायात प्राधिकरण के स्वतंत्र नियंत्रक के रुप में कार्य करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

10.3 ऊर्जा क्षेत्र :

राजस्थान सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न सुधार एवं पुनर्गठन के उपाय किये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के माध्यम से निजी क्षेत्र में 4000 मेगावाट विद्युत क्षमता के सृजन का कार्य निरन्तर प्रगति पर है। ऊर्जा के क्षेत्र में व्यवस्थापन सुधार हेतु राजस्थान सरकार का दृष्टिकोण नीति निर्माण को व्यापारिक कामों से अलग करने का है। इसके अन्तर्गत टेरिफ रिफोर्म के माध्यम से अनुदान को कम करना तथा समाप्त करना भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा की मांग के अनुसार प्रबन्धन में सुधार लाया जायेगा। स्वायत्त राजस्थान बिजली नियंत्रक आयोग की स्थापना हेतु एक बिल केन्द्र सरकार को भेजा हुआ है।

प्रबन्धकीय स्वायत्तता, वित्तीय स्वतंत्रता, कार्यात्मक दक्षता में वृद्धि तथा विद्युत सेवाओं के गुणात्मक सुधार हेतु राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड का पुनर्गठन किया जा रहा है। इसमें कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को राजस्थान राज्य बिजली कारपोरेशन लिमिटेड में परिवर्तित करना भी सम्मिलित है। प्रतिस्पर्धा के माध्यम से विद्युत वितरण में निजी क्षेत्र का प्रवेश अभी परीक्षण के तौर पर प्रारम्भ हुआ है।

❖ ❖ ❖

आर्थिक स्थिति की तालिकायें

TABLES OF ECONOMIC SITUATION

1. राजस्थान की राज्य आय औद्योगिक उद्भव, प्रचलित कीमतों पर एवं प्रतिशत विभाजन
STATE INCOME OF RAJASTHAN BY INDUSTRIAL ORIGIN, AT CURRENT PRICES
AND PERCENTAGE DISTRIBUTION

(लाख रूपये)
(Lakh Rs.)

क्षेत्र Sector	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95*	1995-96@
1	2	3	4	5	6
1. कृषि	851510	1060764	988463	1316702	1400118
Agriculture	(42.48)	(44.30)	(40.19)	(42.97)	(41.54)
2. वन	38837	40827	41890	43667	49012
Forestry	(1.94)	(1.70)	(1.70)	(1.43)	(1.45)
3. मत्स्य पालन	1369	2486	3205	3920	3806
Fisheries	(0.07)	(0.10)	(0.13)	(0.13)	(0.11)
4. खनन्	46225	51265	38861	60553	56092
Mining	(2.31)	(2.14)	(1.58)	(1.98)	(1.66)
5. विनिर्माण (पंजीकृत)	133063	154422	170760	190876	213361
Manufacturing (Regd.)	(6.64)	(6.45)	(6.94)	(6.23)	(6.33)
6. विनिर्माण (गैर पंजीकृत)	83688	84649	88005	100583	115575
Manufacturing (Un-registered)	(4.18)	(3.54)	(3.58)	(3.28)	(3.43)
7. निर्माण कार्य	119253	143445	161989	196966	223685
Construction	(5.95)	(5.99)	(6.59)	(6.43)	(6.64)
8. विद्युत, गैस तथा जल पूर्ति	26221	37858	58557	69365	81807
Electricity, Gas & Water Supply	(1.31)	(1.58)	(2.38)	(2.26)	(2.43)
9. रेल्वे	33420	37736	41363	46401	55816
Railways	(1.67)	(1.58)	(1.68)	(1.51)	(1.66)
10. अन्य यातायात तथा संग्रहण	27961	33303	39185	49145	55709
Other Transport & Storage	(1.39)	(1.39)	(1.59)	(1.60)	(1.65)
11. संचार	13481	16695	21585	26256	31667
Communication	(0.67)	(0.70)	(0.88)	(0.86)	(0.94)
12. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	310416	362407	365875	437470	480007
Trade, Hotels & Restaurants	(15.49)	(15.14)	(14.88)	(14.28)	(14.24)
13. बैंक व्यापार तथा बीमा	72859	75698	92246	112942	138281
Banking & Insurance	(3.63)	(3.16)	(3.75)	(3.69)	(4.10)
14. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवायें	45512	51995	59618	67742	71417
Real Estate, Ownership of Dwelling & Business Services	(2.28)	(2.17)	(2.42)	(2.21)	(2.12)
15. सार्वजनिक प्रशासन	70814	85634	106958	112588	130913
Public Administration	(3.53)	(3.58)	(4.35)	(3.67)	(3.88)
16. अन्य सेवायें	129772	155248	181011	228927	263267
Other Services	(6.46)	(6.48)	(7.36)	(7.47)	(7.81)
शुद्ध राज्य उत्पाद, प्रतिकारक लागत पर	2004401	2394432	2459571	3064103	3370533
Net State Domestic Product at Factor Cost	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)
प्रति व्यक्ति आय (रूपयों में) Per Capita Income (Rs.)	4497	5257	5287	6452	6958

* प्रावधानिक अनुमान Provisional Estimates
कोष्ठकीय संख्याएं प्रतिशत को दर्शाती हैं Figures within bracket denote percentage.
@ त्वरित अनुमान Quick Estimates.

राज्य आय- औद्योगिक उद्भव प्रचलित कीमतों पर
STATE INCOME-BY INDUSTRIAL ORIGIN AT CURRENT PRICES

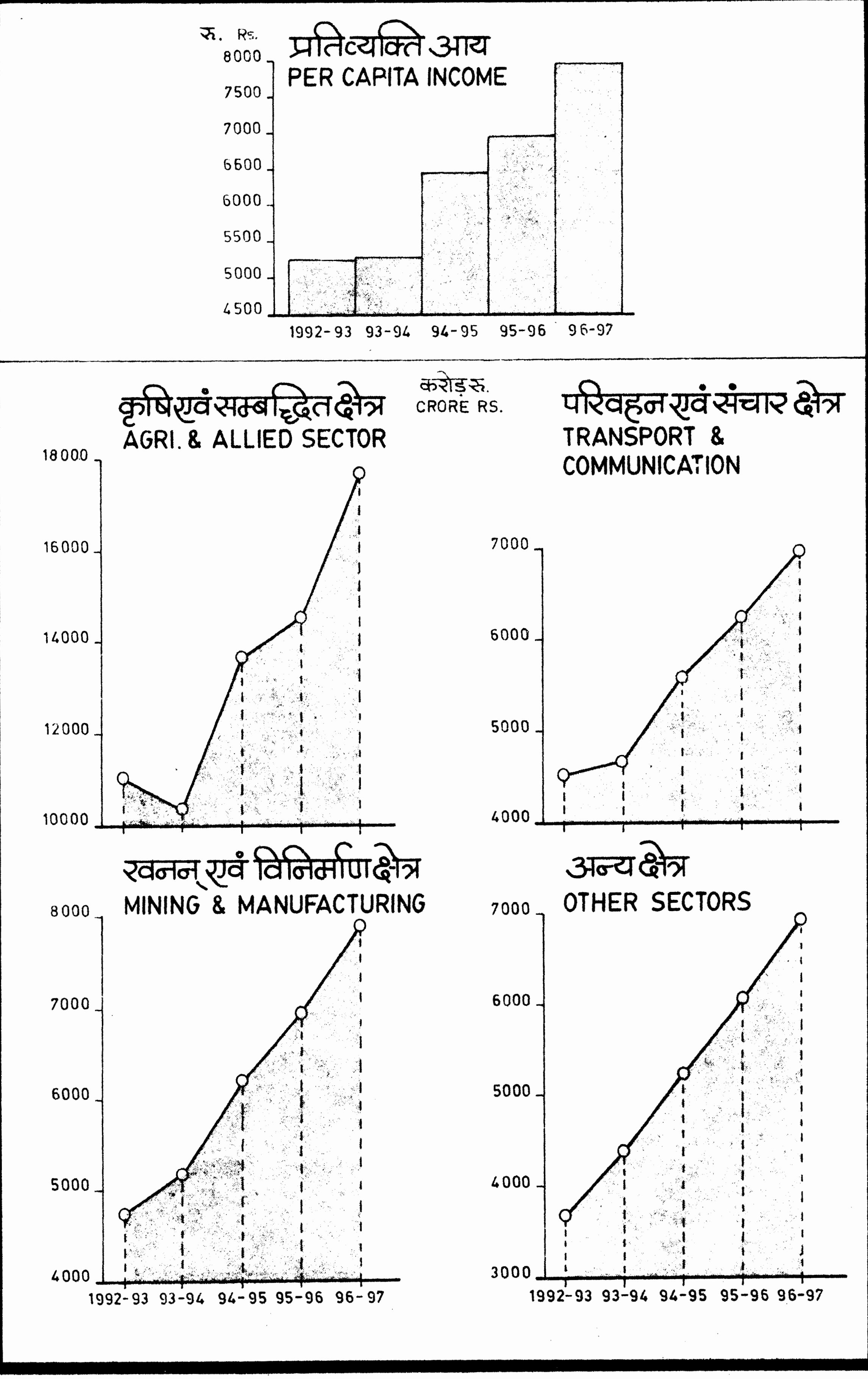

2. राजस्थान की राज्य आय-औद्योगिक उद्भव स्थिर (1980-81) कीमतों पर एवं प्रतिशत विभाजन
STATE INCOME OF RAJASTHAN BY INDUSTRIAL ORIGIN, AT CONSTANT (1980-81) PRICES AND PERCENTAGE DISTRIBUTION

(लाख रू. में)
(Rs.in Lakh)

क्षेत्र Sector	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95*	1995-96@
1	3	4	5	6	7
1. कृषि	320863	402710	311276	415621	391573
Agriculture	(40.88)	(44.36)	(37.37)	(41.91)	(39.41)
2. वन	14773	14896	15394	15663	15972
Forestry	(1.88)	(1.64)	(1.85)	(1.58)	(1.61)
3. मत्स्य पालन	471	654	738	827	728
Fisheries	(0.06)	(0.07)	(0.09)	(0.08)	(0.07)
4. खनन्	15739	17171	19800	25196	20629
Mining	(2.00)	(1.89)	(2.38)	(2.54)	(2.08)
5. विनिर्माण (पंजीकृत)	48110	53399	53832	58523	62176
Manufacturing (Regd.)	(6.12)	(5.88)	(6.46)	(5.90)	(6.26)
6. विनिर्माण (गैर पंजीकृत)	39136	41151	43246	49051	52198
Manufacturing (Un-registered)	(4.99)	(4.53)	(5.19)	(4.95)	(5.25)
7. निर्माण कार्य	54165	59598	64121	69963	73085
Construction	(6.90)	(6.56)	(7.70)	(7.05)	(7.36)
8. विद्युत्, गैस तथा जल पूर्ति	10179	14249	17853	18123	21265
Electricity, Gas & Water Supply	(1.30)	(1.57)	(2.14)	(1.83)	(2.14)
9. रेल्वे	5975	3755	4127	4116	4165
Railways	(0.76)	(0.42)	(0.50)	(0.42)	(0.42)
10. अन्य यातायात तथा संग्रहण	9061	9988	9850	10938	11598
Other Transport & Storage	(1.15)	(1.10)	(1.18)	(1.10)	(1.17)
11. संचार	3155	3837	4569	5295	5696
Communication	(0.40)	(0.42)	(0.55)	(0.53)	(0.57)
12. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	123995	139451	129439	150625	152579
Trade, Hotels & Restaurants	(15.80)	(15.36)	(15.54)	(15.19)	(15.36)
13. बैंक व्यापार तथा बीमा	36619	36576	37899	39479	41125
Banking & Insurance	(4.67)	(4.03)	(4.55)	(3.98)	(4.14)
14. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवायें	28240	28239	30879	31996	32954
Real Estate, Ownership of Dwelling & Business Services	(3.60)	(3.12)	(3.71)	(3.23)	(3.32)
15. सार्वजनिक प्रशासन	26150	29200	33456	31825	35782
Public Administration	(3.33)	(3.22)	(4.02)	(3.21)	(3.60)
16. अन्य सेवायें	48323	52949	56379	64445	72072
Other Services	(6.16)	(5.83)	(6.77)	(6.50)	(7.25)
शुद्ध राज्य उत्पाद, प्रतिकारक ल	784954	907823	832858	991686	993597
Net State Domestic Product at Factor Cost	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)
प्रति व्यक्ति आय (रूपयों में) Per Capita Income (Rs.)	1761	1993	1790	2088	2051

* प्रावधानिक अनुमान Provisional Estimates.
कोष्ठकीय संख्याएं प्रतिशत को दर्शाती हैं। Figures within bracket denote percentage.
@ त्वरित अनुमान Quick Estimates

राज्य आय–औद्योगिक उद्भव स्थिर (1980-81) कीमतों पर
STATE INCOME–BY INDUSTRIAL ORIGIN AT 1980-81 PRICES

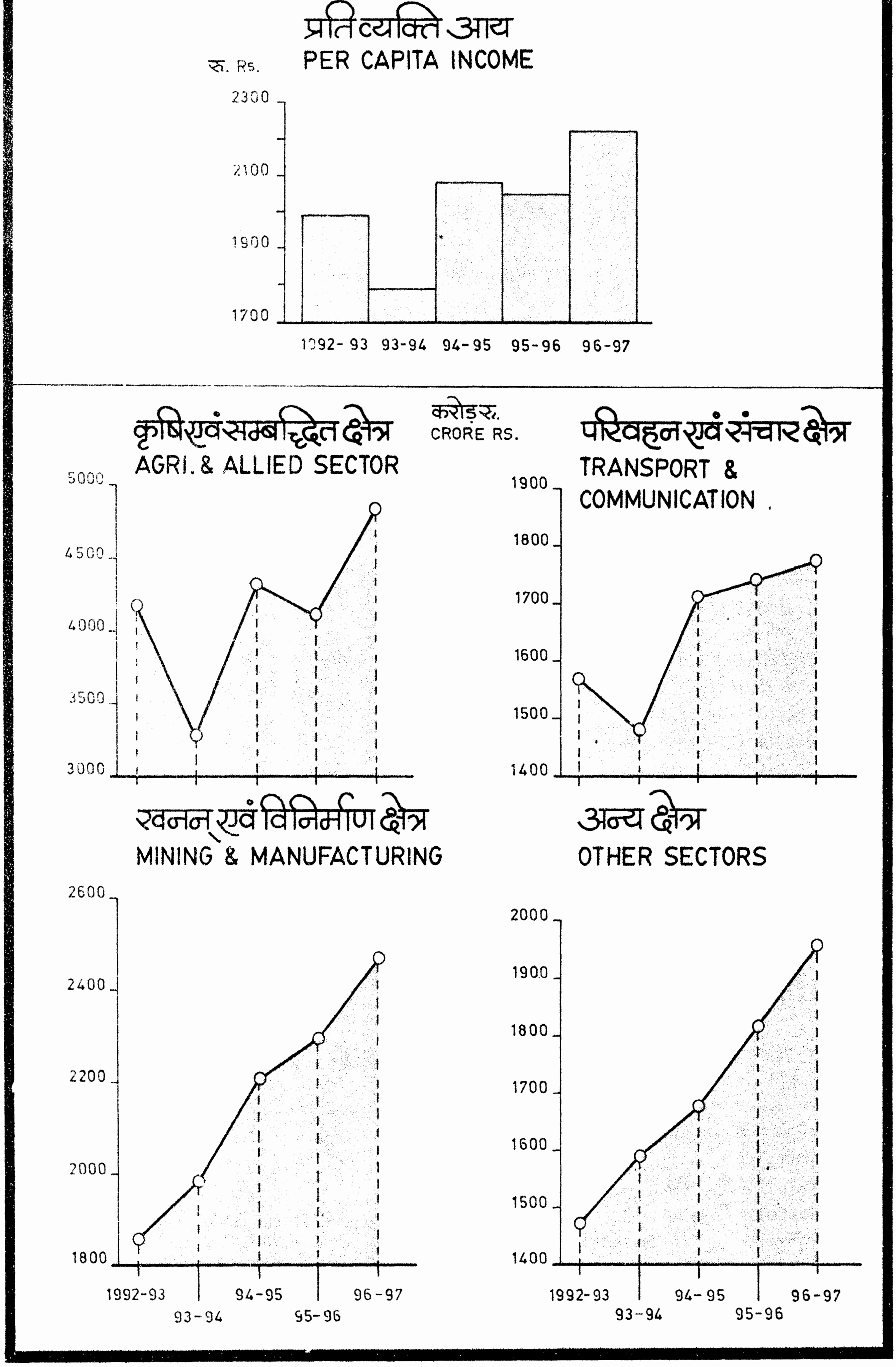

3. राजस्थान में कृषि उत्पादन के सूचकांक
INDEX NUMBER OF AGRICULTURE PRODUCTION IN RAJASTHAN

आधार (1979-80 से 1981-82 = 100) Base (1979-80 to 1981-82 = 100)

फसल Crop	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96 #
1	2	3	4	5	6	7
1. अन्न Cereals	177.89	139.79	195.56	118.37	192.00	161.18
अ - रबी Rabi	149.99	156.20	175.30	117.66	191.85	186.77
ब - खरीफ Kharif	227.51	110.72	231.61	119.68	192.37	115.84
2. दालें Pulses	146.07	77.52	124.10	90.65	166.65	123.77
3. कुल खाद्यान्न Total Food Grain	168.43	121.25	174.29	110.12	184.47	150.07
4. तिलहन Oilseeds +	506.98	587.33	500.99	455.26	551.29	613.37
5. रेशे (कपास एवं सण) Fibres(Cotton & Sanhemp)	209.22	191.31	230.30	188.81	198.10	300.90
6. मसाले (लाल मिर्च एवं अदरक) Spices and Condi-ments (Dry Chillies & Ginger)	310.52	232.91	419.68	317.05	267.40	250.54
7. तरकारियां (आलू) Vegetables (Potato)	763.35	643.73	743.61	599.94	487.59	575.33
8. अन्य फसलें Other Crops *	97.87	107.70	90.28	81.81	79.85	109.44
9. कुल अखाद्य फसलें Total Non-Food	398.11	447.54	400.71	358.36	421.26	479.74
10. समस्त फसलें All Crops	211.43	182.33	216.67	156.59	228.80	211.77

* गन्ना एवं तम्बाकू सम्मिलित हैं।
* Includes Sugarcane and Tobacco.
\+ तिल, मूंगफली, अरण्डी, अलसी, राई एवं सरसों सम्मिलित हैं।
\+ Includes Sesamum, Groundnut, Castor seed, Linseed and Rape & Mustard
\# प्रावधानिक Provisional

कृषि उत्पादन के सूचकांक
INDEX NUMBERS OF AGRICULTURAL PRODUCTION

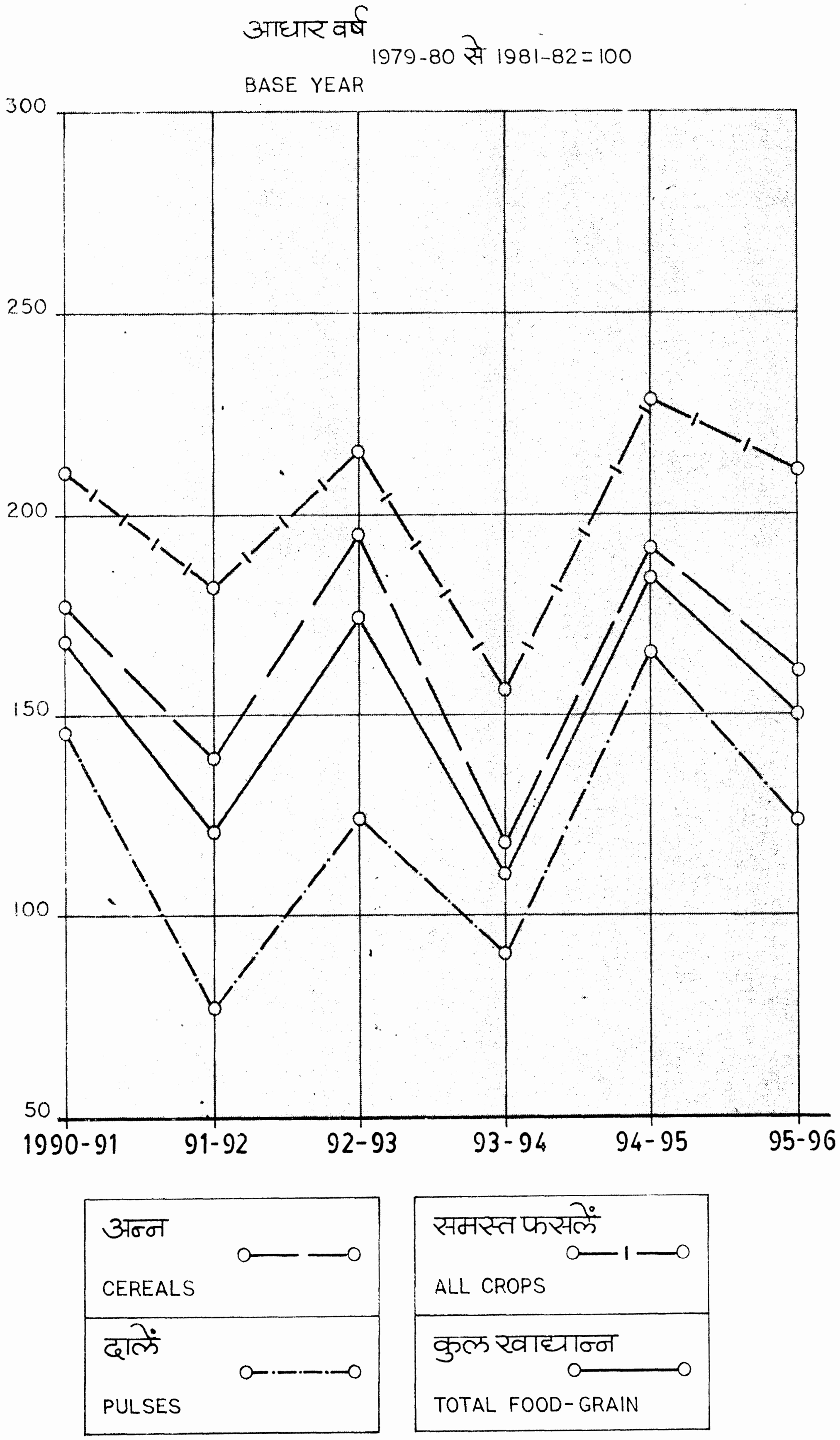

कृषि उत्पादन के सूचकांक
INDEX NUMBERS OF AGRICULTURAL PRODUCTION

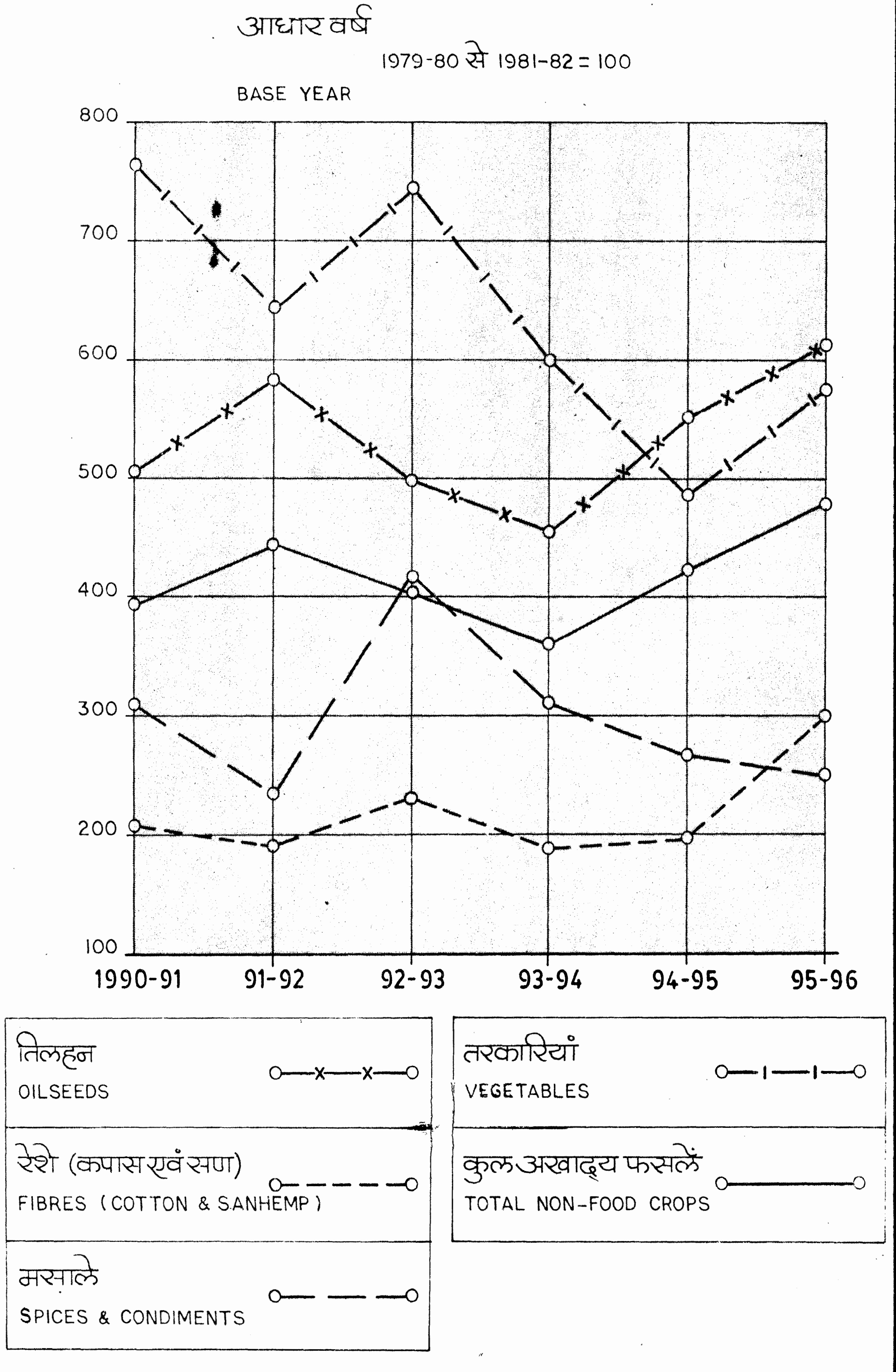

., औद्योगिक उत्पादन
INDUSTRIAL PRODUCTION

मद Items	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996*
1	2	3	4	5	6	7	8
1. सीमेन्ट Cement '000 टन '000 M. Tonnes	4263	4774	4828	4810	6567	6469	6596
2. शक्कर Sugar '000 टन '000 M. Tonnes	13	25	39	26	12	25	31
3. यूरिया Urea '000 टन '000 M. Tonnes	372	363	351	407	381	392	388
4. सुपर फास्फेट Super Phosphate '000 टन '000 M. Tonnes	76	134	103	71	71	36	35
5. बाल बियरिंग Ball Bearings लाख संख्या Lakh No.	157	177	163	184	206	216	231
6. विद्युत मीटर Electric Meters हजार संख्या '000 No.	908	991	875	877	1120	732	711
7. नमक Salt '000 टन '000 M. Tonnes	1055	1441	1181	1296	1171	1493	1102
8. पोलियेस्टर धागा Polyster yarn '000 टन '000 M. Tonnes	16.69	14.94	14.51	13.51	19.96	14.59	11.46

* प्रावधानिक Provisional

औद्योगिक उत्पादन INDUSTRIAL PRODUCTION

लाख मै.टन
LAKH TONNES

सीमेन्ट
CEMENT

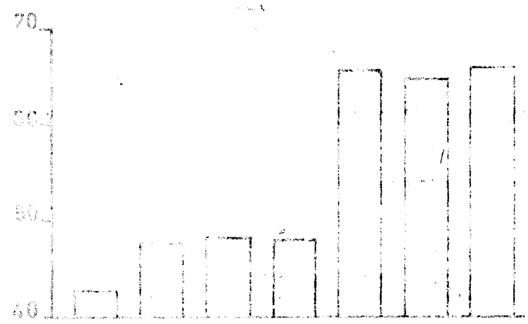

लाख सं.
LAKH NOs.

बाल बियरिंग
BALL BEARINGS

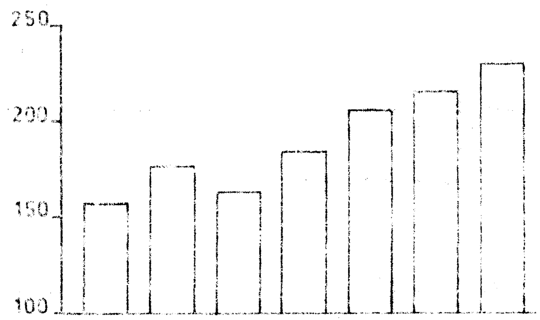

मै.टन
TONNES '000

शक्कर
SUGAR

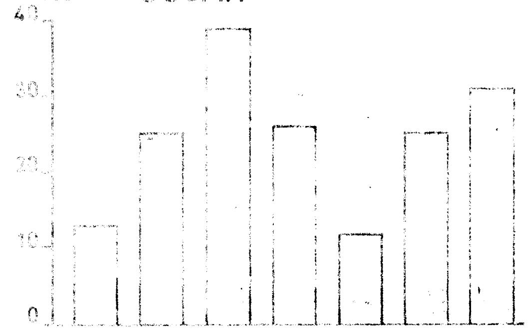

संख्या
NOs '000

विद्युत मीटर
ELECTRIC METERS

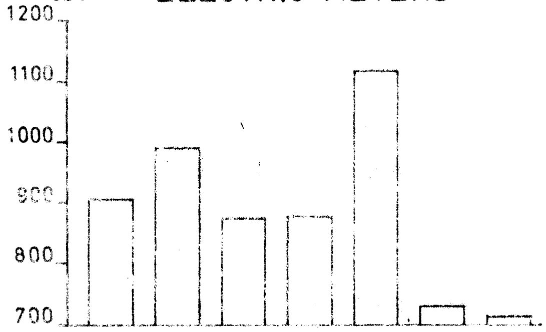

मै.टन
TONNES '000

यूरिया
UREA

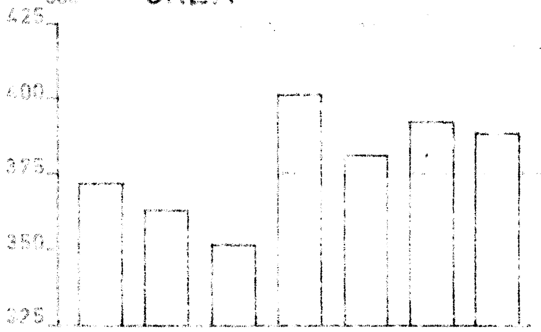

मै.टन
TONNES '000

नमक
SALT

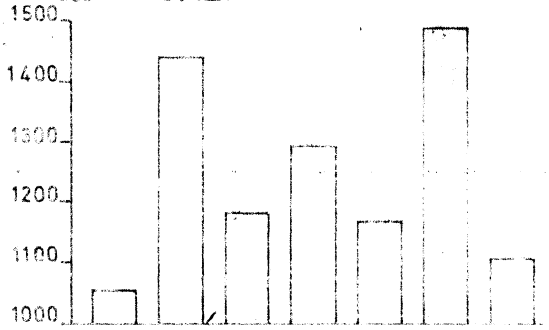

मै.टन
TONNES '000

सुपर फास्फेट
SUPER PHOSPHATE

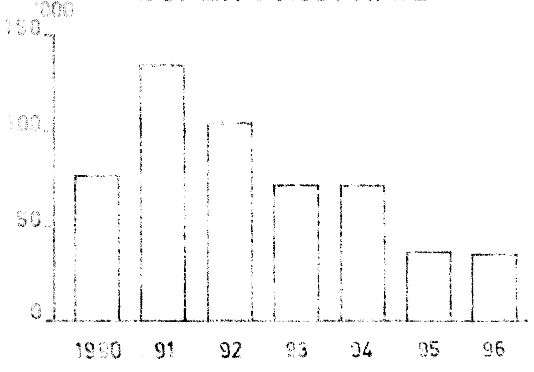

मै.टन
TONNES '000

पोलियेस्टर धागा
POLYSTER YARN

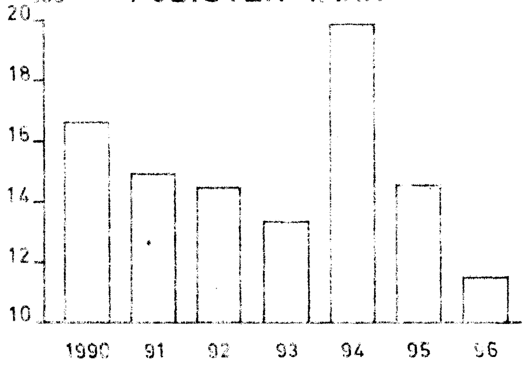

5. राजस्थान के थोक भाव सूचकांक
INDICES OF WHOLESALE PRICES IN RAJASTHAN

(आधार 1952-53=100)
Base

वर्ग Group	1991	1992	1993	1994	1995	1996
1	2	3	4	5	6	7
1. खाद्यान्न वस्तुयें Food Articles	1384.30	1558.50	1578.80	1771.80	1803.71	1946.26
2. औद्योगिक कच्चा माल Industrial Raw Materials	1497.60	1570.90	1555.30	1660.80	1888.73	1970.26
3. ईंधन, शक्ति एवं उपस्नेहक Fuel, Power And Lubricants	2900.10	3005.30	3076.70	3160.91	3314.23	4055.94
4. विनिर्मित वस्तुयें Manufactured Goods	1556.20	1668.90	1843.40	1889.93	1979.56	2098.64
5. सामान्य सूचकांक General Index	1467.80	1622.70	1668.70	1827.61	1885.77	2038.82

राजस्थान के थोक भाव सूचकांक
INDEX NUMBERS OF WHOLESALE PRICES IN RAJASTHAN

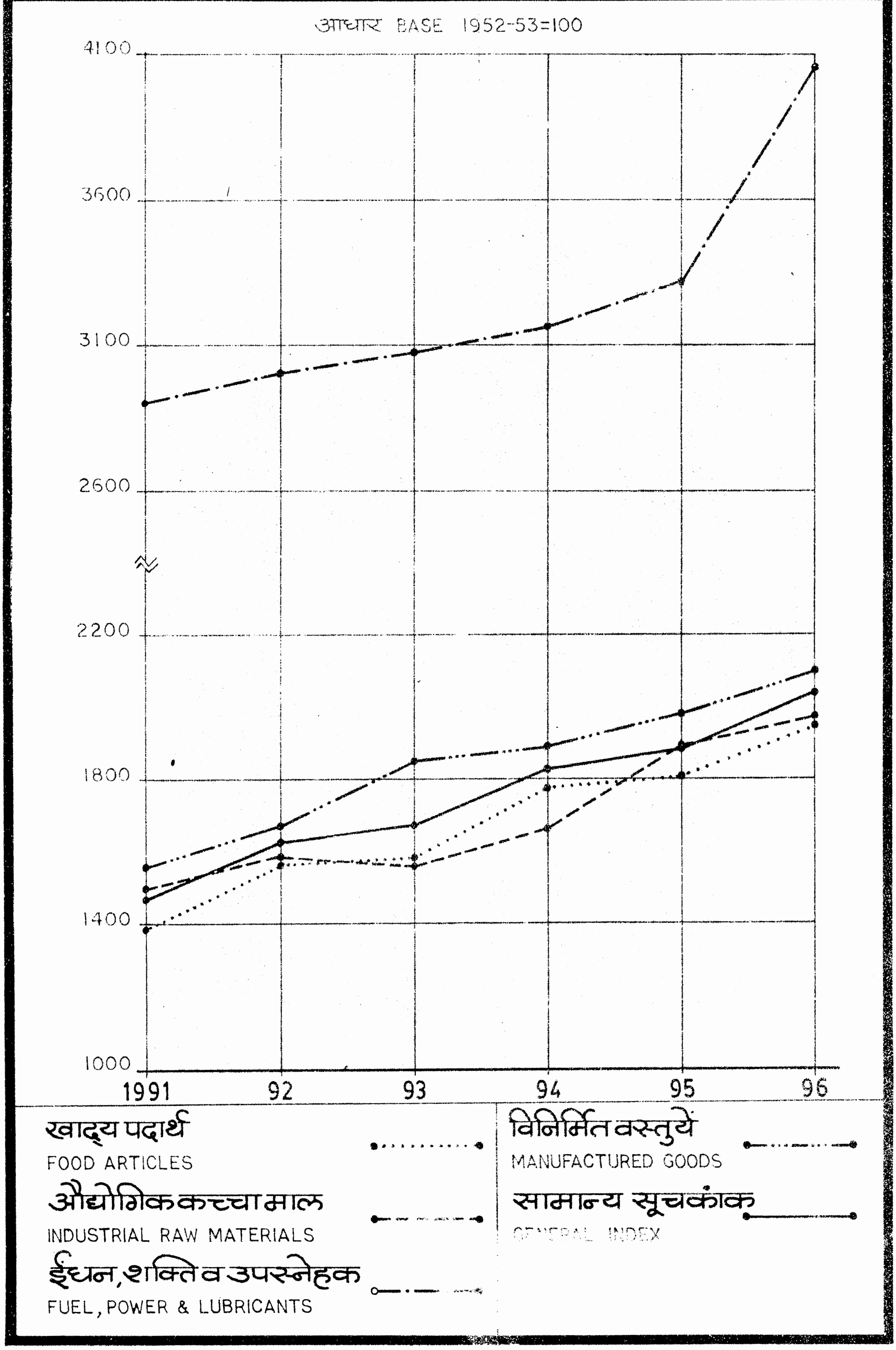

6. उपभोक्ता भाव सूचकांक
INDICES OF CONSUMER PRICES

वर्ग Group	1991	1992	1993	1994	1995	1996
1	2	3	4	5	6	7
अजमेर Ajmer						
(आधार 1982=100) Base						
(i) खाद्य Food	217	243	249	287	318	344
(ii) सामान्य General	217	243	253	280	305	332
जयपुर Jaipur						
(आधार 1982=100) Base						
(i) खाद्य Food	219	248	266	295	323	355
(ii) सामान्य General	210	228	245	269	291	321

उपभोक्ता भाव सूचकांक
COSUMBERS' PRICE INDEX NUMBERS

आधार BASE 1982 = 100

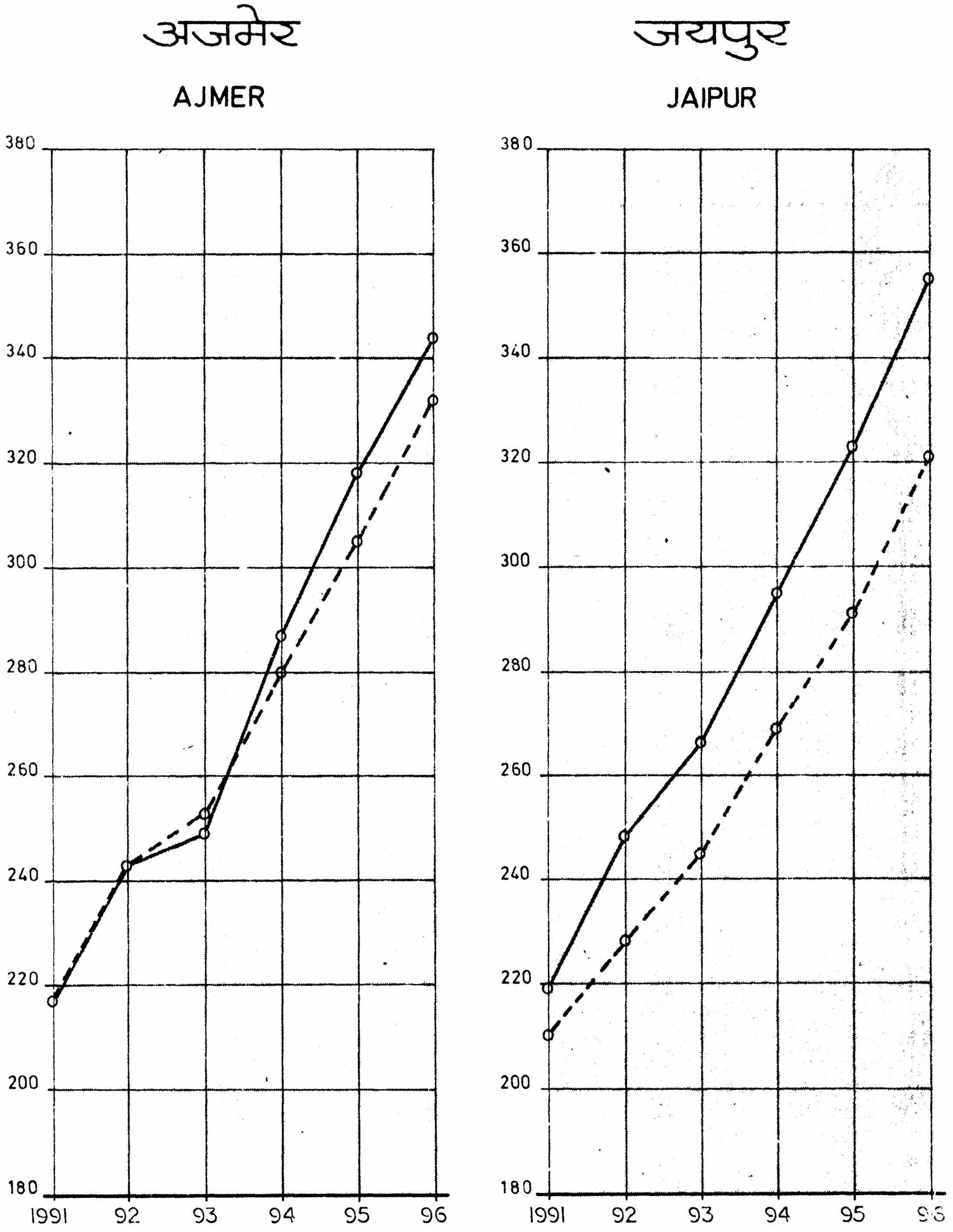

खाद्य वर्ग
FOOD GROUP

सामान्य वर्ग
GENERAL GROUP

7. राजस्थान में अकाल/अभाव स्थिति से हुई क्षति
LOSS DUE TO FAMINE/SCARCITY CONDITION IN RAJASTHAN

कृषि वर्ष Agriculture Year	प्रभावित जिलों की संख्या No. of Distts. Affected	प्रभावित ग्रामों की संख्या Number of Villages Affected	प्रभावित जनसंख्या (लाखों में) Population Affected (in Lakh)	भू-राजस्व * निलंबित (लाख रू) Land Revenue Suspended (Lakh Rs.)
1	2	3	4	5
1981-82	26	23246	200.12	646.15
1982-83	26	22606	171.62	515.68
1983-84	-	-	-	-
1984-85	21	10276	92.02	237.19
1985-86	26	26859	219.80	559.76
1986-87	27	31936	252.70	702.62
1987-88	27	36252	317.37	753.81
1988-89	17	4497	43.45	127.02
1989-90	25	14024	120.67	255.62
1990-91	-	-	-	-
1991-92	30	30041	289.00	325.87
1992-93	12	4376	34.66	29.06
1993-94	25	22586	246.81	491.36
1994-95	-	-	-	-
1995-96	29	25478	273.82	209.12
1996-97	-	-	-	-

* वित्तीय वर्ष के समंक
Figures For Financial Year

राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक
STATEWISE IMPORTANT ECONOMIC INDICATORS

राज्य STATE	देश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत Percentage of Area to total area of the Country	भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत 1991 Percentage of Population to Total Population of India 1991	जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग कि.मि. 1991 Density of Population Per Sq K.M. (1991)	नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत 1991 Percentage of Urban Population to total Population (1991)	साक्षरता का प्रतिशत 1991 Literacy Percentage * (1991)
1	2	3	4	5	6
1. आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	8.44 (5)	7.8 (5)	241 (10)	26.84 (7)	45.11 (12)
2. आसाम Assam	2.40 (13)	2.6 (12)	284 (8)	11.08 (16)	53.42 (10)
3. बिहार Bihar	5.30 (9)	10.2 (2)	497 (3)	13.17 (15)	38.54 (16)
4. गुजरात Gujarat	5.97 (7)	4.9 (9)	210 (12)	34.40 (2)	60.91 (5)
5. हरियाणा Haryana	1.35 (16)	1.9 (14)	369 (7)	24.79 (9)	55.33 (9)
6. हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	1.70 (14)	0.6 (16)	92 (16)	8.70 (17)	63.54 (4)
7. जम्मू एवं कश्मीर Jammu & Kashmir	6.77 (6)	0.9 (15)+	76 (17)+	23.83 (10)+	N.A.
8. कर्नाटक Karnataka	5.85 (8)	5.3 (7)	234 (11)	30.91 (4)	55.98 (8)
9. केरल Kerala	1.18 (17)	3.4 (11)	747 (2)	26.44 (8)	90.59 (1)
10. मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	13.50 (1)	7.8 (5)	149 (14)	23.21 (11)	43.45 (13)
11. महाराष्ट्र Maharashtra	9.38 (3)	9.3 (3)	257 (9)	38.69 (1)	64.87 (2)
12. उड़ीसा Orissa	4.75 (10)	3.7 (10)	202 (13)	13.43 (14)	48.55 (11)
13. पंजाब Punjab	1.54 (15)	2.4 (13)	401 (6)	29.72 (5)	57.14 (7)
14. राजस्थान Rajasthan	10.43 (2)	5.2 (8)	129 (15)	22.88 (12)	38.55 (15)
15. तमिलनाडु Tamilnadu	3.96 (11)	6.6 (6)	428 (5)	34.20 (3)	63.72 (3)
16. उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	8.97 (4)	16.4 (1)	472 (4)	19.89 (13)	41.71 (14)
17. पश्चिम बंगाल West Bengal	2.68 (12)	8.0 (4)	766 (1)	27.39 (6)	57.72 (6)
अखिल भारत All India	100.00	100.0	267	25.71	52.11

साक्षरता दर 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की जनसंख्या से सम्बंधित है।
* The literacy rates relate to the population aged 7 and above.
+ राज्य की अनुमानित जनसंख्या पर आधारित ।
Based on estimated population of state.

राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक(क्रमशः)
STATEWISE IMPORTANT ECONOMIC INDICATORS(Contd.)

राज्य STATE	औसत कृषि जोत (हैक्टेयर) Average size of holdings (Hect.) (1990-91)	प्रति व्यक्ति खाद्यानों का त्रिवार्षिक औसत उत्पादन (कि.ग्रा.) Trinnel Average Per Capita Foodgrain Production(Kg.) (1991-92 to 93-94)	बोये गये क्षेत्रफल का प्रति हैक्टेयर खाद का उपभोग (कि.ग्राम) consumption of fertilizer Per Hectare of cropped area (Kg.) (1994-95)	प्रति लाख जनसंख्या पर श्रमिकों का दैनिक औसत रोजगार (संख्या) Average daily employment of factory workers per lakh of Population (No.) 1992*	उधोगों से प्रति व्यक्ति आय वृध्दि (रूपये) Per Capita value added in industries (Rs.) (1992-93)
1	7	8	9	10	11
1. आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	1.56	172.5 (11)	121.4 (4)	932 (10)	628 (8)
2. आसाम Assam	1.31	148.8 (12)	9.5 (16)	483 (14)	358 (16)
3. बिहार Bihar	0.93	120.9 (15)	64.6 (10)	540 (13)	384 (15)
4. गुजरात Gujarat	2.93	98.6 (16)	77.5 (7)	1853 (2)	1890 (2)
5. हरियाणा Haryana	2.43	578.4 (2)	126.4 (3)	1489 (6)	943 (5)
6. हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	1.20	248.9 (4)	34.6 (14)	1014 (8)	829 (7)
7. जम्मू एवं कश्मीर Jammu & Kashmir	0.83	173.9 (10)	48.2 (11)	338 (17)	114 (17)
8. कर्नाटक Karnataka	2.13	179.8 (8)	64.9 (9)	1608 (3)	893 (6)
9. केरल Kerala	0.33	35.6 (17)	66.7 (8)	951 (9)	609 (9)
10. मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	2.63	248.5 (5)	37.4 (12)	784 (11)	571 (11)
11. महाराष्ट्र Maharashtra	2.21	147.3 (14)	64.9 (9)	1501 (5)	1943 (1)
12. उड़ीसा Orissa	1.34	218.3 (6)	22.5 (15)	423 (15)	433 (14)
13. पंजाब Punjab	3.61	918.2 (1)	174.7 (1)	1910 (1)	1408 (3)
14. राजस्थान Rajasthan	4.11	194.0 (7)	34.8 (13)	608 (12)	511 (12)
15. तमिलनाडु Tamilnadu	0.93	147.8 (13)	136.6 (2)	1513 (4)	1286 (4)
16. उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	0.90	253.2 (3)	99.3 (5)	399 (16)	453 (13)
17. पश्चिम बंगाल West Bengal	0.90	179.5 (9)	86.2 (6)	1295 (7)	597 (10)
अखिल भारत All India	1.57	202.6	75.7	988	817

* प्रावधानिक Provisional.

राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक (क्रमशः)
STATEWISE IMPORTANT ECONOMIC INDICATORS (Contd.)

राज्य STATE	प्रति व्यक्ति विद्युत् उपभोग (कि.वा.) Per Capita Consumption of electricity (kwh.)* 1993-94(P)**	कुल ग्रामो से विद्युतीकृत ग्रामो का प्रतिशत Percentage of Electrified Villages to Total Villages March 94 (P)**	प्रति लाख जनसंख्या पर मोटर गाड़ियों की संख्या Number of motor vechiles per lakh of population (31-3-1993)	प्रति हजार वर्ग किलो मीटर पर रेल मार्ग की लम्बाई (की.मी.) Railway route length per'000 Sq. of Area (Km.) (1991-92)
1	12	13	14	15
1. आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	344.17 (7)	100.00 (1)	2334 (10)	18.49 (10)
2. आसाम Assam	96.45 (17)	97.73 (2)	1386 (16)	31.45 (4)
3. बिहार Bihar	124.92 (16)	70.62 (9)	1291 (17)	30.57 (6)
4. गुजरात Gujarat	590.36 (2)	100.00 (1)	5769 (2)	26.94 (8)
5. हरियाणा Haryana	486.98 (3)	100.00 (1)	4342 (3)	33.90 (3)
6. हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	217.30 (11)	100.00 (1)	1537 (13)	4.78 (16)
7. जम्मू एवं कश्मीर Jammu & Kashmir	196.53 (13)	95.43 (3)	1853 (11)	0.35 (17)
8. कर्नाटक Karnataka	323.24 (6)	100.00 (1)	3697 (4)	15.98 (13)
9. केरल Kerala	216.52 (12)	100.00 (1)	2607 (8)	25.32 (9)
10. मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	310.20 (9)	92.81 (4)	2552 (9)	13.31 (14)
11. महाराष्ट्र Maharashtra	459.23 (4)	100.00 (1)	3604 (5)	17.68 (11)
12. उड़ीसा Orissa	318.66 (8)	70.69 (8)	1525 (14)	12.86 (15)
13. पंजाब Punjab	702.71 (1)	100.00 (1)	7343 (1)	42.89 (2)
14. राजस्थान Rajasthan	254.00 (10)	83.42 (5)	2867 (7)	17.02 (12)
15. तमिलनाडु Tamilnadu	387.36 (5)	100.00 (1)	3368 (6)	30.83 (5)
16. उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	186.39 (14)	75.43 (7)	1585 (12)	30.29 (7)
17. पश्चिम बंगाल West Bengal	163.63 (15)	75.76 (6)	1432 (15)	43.00 (1)
अखिल भारत All India	299.00	85.30	3086	19.00

P प्रावधिक Provisional   * उपयोगिता और अनउपयोगिता Utilities and Non-Utilities.

Source ** - Salient data 1993-94 Central Electricity Authority Jan., 95.

राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक
STATEWISE IMPORTANT ECONOMIC INDICATORS

राज्य STATE	प्रति लाख जनसंख्या पर बैंको की संख्या (सितम्बर,1996) No. of Banking Offices per lakh of population (Sept.,96)	प्रति व्यक्ति बैंक निषेप (रुपये) (सितम्बर,1996) Per Capita Bank Deposit (Sept.,96) Rs.	प्रति व्यक्ति बैंक साख (रुपये) (सितम्बर,1996) Per Capita Bank credit (Sept.,96) Rs.	अष्टम योजना का उदव्यय (करोड रुपये) (1992-97) 8th Plan outlay (Crore Rs.) (1992-97)	प्रचलित कीमतो पर वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक की औसत प्रति व्यक्ति राज्य आय (रुपये) Per capita State Income (at current prices) Average of 1992-93 to 1994-95 (+)(Rs.)
1	16	17	18	19	20
1. आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	6.7 (9)	3263 (11)	2494 (7)	10500 (7)	6470 (7)
2. आसाम Assam	4.9 (16)	1822 (16)	669 (16)	4662 (14)	5141 (13) *
3. बिहार Bihar	5.1 (15)	1980 (15)	594 (17)	13000 (3)	3482 (17)
4. गुजरात Gujarat	7.7 (7)	5949 (4)	2879 (6)	11500 (5)	8829 (4)
5. हरियाणा Haryana	7.4 (8)	5235 (6)	2127 (9)	5700 (12)	10563 (3)
6. हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	13.2 (1)	5653 (5)	1420 (11)	2502 (16)	6025 (10) *
7. जम्मू एवं कश्मीर Jammu & Kashmir	9.1 (5)	4845 (9)	1896 (10)	4000 (15)	4587 (15)
8. कर्नाटक Karnataka	9.2 (4)	4947 (8)	3513 (4)	12300 (4)	7227 (6)
9. केरल Kerala	9.8 (3)	6693 (3)	2995 (5)	5460 (13)	6062 (9)
10. मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	6.0 (12)	2675 (13)	1384 (12)	11100 (6)	5334 (12)
11. महाराष्ट्र Maharashtra	6.7 (9)	10832 (1)	7447 (1)	18520 (2)	11369 (2)
12. उड़ीसा Orissa	6.2 (11)	1766 (17)	909 (15)	10000 (9)	4243 (16) *
13. पंजाब Punjab	10.5 (2)	9623 (2)	3968 (3)	6570 (11)	12538 (1)
14. राजस्थान Rajasthan	6.5 (10)	2640 (14)	1144 (13)	11500 (5)	5665 (11)
15. तमिलनाडु Tamilnadu	7.8 (6)	5135 (7)	5088 (2)	10200 (8)	7280 (5)
16. उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	5.7 (14)	2936 (12)	916 (14)	21000 (1)	4799 (14)
17. पश्चिम बंगाल West Bengal	5.8 (13)	4475 (10)	2262 (8)	9760 (10)	6414 (8)
अखिल भारत All India	6.7	4890	2812	186235	7192

\+ प्रावधानिक Provisional

* प्रचलित कीमतों पर वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की औसत प्रति व्यक्ति राज्य आय (रुपये)
Per Capita State Income (at current prices) Average of 1991-92 to 1993-94. (Rs.)

राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक
STATEWISE IMPORTANT ECONOMIC INDICATORS

राज्य STATE	प्रति व्यक्ति राजस्व (रुपये) Per Capita Revenue 1996-976(B.E.) (Rs.)	प्रति व्यक्ति कर राजस्व Per Capita Tax-Revenue 1996-97(B.E.) (Rs.)	केन्द्रीय करों का प्रति व्यक्ति अंश Per Capita Share in Central Taxes 1996-97(B.E.) (Rs.)	प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय Per Capita Revenue Expenditure 1996-97(B.E.) (Rs.)	प्रति व्यक्ति विकास पर व्यय Per Capita Development Expenditure 1996-97(B.E.) (Rs.)
1	21	22	23	24	25
1. आन्ध्र प्रदेश * Andhra Pradesh	1412.92 (12)	990.87 (11)	297.62 (11)	1512.13 (13)	1020.66 (12)
2. आसाम * Assam	1561.66 (9)	735.92 (15)	396.94 (4)	1534.02 (12)	1029.13 (10)
3. बिहार * Bihar	827.52 (17)	581.49 (17)	363.45 (6)	881.59 (17)	506.57 (17)
4. गुजरात Gujarat	1961.14 (7)	1551.56 (4)	280.57 (13)	2004.96 (8)	1219.53 (7)
5. हरियाणा Haryana	2604.00 (3)	1444.65 (6)	220.37 (17)	2686.69 (2)	1396.02 (4)
6. हिमाचल प्रदेश * Himachal Pradesh	3041.97 (2)	1390.91 (7)	797.85 (1)	3285.77 (1)	2118.14 (1)
7. जम्मू एवं कश्मीर* Jammu & Kashmir	3474.13 (1)	1061.56 (9)	748.35 (2)	2683.99 (3)	1565.11 (2)
8. कर्नाटक Karnataka	2148.00 (5)	1622.52 (2)	344.90 (8)	2175.79 (7)	1456.16 (3)
9. केरल Kerala	1910.38 (8)	1516.13 (5)	369.44 (5)	2273.93 (5)	1387.17 (5)
10. मध्य प्रदेश* Madhya Pradesh	1269.98 (14)	743.13 (14)	297.46 (12)	1335.19 (14)	870.63 (14)
11. महाराष्ट्र Maharashtra	2130.21 (6)	1616.40 (3)	236.07 (16)	2268.69 (6)	1211.48 (8)
12. उड़ीसा Orissa	1357.65 (13)	858.40 (12)	449.16 (3)	1582.34 (11)	964.69 (13)
13. पंजाब Punjab	2324.27 (4)	1800.59 (1)	237.18 (15)	2554.19 (4)	1246.53 (6)
14. राजस्थान Rajasthan	1521.98 (11)	1009.31 (10)	345.69 (7)	1595.39 (10)	1021.34 (11)
15. तमिलनाडु * Tamilnadu	1537.91 (10)	1283.58 (8)	308.91 (10)	1722.01 (9)	1151.77 (9)
16. उत्तर प्रदेश * Uttar Pradesh	989.22 (16)	681.70 (16)	339.70 (9)	1196.80 (16)	589.16 (16)
17. पश्चिम बंगाल * West Bengal	1067.91 (15)	817.79 (13)	274.27 (14)	1309.62 (15)	817.29 (15)

कोष्ठीय संख्या राज्य की श्रेणी को दर्शाती है ।
Figure with in brackets denotes State Rankings.
आंकड़े वर्ष 1995-96 से सम्बंधित है।
* Figures relates to year1995-96

Economic Review
1996-97

KEY INDICATORS OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Particulars	Unit	1993-94	1994-95	1995-96	1996-1997 (provi-sonal)
1	2	3	4	5	6
1. Gross Domestic Product	Rs.in Crores				
(a) At current Prices		28342	34978	38598	44881
(b) At constant (1980-81) Prices		9492	11174	11273	12420
2. Economic Growth Rate as per GSDP	Percent				
(a) At current Prices		4.08	23.41	10.35	16.28
(b) At constant (1980-81) Prices		(-)6.87	17.72	0.89	10.17
3. Percentage Contribution of GSDP at Constant (1980-81) prices by	Percent				
(a) Primary		40.32	44.35	41.51	43.85
(b) Secondary		23.46	21.74	23.15	22.46
(c) Other service sector (Tertiary)		36.22	33.91	35.34	33.69
4. Net State Domestic Product	Rs. in Crores				
(a) At current Prices		24596	30641	33705	39460
(b) At constant (1980-81) Prices		8329	9917	9936	11021
5. Per Capita Income	Rs.				
(a) At current Prices		5287	6452	6958	7992
(b) At constant (1980-81 Prices		1790	2088	2051	2232
6. Index for Agricultural Production (Base 1979-82=100)	Index	156.59	228.80	211.77	N.A.
7. Total Foodgrain Production	Lakh Tonnes	70.55	117.10	95.66	127.02

SELECTED KEY INDICATORS

GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT

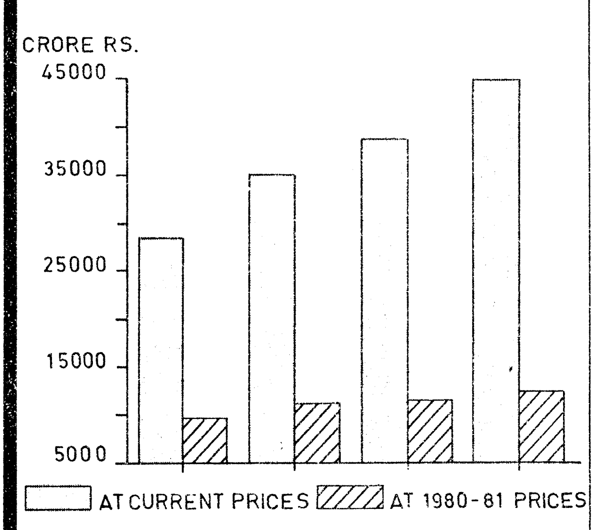

POWER PRODUCTION

(GENERATION & PURCHASE)

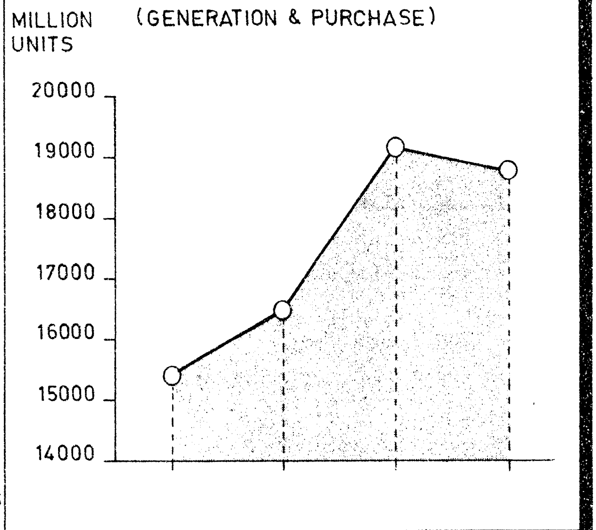

BROAD SECTORS AS A PERCENTAGE OF GSDP

AT (1980-81) PRICES

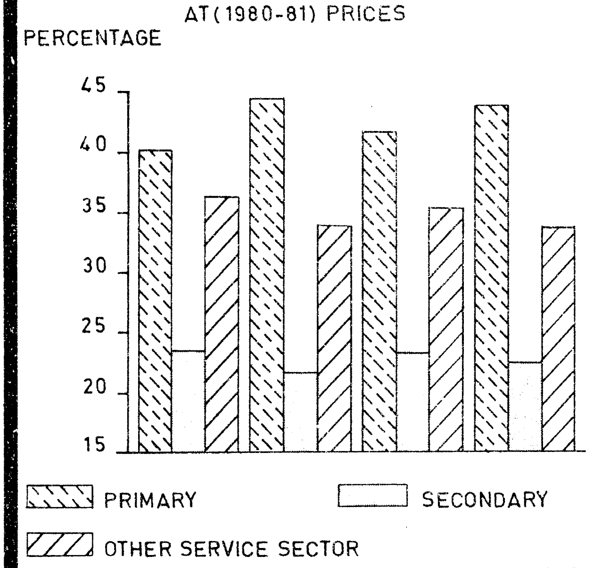

GENERAL WHOLESALE PRICE INDEX

(BASE 1952-53=100)

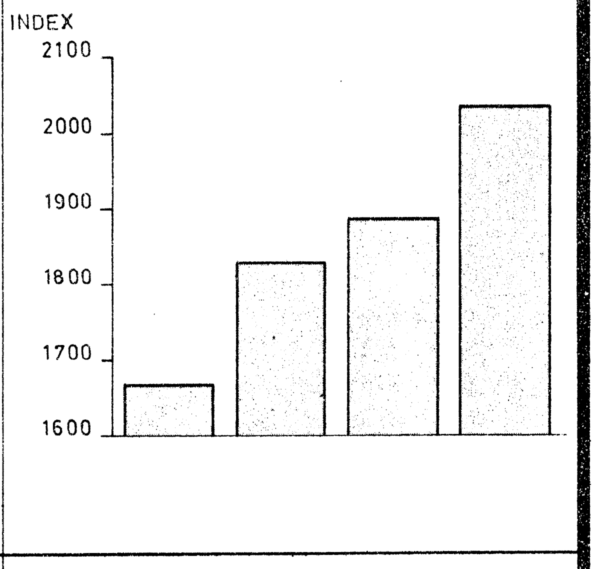

TOTAL FOODGRAIN PRODUCTION

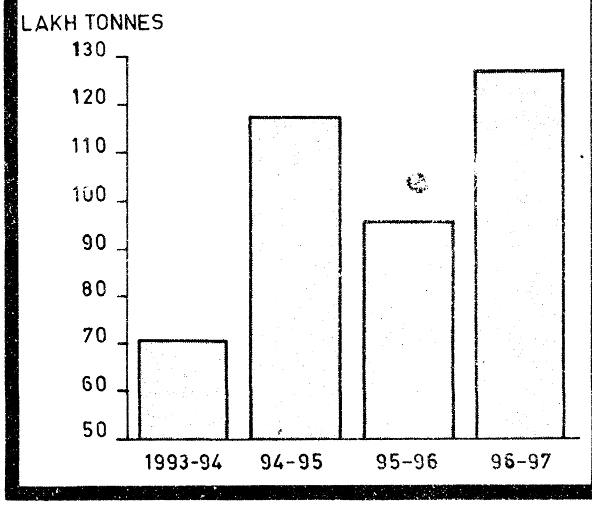

SCHEDULED COMMERCIAL BANK CREDIT

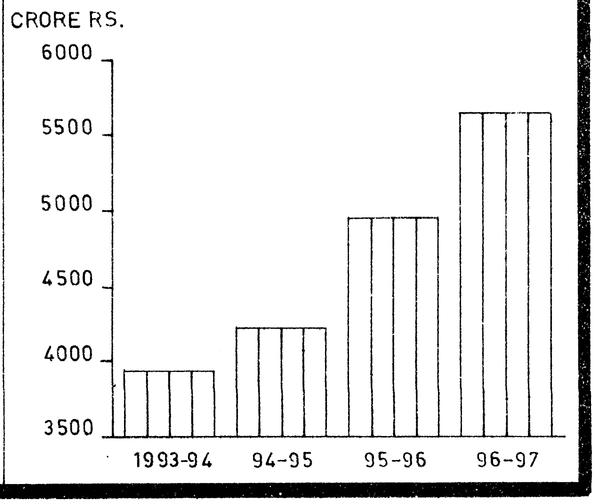

1	2	3	4	5	6
8. Index for Industrial Production of Manufacturing (Base 1970=100)	Index	309.86	316.44	327.03	Under preparation
9. General Wholesale Price Index (Base 1952-53=100)					
(a) Index Number	Index	1668.7	1827.61	1885.77	2038.82
(b) Percentage Increase		2.83	9.52	3.18	8.12
10. General Consumer Price Index Number for Industrial Workers (Base 1982=100)					
(a) Jaipur Centre	Index	245	269	291	321
(b) Ajmer Centre		253	280	305	332
11. Power Production (Generation + Purchase)	In million unit	15399.97	16423.50	19171.24	18727.65
-Percentage increase	Percent	5.00	6.65	16.73	(-)2.31
12. Commercial Bank credit (Upto September)	Rs. in Crores	3912.00	4210.00	4955.00	5650.00
-Percentage increase	Percent	11.55	7.62	17.70	14.03

+ WPI/CPI are related with calender year.

N.B.: In case of Gross Domestic Product, Economic Growth Rate as per GSDP and Percentage contribution of GSDP at Constant (1980-81) Prices data is provisional for 1993-94 and 1994-95, quick estimates for 1995-96 and advance estimates for 1996-97.

*****

PER CAPITA INCOME

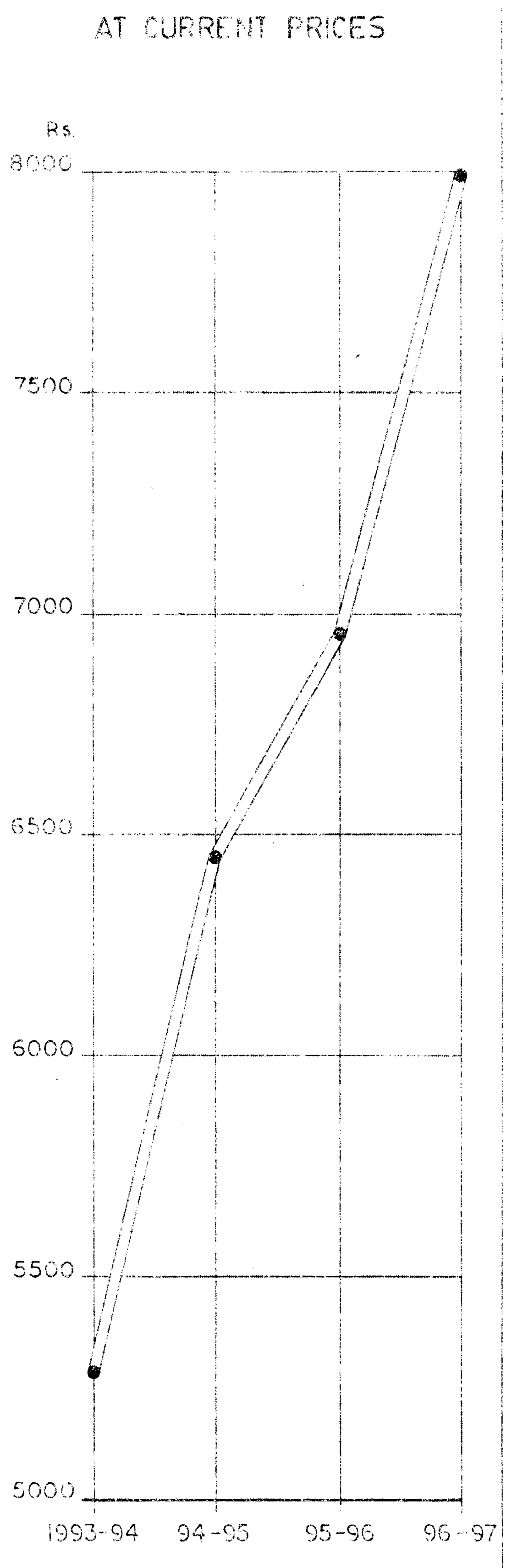

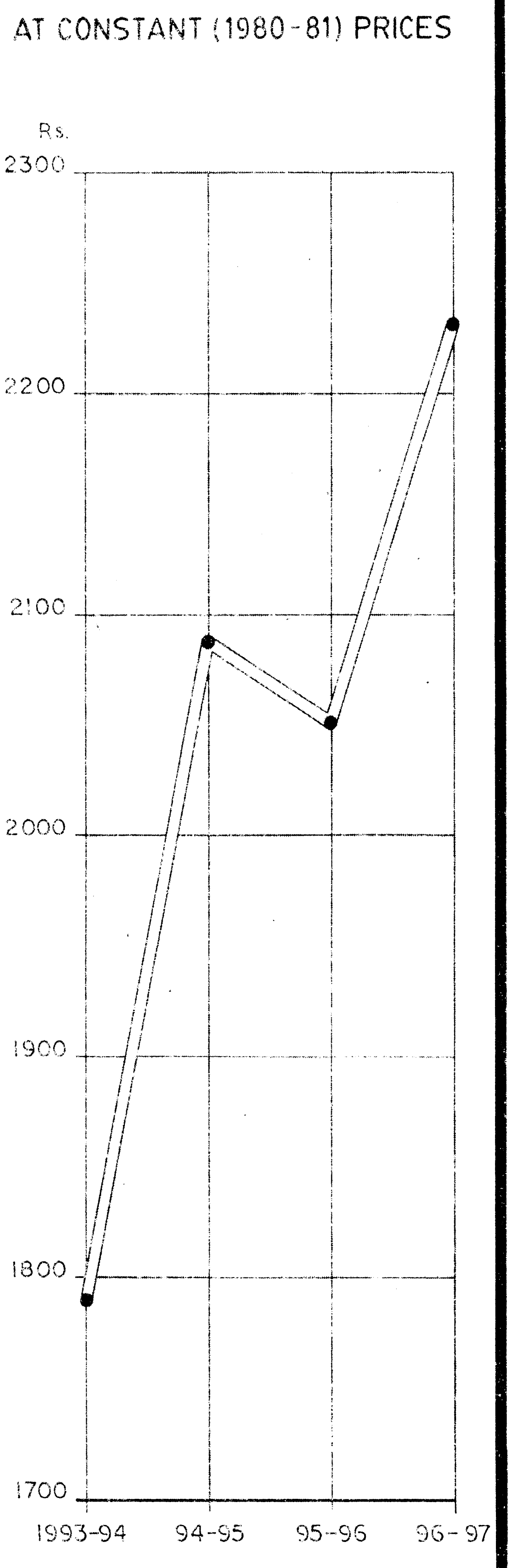

1. GENERAL REVIEW 1996-97

MACRO ECONOMIC OVERVIEW:

Rajasthan is situated in the north western part of India and shares geographical boundaries with the states of Punjab, Haryana, Utter Pradesh, Madhya Pradesh and Gujarat. It also has a long international border with Pakistan. Rajasthan is the second largest State in the Country after Madhya Pradesh, having 3.42 lakh Sq.kms. area. Administratively, Rajasthan State is divided into 31 districts which are further sub-divided into 100 sub division and 229 tehsils.

The salient features of Rajasthan are given in the table below:-

Table - 1.1

Items	Year	Unit	Particulars
1. Area	1991	Lakh sq.km.	3.42
2. Districts	1996	Number	31
3. Sub-Divisions	1996	Number	100
4. Tehsils	1996	Number	229
5. Zila Parishads	1996	Number	31
6. Panchayat Samities	1996	Number	237
7. Village Panchayats	1996	Number	9185
8. Total Villages	1991	Number	39810
9. Inhabited Villages	1991	Number	37889
10. Towns	1991	Number	222

The topography of Rajasthan is dominated by the Aravali range of mountains, one of the oldest mountain systems in the world. Aravali hill range

runs through the heart of the State; extending for 692 km. Besides, a large area of the State is covered under desert.

As per 1991 Census the population of the State is 4.40 crores and in comparison to National population, state's population is 5.20 percent. The population of scheduled castes and scheduled tribes is 17.29 percent and 12.44 percent respectively of the state's total population, as against the National average of 16.33 percent and 8.01 percent.

The population of the State has been increasing at a faster rate. The growth rate of population in the state had been higher than that of the Country. Decennial growth of population in Rajasthan as well as in India is depicted below:-

Table 1.2

Year	Population (Lakh Nos.)		Decennial Growth	
	Rajasthan	India	Rajasthan	India
1951	160	3611	15.20	13.31
1961	202	4392	26.20	21.51
1971	258	5482	27.83	24.80
1981	343	6843	32.97	24.66
1991	440	8463	28.44	23.56

Further there is large variation in the density of population with in the State from area to area. While the state average is 129 persons per sq. km., it is 84 persons per sq. km. in desert areas and 203 persons in other areas.

Rajasthan is an unusually diverse State. The region to the West and North-West comprising of 11 districts and having 61.11 percent of the total area is known as Great Indian Desert "THE THAR", carrying 39.79 percent of its population. The tribal area in the South constitutes 5.85 percent of State's land mass and has 8.00 percent of its

population. The other remaining area i.e. 33.04 percent habitats 52.21 percent of the total population.

The climate of the State in general is characterised as driest in the country and having a large variation. The rainfall in the State is not only meager but it also varies year to year and creates drought conditions. The average rainfall is 58.64 cms. but in arid and semi-arid areas, it is very low.

Rajasthan is predominantly an agrarian State. Agriculture plays an important role in the State's economy as more than 40 percent of the total State Income is generated by agriculture and allied activities. Irrigation is an essential input for agriculture production. The surface water resources in the State are scarce. The ground water table, owing to scanty and erratic rainfall, is getting deeper and deeper. Agriculture, thus, is still dependent on vagaries of monsoon. A great emphasis is being continuously given on augmentation of the agriculture production in the State.

The year 1996 witnessed some delayed but good rains through out the State, raising expectations of a bumper production of foodgrains and oilseeds during 1996-97. Total foodgrain production is estimated to be 127.02 lakh tonnes in 1996-97 as compared to 95.66 lakh tonnes in 1995-96. Oilseed production is likely to achieve the highest level of 40.94 lakh tonnes during 1996-97, surpassing all the earlier records.

Water is indeed a critical resource on account of the fact that the State, which occupies 10.40 percent of the country's geographical area, is endowed with only 1.04 percent of the total surface water resources of the country. However, the Government is striving hard to enhance water availability for diverse uses. The stress is being laid on efficient water utilisation by adopting water saving devices in agriculture as well as in other fields. Other strategy adopted by the State relates to utilisation of its share in Inter-State waters.

Water is now available in Sri Ganganagar, Hanumangarh, Bikaner, Jaisalmer and Jodhpur districts from Indira Gandhi Nahar. Chambal water covers areas of Kota, Baran, Bundi & Sawai Madhopur districts. Water availability in Banswara district has increased due to commissioning of Mahi Bajaj Sagar Project. Yamuna water is now available in the eastern part of the State and Narmada water would benefit areas of Jalore & Barmer districts.

The State Government has formulated an Industrial Policy, 1994 which helped in creating better investment opportunities in the State. The policy provides an attractive package of incentives and concessions to new entrepreneurs.

A number of measures like improving investment climate, simplifying rules and procedures, ensuring speedy inputs, increasing role of private sector in infra-structural development and providing encouragement to employment oriented investment as well as to rural industries, etc. have been taken up for rapid industrial development in the State. As a result, 182828 small scale units including artisan units have so far been registered with an investment of Rs. 1920.38 crores and providing employment to 7.08 lakh persons.

The Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation (RIICO) is engaged in promoting industrialisation in the State by developing industrial areas and providing financial assistance by way of term loan, equity participation and investment subsidy etc. The Technology Park, Software Technology Park and Leather Complexes in Jaipur district , Leather Complex Bharatpur, Textile City Bhilwara etc. are being developed. Under infrastructural development, during the year 1996-97, land measuring 2658 acres has been acquired up to December '96 against the annual target of 2300 acres. Besides, 1175 industrial plots have been developed and 456 industrial plots allotted by RIICO up to December '96.

The industrial scene in the State has changed considerably. The industrial production has not only increased but also diversified over

the year. The State is now, not only a producer of a wide range of products such as synthetic yarn, cement, T.V. picture tubes, chemicals and fertilizers, but also the sophisticated electronic items and even an exporter of variety of goods.

Rajasthan has acquired a special position in the field of mines and minerals. The State is geologically endowed with wide range of depository of minerals. Important minerals with which the name of the State is intimately associated are that of non-ferrous metals like lead, zinc and copper and for ferrous metals such as tungsten and various other minerals.

In the field of minor minerals particularly of dimensional and decorative stones such as marble, Kota stone and sand-stone, the State occupies a unique position by contributing about 30 percent of the total value of minor minerals being produced in the country.

The Mineral Policy, declared by the State Government in 1994 with a view to explore mineral wealth of the State more expeditiously by adopting modern exploration techniques particularly in the tribal and remote areas. Under the New Mineral Policy, employment opportunities in the mining sector particularly for the persons belonging to scheduled castes, scheduled tribes and other weaker sections have increased.

The State Mines & Geology Department and the Rajasthan State Mineral Development Corporation (RSMDC) and the Rajasthan State Mines and Minerals Ltd. (RSMM) are functioning for speedy and scientific exploration of mineral resources in the State.

Power is an essential input to all productive economic activities. The development of power sources is highly capital intensive and very large investment is required for meeting the demand of power. Hence, power has always been accorded the highest priority in State's plans. In the Eighth Five Year Plan, about 28.31 percent of total plan outlay has been earmarked for this sector.

Looking to the move towards an open market economy, based on competitiveness and international outlook, private participation is being encouraged in the field of power generation. Lignite reserves of the State have been opened up for private sector investment.

Under Rural Electrification Programme, 34015 villages (as per 1991 Census) have been electrified upto December, 1996 which is 89.77 percent of the total inhabited villages. Besides, 5.26 lakh wells have also been energised in the State.

Under non conventional sources of energy installation of Solar Power Pack, strengtheing of SPV Street lights, installation of SPV pumps, Solar water heating system and wind energy etc. are being developed by the Rajasthan Energy Development Agency (REDA). A programme for electrification of 50 villages through solar power pack has also been taken up during the year 1996-97.

A well developed network of transport and communication is a basic infrastructure for rapid economic development. Rajasthan is an under developed State in terms of transport and communications. In the absence of internal waterways and inadequate expansion of railways, roads provide a major infrastructural link in the State.

Recognising the importance of a good road communications network, a policy on Road Development has been adopted in the State. The total road length in the State which was 17339 Kms. in 1950-51, increased to 134449 Kms. (inclusive other departmental roads) during 1995-96 and is likely to reach a level of 137949 by the end of 1996-97. The total road density in the State which was 39.29 Kms. per hundred sq.kms. at the end of 1995-96 (inclusive other departmental roads) is expected to be 40.31 Kms. at the end of 1996-97. It is still much below the national average of 62.1 Kms. per hundred sq. Kms.

The State is poised towards taking a major leap forward with the on-going and proposed programme of conversion of meter-gauge railway

lines into broad-gauge. Jaipur, the capital city of Rajasthan has already been linked with Mumbai, Delhi, Calcutta and Chennai. Jodhpur and Bikaner have also been brought on the broad-gauge network. It has offered a great facility for development of industries and minerals in the State. A major track renewal programme to convert existing meter gauge routes to broad-gauge is under implementation at several places in the State.

Rajasthan is becoming one of the most important tourist attraction centre for both Indian and foreign tourists. Rajasthan with its rich and varied cultural heritage historical as well as archaeological wonders and rare wild life has a unique place in the world map of tourism. Due to the unique attraction, State tourism is an important economic activity in the State and continuous efforts are being made for increasing the tourist traffic. ourist traffic in Rajasthan which was 33 lakhs in 1983 increased to 57.82 lakh during 1995 which includes 5.34 lakh foreign tourists.

Movement of prices of various commodities has a significant impact both on the economy of the State and life of the people. Changes in the level of wholesale and retail prices at specific intervals, are revealed through Wholesale Price Index Numbers and Consumer Price Index Numbers for industrial workers. During 1996, a rising trend has been visible in both wholesale and retail prices over 1995 in the State. The Wholesale Price Index (base 1952-53 = 100) during the year 1996 stood at 2038.82 as against 1885.77 of 1995, which reveals an increase by 8.12 percent.

The State's Eighth Five Year Plan allocation amounts to Rs. 11500 crores, which is 283 percent more than the size of the Seventh Plan. This outlay is nearly equal to that of Gujarat and more than that of Punjab, Orissa, Madhya Pradesh, Tamil Nadu etc.

The per capita plan outlay during the Eighth Five Year Plan has increased to Rs. 2614 from Rs. 875 in Seventh Plan. Further, the per capita outlay in the State during Eighth Plan is higher than the States like Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh.

An amount of Rs. 8728.28 crores has been spent during first four years (1992-93 to 1995-96) of Eighth Five Year Plan. Further, likely expenditure for annual plan 1996-97 is Rs. 3310.49 crores. Thus the total expenditure during Eighth Plan period would be over Rs. 12000 crores against the plan size of Rs. 11500 crores.

Credit through banks is an important source for investment and development. Banks are actively involved in the implementation of the various programmes like NRY, PMRY, IRDP, RSCDC, SUME schemes etc. The expansion of bank branches, particularly the regional rural banks has helped in execution of various rural development programmes.

The bank population ratio indicates that there was one bank office for a population (1991 census) of 13677 in Rajasthan as on September, 1996. The position of area coverage per bank office was 106 sq.kms.in the State.

State Domestic Product and the per capita income reflect overall performance of the State's economy during a given period. Growth in State Domestic Product is largely dependent upon the agriculture production. The State Domestic Product, thus is subjected to wide fluctuations depending on the monsoon conditions.

Yearwise net state domestic product (NSDP) and per capita income (PCI) since 1991-92 onwards on constant (1980-81) and current prices are depicted below :-

Table 1.3

Year	On Constant Prices		On Current Prices	
	NSDP (Crore Rs.)	P.C.I. (Rs.)	NSDP (Crore Rs.)	P.C.I. (Rs.)
1991-92	7850	1761	20044	4497
1992-93	9078	1993	23944	5257
1993-94 *	8329	1790	24596	5287
1994-95 P	9917	2088	30641	6452
1995-96 Q	9936	2051	33705	6958
1996-97 A	11021	2232	39460	7992

* Drought year, P-Provisional, Q-Quick, A-Advance

It is evident from the above table that the net State domestic product (NSDP) popularly known as "State Income" has been manifesting an upward trend over the years except 1993-94, which was a drought year. Yet, the fast increase in population has neutralised it's most of the impact, thus the per capita income has been witnessing a low percentage increase in comparison to N.S.D.P.

As per advance estimates, Net State Domestic Product at constant (1980-81) prices works out to Rs. 11021.40 crores for 1996-97 as compared to Rs. 9935.97 crores during 1995-96, showing an increase of 10.92 percent over the previous year. Per Capita Income at constant (1980-81) prices works out to Rs. 2232 for the year 1996-97 as compared to Rs. 2051 for 1995-96 indicating an increase of 8.83 percent.

As per advance estimates Net State Domestic Product at current prices works out to Rs. 39460.24 crores for 1996-97 as compared to Rs. 33705.33 crores during 1995-96, showing an increase of 17.07 percent. Per capita income for the year 1996-97 at current prices works out to Rs. 7992 as against Rs. 6958 during 1995-96, showing an increase of 14.86 percent.

Continuous efforts are being made for development of education in the State. Universalisation of primary education, expansion of educational facilities with more stress on girls education etc. remained the thrust areas during the year 1996-97. Free education upto the college level is being provided to girls in the State.

The Directorate of Adult Education of the State is adopting the Total Literacy Campaign as the dominant strategy since the year 1990, under the guidelines of National Literacy Mission.

Elementary Education is a part of Minimum Needs and 20-Points Programme. The "Lok Jumbish" and "Shiksha Karmi Project" and "Guru Mitra Yojana" are being implemented in the State with a view to attain proper coordination between formal and non-formal education. For encouraging the girls education "SARASWATI YOJNA" through educated women is being implemented in the rural areas of

the State. For increasing the enrolment and retaining the students at elementary education level. Free Text Book Distribution Scheme for girls studying in class I to VIII and for boys studying in class I to V is being implemented in the State. Under this scheme, 58.50 lakh students have been benefited during 1996-97.

Towards the objectives of "Health for all by 2000 A.D.", considerable efforts have been made through strengthening and expanding the health care system. As a result, the general health condition of the people of the State, has shown improvement. The life expectancy has increased from 46.8 years in 1961 to about 61 years (1991-96). Death and Birth rate have also declined. Smallpox has been completely eradicated. Other epidemic and communicable diseases have been controlled to a great extent in the State.

Concerted efforts are being made to solve the drinking water problem in both rural and urban areas of the State. 37274 villages have been covered with safe water supply. During 1996-97 (upto December, 1996), safe drinking water facility provided to 92 main habitations and 2690 other habitations. 553 partially covered villages have been fully covered.

About 77 percent of total population of the State resides in rural areas. Poverty, malnutrition, inadequate employment and lack of infrastructural facilities in rural areas are the major problems. Continuous efforts are being made to alleviate rural poverty, by providing additional employment opportunities through creation of rural infrastructure under various programmes like IRDP, TAD, DDP, DPAP, JRY etc. which are being implemented through the District Rural Development Agencies.

Besides, various other programmes like Apna Gaon Apna Kaam, Tees Zile Tees Kaam and DWCRA etc. are also being implemented for overall rural development of the State.

During the year 1996-97, upto December, 1996, 28437 families have been benefited under Integrated Rural Development Programme and 2261 rural youth were trained for self employment under TRYSEM scheme.

Under Jawahar Rojgar Yojana 79.82 lakh mandays employment was generated upto December, 1996 during the current year.

Public Distribution System has been working through a network of fair price shops, both in rural and urban areas in the State to provide essential commodities at reasonable prices fixed by the Government. A total number of 17963 fair price shops were functioning by the end of December, 1996 in the State.

Under the Consumer Protection Act 1986, consumers protection forums at State level as well as district level are functioning for safe-guarding the consumer's interest.

*****

2. STATE DOMESTIC PRODUCT AND FINANCE

2.1 STATE DOMESTIC PRODUCT

Estimates of State Domestic Product are one of the important economic indicators to measure the economic development of a State.

The per capita State Domestic Product is used to determine both the absolute and relative performance of the economy of the State. It is regarded as an important tool to measure the regional disparities as well. It is also used by policy makers like Planning Commission and Finance Commission for allocation of plan resources and distribution of taxes and duties to different states.

In the present analysis the estimates of State Domestic Product have been given both at constant (base 1980-81) and current prices. The estimates of S.D.P. at constant prices reflect the production effects on the economy, while the estimates at current prices depict the combined effect of production and prices. The estimates for the year 1996-97 are advance and tentative, based on likely production trend as observed in the economy and projections. Hence these should be used carefully.

GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT (G.S.D.P.)

Broadly, sum of the products of all goods and services rendered by the State in monetary terms, during a year before making any provision for Consumption of Fixed Capital (C.F.C.) is known as Gross State Domestic Product.

The composition of Gross State Domestic Product by broad sectors of economy from 1992-93 onwards at

constant (1980-81) prices is depicted in the following table:-

Table - 2.1.1

GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT AT CONSTANT (1980-81) PRICES

(Rs. in crores)

Year	Primary: Agriculture including animal husbandry	Primary: Total	Secondary: Manufacturing	Secondary: Total	Tertiary	Total (GSDP) Col. 3+5+6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1992-93	4293.27	4692.69	1162.90	2094.23	3405.46	10192.38
	(42.12)	(46.04)	(11.41)	(20.55)	(33.41)	(100.00)
1993-94	3385.56	3826.91	1198.32	2226.43	3438.24	9491.58
	(35.67)	(40.32)	(12.62)	(23.46)	(36.22)	(100.00)
1994-95	4435.81	4956.02	1326.13	2429.73	3788.71	11174.46
(P)	(39.70)	(44.35)	(11.87)	(21.74)	(33.91)	(100.00)
1995-96	4202.29	4679.39	1409.89	2610.11	3983.95	11273.45
(Q)	(37.28)	(41.51)	(12.51)	(23.15)	(35.34)	(100.00)
1996-97	4945.66	5445.79	1519.87	2789.23	4184.84	12419.86
(A)	(39.82)	(43.85)	(12.24)	(22.46)	(33.69)	(100.00)

P- Provisional Q- Quick A- Advance

The above table reveals that the Gross State Domestic Product of the State in real terms is continuously increasing over the years except in 1993-94, which was a drought year and agricultural production was adversely affected.

As per advance estimates, the Gross State Domestic Product (GSDP) for 1996-97 at constant (1980-81) prices is worked out to Rs. 12419.86 crores in comparison to Rs. 11273.45 crores for the year 1995-96, thus registering an increase of 10.17 percent.

NET STATE DOMESTIC PRODUCT (N.S.D.P.)

Net State Domestic Product is arrived at after deducting the value of Consumption of Fixed Capital (CFC) or depreciation from Gross State Domestic Product.

The Net State Domestic Product (NSDP) at current prices for the year 1995-96 estimated at Rs. 33705.33 crores as compared to Rs. 30641.03 crores in 1994-95, thus registering an increase of 10.00 percent. As per advance estimate for the year 1996-97, it works out Rs. 39460.24 crores registering an increase of ~~10.86~~ 17.07 percent over the previous year.

The Net State Domestic Product at constant (1980-81) prices, in 1995-96 was estimated at Rs. 9935.97 crores as against Rs. 9916.86 crores during 1994-95. As per advance estimates for the year 1996-97, it is estimated to Rs. 11021.40 crores, registering an increase of 10.92 percent over the previous year.

SECTORAL COMPOSITION

The composition of Net State Domestic Product by broad sectors of economy from 1992-93 and onwards at constant (1980-81) prices is as follows:-

Table - 2.1.2

NET STATE DOMESTIC PRODUCT AT CONSTANT (1980-81) PRICES

(Rs. in crores)

Year	Primary		Secondary		Tertiary	Total (NSDP)
	Agriculture including animal husbandry	Total	Manufacturing	Total		Col. 3+5+6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1992-93	4027.10	4354.31	945.50	1683.97	3039.95	9078.23
	(44.36)	(47.96)	(10.42)	(18.55)	(33.49)	(100.00)
1993-94	3112.76	3472.08	970.78	1790.52	3065.98	8328.58
	(37.37)	(41.69)	(11.66)	(21.50)	(36.81)	(100.00)
1994-95 (P)	4156.21	4573.07	1075.74	1956.60	3387.19	9916.86
	(41.91)	(46.11)	(10.85)	(19.73)	(34.16)	(100.00)
1995-96 (Q)	3915.73	4289.02	1143.74	2087.24	3559.71	9935.97
	(39.41)	(43.17)	(11.51)	(21.01)	(35.82)	(100.00)
1996-97 (A)	4651.96	5041.62	1234.27	2249.01	3730.77	11021.40
	(42.21)	(45.74)	(11.20)	(20.41)	(33.85)	(100.00)

P- Provisional Q- Quick A- Advance

It is evident from the above table that N.S.D.P. has been manifesting an upward trend over years except during 1993-94 which was a drought year. Some other characteristics of the N.S.D.P. are depicted below:-

(i) Primary sector including agriculture, animal husbandry, forestry, fishing, mining & quarrying still continues to dominate State's economy as nearly 42 to 48 percent value added is generated by this sector in the State. Further agriculture (including animal husbandry) alone contributes near about 90 percent value added of primary sector.

(ii) The secondary sector includes manufacturing, utilities (electricity, gas and water supply) and construction sector. The share of this sector to NSDP fluctuates in between 19 to 21 percent.

(iii) The tertiary sector includes transport, communication, trade , hotels & restaurants, banking & insurance, real-estate, ownership of dwelling, business services, public administration and other services. The share of tertiary sector to NSDP lies in between 33 to 37 percent.

PER CAPITA INCOME

Per Capita Income is derived at after dividing the Net State Domestic Product by the total population of the State.

As per advance estimates, the per capita income for the year 1996-97 at current prices is estimated to Rs. 7992, registering an increase of 14.86 percent over previous year, which was Rs. 6958 during 1995-96.

The per capita income at constant (1980-81) prices has increased from Rs. 2051 during 1995-96 to Rs. 2232 in 1996-97, registering an increase of 8.83 percent.

2.2 **EIGHTH PLAN AND ANNUAL PLAN 1996-97**

An amount of Rs. 8728.28 crores has been spent during the first four years of Eighth Plan period i.e. 1992-93 to 1995-96 against the Eighth Plan outlay of Rs. 11500 crores.

Broad sectorwise allocations for Eighth Plan, expenditure incurred during the years 1992-93 to 1995-96 are given in the following table:-

Table - 2.2.1

PLAN OUTLAY AND EXPENDITURE

(Rs. in crores)

S.No.	Sector	Eighth Plan outlay (1992-97)	Expenditure during			
			1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6	7
1.	Agriculture and Allied Services	1286.92 (11.19)	128.24 (9.12)	161.00 (9.23)	240.21 (9.94)	306.75 (9.70)
2.	Rural Development	1021.75 (8.88)	100.80 (7.17)	116.67 (6.69)	180.54 (7.47)	242.00 (7.65)
3.	Special Area Programme	84.00 (0.73)	1.10 (0.08)	1.52 (0.09)	3.45 (0.14)	4.54 (0.14)
4.	Irrigation& Flood control	1919.99 (16.70)	263.00 (18.70)	288.34 (16.54)	381.13 (15.78)	441.18 (13.95)
5.	Power	3255.49 (28.31)	395.60 (28.12)	499.60 (28.66)	651.39 (26.97)	816.77 (25.83)
6.	Industry & Minerals	536.02 (4.66)	82.15 (5.84)	88.12 (5.05)	127.64 (5.28)	161.78 (5.12)
7.	Transport	783.97 (6.82)	80.39 (5.71)	142.60 (8.18)	178.62 (7.40)	254.84 (8.06)
8.	Scientific Services	19.96 (0.17)	2.93 (0.21)	3.31 (0.19)	3.91 (0.16)	3.54 (0.11)

1	2	3	4	5	6	7
9.	Social & Community Services	2461.62 (21.41)	330.89 (23.52)	412.81 (23.68)	606.51 (25.11)	867.54 (27.43)
10.	Economic Services	71.72 (0.62)	8.87 (0.63)	11.54 (0.66)	17.72 (0.73)	20.93 (0.66)
11.	General services	58.56 (0.51)	12.70 (0.90)	17.93 (1.03)	24.63 (1.02)	42.55 (1.35)
	Total	11500.00 (100.00)	1406.67 (100.00)	1743.44 (100.00)	2415.75 (100.00)	3162.42 (100.00)

During 1996-97 the expenditure is expected to be Rs. 3310.49 crores, including the provision made for basic minimum services. With this, the expenditure during Eighth Plan Period would be over Rs. 12000 crores, against the outlay of Rs. 11500 crores.

2.3 BANKING

Rapid economic growth in the country has improved the quality of life for a larger number of people but still poverty remains a major problem needing urgent attention. Difficult geographical conditions, in which the State is placed, makes the task of development more daunting. Rising expectation of the people cannot be met with the meagre resources of the State alone and that among others, the flow of institutional finance and credit needs to be harnessed effectively.

The State Government has been making strenuous efforts through plan development to strengthen infrastructure and to develop human resources over the years. However, the gap in average per capita income at the National and State levels still continues. To accelerate the pace of development, the banks have a vital role to play in providing resources for generating additional economic activities and incomes for the people.

Credit through banks is an important source of investment and development in the State. Various credit based programmes like NRY, PMRY, IRDP, SUME schemes for development of SC / ST and other poverty alleviation programmes are being implemented with the active involvement of banks. The expansion of bank branches, particularly the Regional Rural Banks has helped in execution of various rural development schemes by providing credit support and thus fulfilling the national cause of upliftment of the weaker sections living below the poverty line. The comparative position of bank branches, their deposits and credit allowed in Rajasthan vis-a-vis at national level upto September, 1996 is presented in the table given below :-

Table - 2.3.1 (September)

S.No.	Items	Rajasthan		India	
		1995	1996	1995	1996
1	2	3	4	5	6
1.	Regional Rural Banks				
a)	No.of offices (No.)	1069	1070	14528	14508
b)	Deposits (crore Rs.)	727	908	11542	18055
c)	Credit (crore Rs.)	302	355	6565	8967
2.	Other Scheduled Commercial Banks				
a)	No.of offices (No.)	2114	2147	48095	48689
b)	Deposits (crore Rs.)	10387	12129	380269	439659
c)	Credit (crore Rs.)	4653	5295	228700	254189
3.	Total				
a)	No. of offices (No.)	3183	3217	62623	63197
b)	Deposits (crore Rs.)	11114	13037	391811	457714
c)	Credit (crore Rs.)	4955	5650	235265	263156

It is revealed from the above table that both the total deposits and credit have increased during 1996 (up to September) over the

corresponding period in the previous year i.e. upto September, 1995. The deposits have increased by 17.30 percent in Rajasthan in 1996 over 1995, while it was 16.82 percent at all India level during the same period. The credit deposit ratio was 43.34 percent in September, 1996 in Rajasthan, and at all India level it was 57.49 percent, whereas in September, 1995 it was 44.50 percent and 60.04 percent in Rajasthan and at India level respectively. Total credit percentage in Rajasthan upto September, 1996 over corresponding period of 1995 has increased by 14.02 percent while it was 11.85 percent at All India level.

One bank office is catering the needs of 13677 persons (as per 1991 Census) in Rajasthan as on September, 1996 while one bank office is covering 106 sq. Kms of area.

*****

3. PRICES AND PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM

Price stability is essential for sustaining the momentum of growth and ensuring proper distribution of benefits. Inflation hurts the poor the most since their income is not indexed to prices. Inflationary pressures in the economy are reflected by Wholesale Price Index Numbers as well as Consumer Price Index Numbers.

3.1 WHOLESALE PRICE INDEX NUMBERS (1952-53=100)

The Wholesale Price Index during the year 1996 stood at 2038.82 as against 1885.77 in 1995 revealed, an increase by 8.12 percent over previous year. The Price Index of Fuel, Power, Light and Lubricants Group witnessed the highest increase by 22.38 percent on a point-to-point basis, followed by Food Group 7.90 percent, Manufacturing Group by 6.02 percent and Industrial Raw Material Group by 4.32 percent.

The Wholesale Price Index Numbers increased through out the year during 1996 except in the months of January and December. During these months index decreased by 2.12 percent and 1.10 percent respectively over previous month. The general index, however, exhibited an upward trend during the year 1996. The percentage variation in the Wholesale Price Index Numbers under major commodities groups during 1995 and 1996 over the previous year is given in the following table:-

WHOLESALE PRICE INDEX NUMBERS

Table - 3.1.1 (Base 1952-53 = 100)

S.No.	Major Groups	Annual Average			% Variation over last year	
		1994	1995	1996	1995	1996
1	2	3	4	5	6	7
1.	Food Group	1771.80	1803.71	1946.26	1.80	7.90
2.	Industrial Raw Material Group	1660.80	1888.73	1970.26	13.72	4.32
3.	Fuel, Power, Light & Lubricant Group	3160.91	3314.23	4055.94	4.85	22.38
4.	Manufacturing Group	1889.93	1979.56	2098.64	4.74	6.02
5.	General Index	1827.61	1885.77	2038.82	3.18	8.12

3.2 CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS FOR INDUSTRIAL WORKERS (Base 1982=100)

The Consumer Price Index for industrial workers is prepared and released by the Labour Bureau, Simla which includes Jaipur and Ajmer centres of the State. The rising trend in the retail prices continued during the year 1996. General Consumer Price Index for the year 1996 recorded an increase of 10.31 percent for Jaipur and 8.85 percent for Ajmer centre in comparison to the year 1995. This rate of increase is higher in case of Jaipur centre which was 8.18 percent in 1995 and lower in case of Ajmer centre which was 8.93 percent in 1995.

Consumer Price Index for all the commodity groups for Jaipur and Ajmer centres are summarised in the table given below :-

GROUPWISE CONSUMER PRICE INDEX FOR INDUSTRIAL WORKERS

Table - 3.2.1 (Base 1982 = 100)

Groups	Jaipur			% Variation		Ajmer			% Variation	
	1994	1995	1996	1996 over 1995	1995 over 1994	1994	1995	1996	1996 over 1995	1995 over 1994
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Food	295	323	355	9.91	9.49	287	318	344	8.18	10.80
2. Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants	356	365	378	3.56	2.53	337	347	360	3.75	2.97
3. Fuel & Light	219	228	268	17.54	4.11	239	238	248	4.20	-0.42
4. Housing	154	159	158	- 0.63	3.25	314	318	382	20.13	1.27
5. Clothing, Bedding & Footwear	210	236	283	19.91	12.38	248	274	296	8.03	10.48
6. Miscellaneous	297	320	354	10.62	7.74	255	281	304	8.18	10.20
7. General Index	269	291	321	10.31	8.18	280	305	332	8.85	8.93

It is revealed from the above table that all the commodity groups contributed in the rise of the General Average Indices of both the centres during 1996 except housing group in Jaipur centre.

Average General Consumer Price Index at base 1982=100 for Jaipur, Ajmer and All India for the last 5 years are given in the following table :-

CONSUMER PRICE INDEX FOR INDUSTRIAL WORKERS

Table - 3.2.2 (Base 1982 = 100)

Year	Jaipur		Ajmer		All India	
	Index	% variation over previous year	Index	% variation over previous year	Index	% variation over previous year
1992	228	8.57	243	11.98	237	11.79
1993	245	7.46	253	4.11	252	6.33
1994	269	9.80	280	10.67	278	10.32
1995	291	8.18	305	8.93	306	10.07
1996	321	10.31	332	8.85	334	9.15

The table depicts that the rate of increase in the index was the highest during the year 1996 at Jaipur Centre (10.31 percent) followed by All India (9.15 percent) and Ajmer Centre (8.85 percent).

3.3 PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM

Public Distribution System is operating through a network of Fair Price Shops in the State to provide the essential commodities in the prescribed quantity at prices fixed by the Government. Total 17,963 fair price shops were functioning in the State by the end of December, 1996. Out of these, 13517 shops were functioning in the rural areas. Through these shops 7.80 lakh tonnes of wheat, 0.13 lakh tonnes of rice, 1.80 lakh tonnes of sugar and 3.33 lakh kilo litres of kerosene oil were distributed during the period April to December, 1996.

The Revamped Public Distribution System (RPDS) is operational in the Tribal, Desert and Drought Prone Areas of the State since January, 1992. A total of 122 selected blocks of 22 districts are covered under RPDS in which wheat and rice are distributed at further subsidised rates of Rs. 60 per quintal.

*****

4. INDUSTRIES AND MINES

4.1 INDUSTRIES

The New Industrial Policy, 1994, which aims at rapid industrialisation, has generated healthy industrial environment in the State through coordinated efforts of Industries Department, RIICO, RAJSICO, RFC, Rajasthan Khadi and Village Industries Board and the Bureau of Industrial Promotion etc. As a result of the policy the establishment of non-traditional industries based on high technology are regularly increasing with the increase of industrial investment.

The Industries Department of the State has been making efforts for rapid growth of small scale industries and artisan units. During the financial year 1996-97, 5221 S.S.I. units have been registered wherein with an investment of Rs. 162.10 crores, 21784 persons got employment.

Under handloom development schemes, 257 worksheds have been sanctioned in the current year and weavers have also been covered under the Health Package Scheme.

Under the Prime Minister Rojgar Yojna loan and subsidy upto Rs. 1.00 lakh is provided to un-employed youth for establishing their own industries/service enterprises etc. The sanction of the loan was accorded in 5884 cases during the current year upto December, 1996. Out of these, training was imparted to 3922 youth and loan was disbursed to 864 youth, after training.

Under household industry scheme 3310 poor urban women were imparted training in Embroidery, Knitting, Ari-Tari, Dari-Patti and Sewing etc. through 34 voluntary organisations in 24 districts during 1996-97 (upto December, 1996).

"Udhyam Protsahan Sansthan (UPS)" has been set-up in the State for assisting the marketing of industrial products. The objective of the UPS is to organise exhibitions at the State and National level. Besides organising exhibitions, the UPS organised a 'Buyer Seller Meet' also on 3rd September, 1996 with Artisans Development Society, Alwar.

In the Directorate of Industries, an Exports Promotion Cell is functioning, which along with other activities, publishes an Export Directory for exporters. During the year 1996-97, a provision of Rs. 3.00 lakhs has been made for giving awards to exporters, 22 exporters were given awards last year for excellence in exports.

Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation (RIICO) has provided necessary infrastructural facilities in 213 industrial areas upto December, 1996 in the State. There has been a lot of emphasis on the facilities attached to these areas. During 1996-97, 1175 industrial plots have been developed and 456 plots have been allotted by the end of December, 1996. Financial assistance to large and medium industries is also being provided by RIICO. During 1996-97 (upto December 1996), term loan of Rs. 58.08 crores had been sanctioned and Rs. 35.24 crores disbursed.

Under Centrally Sponsored Scheme, an amount of Rs. 22.92 crore has been spent on 4 Growth Centres i.e. Bikaner, Dholpur, Jhalawar and Abu-Road during the current year upto December, 1996. Besides, Jodhpur Mini Growth Centre has also been sanctioned by the Government of India and Rs. 1.57 crore have been spent on its implementation by the end of December, 1996. The develompent of Export Promotion Industrial Park (EPIP), Electronic Hardware Technology Park, Software Technology Park, has been taken up this year. Besides this, a Leather Complex at village MANPURA-MANCHERI in District Jaipur is also in progress.

Rajasthan Small Industries Corporation (RAJSICO) is helping the small scale industries and craftmens by providing raw material at reasonable rates with marketing facilities for finished products. A number of emporiums are functioning for marketing and popularising the handicrafts of Rajasthan. Exhibitions and training programmes are also organised by RAJSICO for development of handicrafts. During 1996-97, handicraft goods worth Rs. 5.18 crores were sold by the end of December, 1996.Through the Inland Container Depots at Sanganer and Jodhpur and Air Cargo complex at Sanganer goods worth Rs. 595.74 crores were exported upto November, 1996.

The Rajasthan Financial Corporation is functioning mainly to provide term loan for establishment, expansion and renewal of industries in the State. A loan upto Rs. 2.40 crores is sanctioned by the Corporation for establishing industries in the State. Due to simplified and liberal procedure, the Corporation sanctioned loans worth Rs. 163.44 crores and disbursed a sum of Rs. 131.66 crores during the year 1995-96. During the current year upto November, 1996 loans amounting to Rs. 66.68 crores have been sanctioned and Rs. 72.38 crores disbursed. The R.F.C. is playing an important role as an agent of the State Government in providing interest free loans and investment subsidies to industrial units in the State. In the current year, loans upto Rs. 2 lakhs at 2 percent lower interest rates were provided to the persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. No penal interest is being charged such loans. As such the small enterpreneures are benefited by this decision of the Corporation.

In the year 1996-97, an important policy decision was taken to make effective recovery of loans by allowing concession on balance of loans in case of one-time settlement. This has resulted a recovery of Rs. 90.52 crores upto November, 1996 which is 46.42 percent of the stipulated target and 5.35 percent more than the amount recovered last year in the same duration.

Recently, the Corporation has introduced a "Gold Card Scheme". Under this scheme, financial assistance upto Rs. 30 lakhs is provided to the regular loan payers towards working capital and for acquiring additional assets. Top priority was given to Small Scale Industries. The total share of SSI sector in the loans sanctioned by RFC in 1995-96 was 89.79 percent. In the year 1996-97 also, this sector has been given priority which is

depicted in the following table:

Table: 4.1.1

(Rs. in Crores)

Type of Enterprises	1995-96		1996-97 (Upto November, '96)	
	Number	Amount	Number	Amount
1	2	3	4	5
1. Small Transport	105	3.71	40	1.35
2. Small Scale Indus.	1643	146.76	555	60.29
3. Others	22	12.97	7	5.04

INDUSTRIAL PRODUCTION

A comparative picture of production of important selected items during the year 1995 and 1996 in the State is depicted in the following table:-

Table - 4.1.2

INDUSTRIAL PRODUCTION OF SELECTED ITEMS

S.No.	Item	Unit	1995	1996 (Provi-sional)	change in 1996 over 1995 %
1	2	3	4	5	6
1.	Sugar	Tonnes	24717	30987	25.37
2.	Spirit (all Types)	'000 Ltr.	17600	21406	21.62
3.	Vegetable Ghee	Tonnes	28402	30133	6.09
4.	Salt	Lakh M.T.	15	11	- 26.67
5.	Urea	'000 M.T.	392	388	- 1.02

1	2	3	4	5	6
6.	Super Phosphate	'000 M.T.	36	35	- 2.78
7.	Cement	'000 M.T.	6469	6596	1.96
8.	Mica Insulating Bricks	'000 No.	1265	1051	- 16.92
9.	Zinc Ingots	'000 M.T.	91	94	3.30
10.	Cadmium finished prod.	Tonnes	156	161	3.20
11.	Railway Wagons	No.	590	1107	87.63
12.	Ball Bearings	Lakh No.	216	231	6.94
13.	Water Meters	No.	40704	41326	1.53
14.	Radiators	No.	2912	4334	48.83
15.	Polished and repolished stone	'000 Sq. Mtr.	212	242	14.15
16.	Electric Meters	No.	732513	711238	- 2.90
17.	Nylon Yarn	Tonnes	3998	3628	- 9.25
18.	Polyester Yarn	Tonnes	14590	11462	- 21.44
19.	Caustic soda	Tonnes	33711	39566	17.37
20.	Calcium Carbide	Tonnes	50073	44358	- 11.41
21.	P.V.C. Resin	Tonnes	31789	31231	- 1.76
22.	P.V.C. Compound	Tonnes	5282	5279	- 0.06
23.	Sulphuric Acid	'000 Tonnes	240	206	- 14.17
24.	Copper Cathodes	Tonnes	30513	21630	- 29.11
25.	Cotton Cloth	Lakh Mtr.	411	457	11.19
26.	Cotton Yarn	'000 Tonnes	54	57	5.56

As revealed from the above table, there was a mixed trend in the industrial production of the selected items during 1996 as compared to the previous year. Out of the 26 selected items , the production of 14 items increased, whereas production of remaining 12 items decreased during 1996. The range of variation in the production of these items is given in the following table:

Table - 4.1.3

Range of Variations in Production in 1996 over 1995.	Items
1.1 Increase upto 10 percent	Vegetable Ghee, Cement, Zinc ingots, Cadmium finished products, Water Meters, Ball Bearings, Cotton Yarn.
1.2 Increase between 10 to 20 percent	Polished & Repolished stones, Caustic soda, Cotton Cloths.
1.3 Increase between 20 to 50 percent	Sugar, Sprit (All Types), Radiators.
1.4 Increase between 50 to 100 percent	Railway Wagons.
1.5 Increase of more than 100 percent	Nil.
2.1 Decrease upto 10 percent	Urea, Super phosphate, Electric Meters, Nylon Yarns, P.V.C. Resin & P.V.C. compound.
2.2 Decrease between 10 to 20 percent	Mica Insulating Bricks, Calcium Carbide, Sulphuric Acid.
2.3 Decrease between 20 to 50 percent	Salt, Polyster Yarn, Copper Cathodes.
2.4 Decrease between 50 to 100 percent	Nil.

4.2 KHADI & VILLAGE INDUSTRIES

The economic condition of the rural folk is being improved by way of providing them employment on full time & part time basis through Khadi and Village Industries. Financial assistance was provided to 3713 industrial units during the year 1995-96 and during the current year 1458 units have been assisted upto November, 1996.

Production worth Rs. 39.41 crores was recorded in Khadi Industries during the year 1995-96. This is likely to reach the level of Rs. 50 crores by the end of 1996-97. Likewise, in the village industries, the total production was worth Rs. 260.48 crores by the end of 1995-96 which is expected to be of the order of Rs. 278.00 crores by the end of 1996-97. Additional employment opportunities will be provided to 33000 persons by the end of 1996-97. Whereas during 1995-96, 30732 persons were provided employment.

Efforts are also being made to enhance production and improve the quality of woollen and cotton based Khadi by encouraging AMBAR CHARKHAS instead of conventional charkhas.

The Bureau of Industrial Promotion (BIP), Rajasthan is endeavoring to provide one step sevice to entrepreneurs. BIP has also been making efforts to attract prospective lnvestors for seting up their industrial ventures in Rajasthan. Many large and medium scale companies/groups have been contacted in this regard.

4.3 FACTORIES AND BOILERS

The Chief Inspector of Factories And Boilers, is the State authority in respect of registered factories and boilers. The Department is to enforce the provisions of the Factories Act, 1948, Indian Boilers Act, 1923 and Payment of Wages Act, 1936, to ensure safety, health and welfare of industrial workers.

In the current year, 279 new factories were registered and 7246 workers got employment upto December, 1996. 26 training programmes for Supervisors and workers have been organised in the Departmental Training Centre. 359 workers and Supervisors were benifited by these programmes. 161 samples were collected by the Industrial Hygiene Laboratory from the chemically hazardous factories.

In order to gear up the functioning of the department, powers regarding approval of factory drawings and renewal of licences have been de-centralised upto the level of Dy.Chief Inspector of the department. Computers have also been installed for storage and retrieval of data.

4.4 MINES AND MINERALS

The Mines and Geology Department of the State is making concerted efforts to achieve the basic objectives of the new Mineral Policy, 1994 for exploration of mineral deposits by way of survey in various parts of the State. 76 projects have been kept under the scheme of Mineral Survey and Prospecting during the year 1996-97.

The targets proposed and achievements made upto December, 1996 are shown in the following table:-

Table - 4.4.1

Work	Unit	Target (96-97)	Achievement (upto Dec.96)	% Achievement.
1.R.M.S.	Sq.kms.	5200	3778	72.65
2.R.G.M.	Sq.kms.	490	328	66.93
3.D.G.M.	Sq.kms.	20	12.35	61.75
4.Delineation	Sq.kms.	31.50	23.60	74.92
5.Drilling	Mtrs.	16750	7100.05	42.38

In view of increasing demand of building and decorative stones emphasis has been given to search and demarcation of marble and granite deposits. Demarcation of 43 plots of granite and 11 plots of marble was made during the current year in various districts and notification were issue for their allotment. In Andhi region of Jaipur District and Begun Tehsil of Chittorgarh District, exploration of marble is in progress.

For search of S.M.S. grade lime-stone in the current year, exploratory drilling work has been continued in Jaisalmer District and about 10 million tonnes SMS grade and 170 million tonnes cement grade lime-stone reserves have been assessed there. In Nagaur district also lime-stone deposits have been found at Tankala and Dehra regions and addidional reserves of the order of 15.50 M.T.have been assessed.

During the search of other industrial minerals, a good quality of quartzite mineral has also been discovered in Kama Tehsil of Bharatpur District.

Vigorous search of lignite in Nagaur and Bikaner Districts have also been continued an exploratory drilling work is in progress. Thick lignite seams of 15m to 16m thickness have been intersected in Hadla area of district Bikaner. The investigation for gold is being continued in Sadri-Undwala-Khemera areas in district Banswara and encouraging results have been encounted. One to eight gm of gold per tonne of rock has been found at 172.30 m to 182.30 m depth.

Rajasthan State Mineral Development Corporation is also engaged in developing, promoting, establishing and executing the projects, enterprises and industries based on minerals, either its own or in the joint sector. Apart from the mining activities, the Corporation also provides consultancy for development of mines and setting up of mineral based industries. The Corporation is operating mines on commercial lines at different places in 13 districts of the State.

The Coroporation helps entrepreneurs in the State by way of participation in equity and management of companies and also by allocating mining areas for their capative consumption. The corporation has so far made an investment of Rs. 92.15 lakh in the equity of joint/assisted sector companies. The target of lime-stone production has been kept at 17.95 lakh mt.tonnes in 1996-97 for meeting out the increasing demand of steel plants.

The corporation contributed a sum of Rs. 13.42 crore to the State Exchequer by way of payment of Royalties, Land Tax, Sales Tax and by

way of sharing of profits from lime-stone operations at Jaisalmer, Banswara and Kotputli and levy on Gypsum during 1995-96.

4.5 LABOUR

INDUSTRIAL RELATIONS

Labour Department of the State has endeavoured to enforce various labour laws effectively for maintaining industrial peace and welfare of the labourers. The department has adopted reasonable and determined attitude to solve labour problems, the watchful enforcement of labour laws resorted industrial peace in various institutions and labourer's intrest.

Measures were taken up to control strikes and lockouts. Out of 7054 complaints, 4163 complaints were disposed off during the current year upto December, 1996.

During the year 1996-97 (upto December, 1996) 32 strikes/lockouts were reported affecting 19548 labourers and 4.66 lakh mandays were lost, whereas 51 strikes/lockouts were reported during 1995-96 affecting 26950 labourers and loss of 5.02 lakh mandays.

At the beginning of the year 1996-97, there were 3110 registered trade unions in the State with membership of 5.22 lakhs. 96 new trade unions with the membership of 0.11 lakhs have been registered upto December, 1996.

4.6 EMPLOYMENT

Generation of employment opportunities is one of the main objectives of planned development. Therefore, information on employment opportunities and unemployment in various categories of the

population is essential. Estimated employment in public & private sectors in Rajasthan is given in the following table:

Table - 4.6.1

(In lakhs)

Year	RAJASTHAN		
	Public Sector	Private Sector	Total
1.	2.	3.	4.
1992	9.73	2.31	12.04
1993	9.77	2.32	12.09
1994	10.05	2.43	12.48
1995	10.09	2.55	12.64
1996 (on 30th June, '96)	10.10	2.56	12.66

During the period of January to December 1996, the number of unemployed persons registered with various Employment Exchanges was 2,94,164, out of which 40,629 persons were under Scheduled Castes category and 20,195 persons under Scheduled Tribes category. 20,380 vacancies were notified against which 2,11,969 candidates were referred, out of which 11,483 persons were provided employment during the same period.

*****

5. AGRICULTURE AND ALLIED SECTORS

5.1 MONSOON

The prospects of agriculture in the State depend largely on timely occurrence of rains. It is particularly so in the case of Kharif season, where production and productivity of crops are dependent not only on the quantum of rains, but also on it's proper distribution over a reasonable time span alongwith intensity.

The behaviour of the monsoon in Rajasthan is usually erratic and uncertain. The year 1996-97 experienced some delayed but satisfactory rains throughout the State. The rainfall recorded 72.63 Cms. during June to September, 1996, which is 39 percent higher than the normal rainfall of the same period.

5.2 AGRICULTURE PRODUCTION

Rajasthan is predominantly an agrarian State and a large number of its population depending on it. Agriculture plays an important role in the State's economy, as more than 40 percent of Net State Domestic Product popularly known as "State Income" is generated from agriculture and allied sectors.

The area and production of major crops for last 3 years are depicted in the following table:

Table - 5.2.1

Crop	Area (in lakh hect.)			Production (in lakh tonnes)		
	1994-95 (Revised)	1995-96 (Final)	1996-97 (Likely)	1994-95 (Revised)	1995-96 (Final)	1996-97 (Likely)
1	2	3	4	5	6	7
Cereals	93.23	83.09	88.34	97.45	81.03	105.90
Kharif	67.65	59.16	62.56	36.95	22.20	35.93
Rabi	25.58	23.93	25.78	60.50	58.83	69.97
Pulses	36.02	35.74	37.16	19.65	14.63	21.12

1	2	3	4	5	6	7
Kharif	19.77	19.14	20.63	5.45	3.29	5.97
Rabi	16.25	16.60	16.53	14.20	11.34	15.15
Foodgrains	129.25	118.83	125.50	117.10	95.66	127.02
Kharif	87.42	78.30	83.19	42.40	25.49	41.90
Rabi	41.83	40.53	42.31	74.70	70.17	85.12
Oil-Seeds	34.89	38.39	40.43	28.34	30.68	40.94
Kharif	10.87	10.10	12.41	7.53	6.42	8.95
Rabi	24.02	28.29	28.02	20.81	24.26	31.99
Sugarcane	0.22	0.28	0.22	9.87	13.85	10.21
Cotton *	4.86	6.06	5.89	8.75	13.38	12.95

* Production in lakh bales (each bale of 170 Kg.)

Area under kharif foodgrains in 1996-97 is likely to be 83.19 lakh hectares as compared to 78.30 lakh hectares in 1995-96. Kharif foodgrain production is estimated to be 41.90 lakh tonnes in 1996-97 as compared to 25.49 lakh tonnes in 1995-96 showing an increase of 64.38 percent. The main contributor in kharif cereals are Bajra and Maize. The production of Bajra in the year 1996-97 is estimated to be 21.00 lakh tonnes which was 11.52 lakh tonnes in 1995-96 showing an increase of 82.29 percent, while the production of Maize is estimated to be 10.16 lakh tonnes during 1996-97 from 8.08 lakh tonnes during previous year, registering an increase of 25.74 percent.

The production of Rabi foodgrains in 1996-97 is likely to reach upto 85.12 lakh tonnes from 70.17 lakh tonnes in 1995-96 thereby showing an increase of 21.31 percent. The main contributor in Rabi cereals is Wheat which is expected to be 64.81 lakh tonnes in the year 1996-97 as compared to 54.93 lakh tonnes in 1995-96 showing an increase by 17.99 percent. Production of Barley is likely to increase upto 5.16 lakh tonnes from 3.90 lakh tonnes during the reference period.

Pulses are a rich source of energy and minerals and constitute an important source of dietary proteins. The production of Kharif Pulses is likely to be 5.97 lakh tonnes in 1996-97 as against 3.29 lakh tonnes in 1995-96 showing an increase of 81.46 percent. The production of Gram is likely to reach 14.83 lakh tonnes in 1996-97 which was 10.90 lakh tonnes in 1995-96 showing an increase of 36.06 percent.

Production of Oilseeds includes groundnut, sesamum, soyabean and castorseed during Kharif season and rape and mustard, taramira and linseed in Rabi season. Production of Oilseeds during 1996-97 has surpassed all previous records. The production of Oilseeds in 1996-97 is estimated to be 40.94 lakh tonnes from 30.68 lakh tonnes in 1995-96 showing an increase of 33.44 percent over the previous year. The production of Kharif Oilseeds is estimated to be 8.95 lakh tonnes in 1996-97 from 6.42 lakh tonnes in 1995-96, rising by 39.41 percent. The production of Rabi Oilseeds is likely to reach 31.99 lakh tonnes in 1996-97 from 24.26 lakh tonnes in 1995-96, showing an increase of 31.86 percent. The production of Rape & Mustard is likely to be 31.06 lakh tonnes in 1996-97 from 23.68 lakh tonnes in 1995-96 showing an increase of 31.17 percent.

The production of sugarcane during the year 1995-96 which was 13.85 lakh tonnes, is likely to go down to 10.21 lakh tonnes in 1996-97.

Cotton is an important cash crop being grown in the State especially in Ganganagar and Hanumangarh Districts. The production of cotton is likely to be 12.95 lakh bales during 1996-97 which was 13.38 lakh bales in the year 1995-96 showing a marginal decrease of 3.21 percent.

5.3 <u>AGRICULTURE EXTENSION AND INPUT MANAGEMENT</u>

The availability of quality seeds is essential for achieving higher level of production. Accordingly, High Yielding Seeds Variety Programme introduced in the State has been a major instrument of agricultural strategy to increase foodgrain production. Use of fertilizers also remains one of the larger determinants of crop yield.

Various measures are being taken through agriculture extension and input management to reduce the adverse influence of the erratic monsoon and hostile weather conditions on agriculture production in the State. Achievements under agriculture extension and input management programmes during the years 1995-96 and 1996-97 are shown in the following table:

Table 5.3.1

Items	Season	Unit	1995-96 Achievements	1996-97 Target	1996-97 Achievements (Likely)
1	2	3	4	5	6
1. Area under high yielding varieties	Kharif	Lakh Hect.	16.77	17.00	14.50
	Rabi (Wheat)	" "	16.40	17.00	17.25
2. Distribution of high yielding variety seeds	Kharif	'000 Qtls.	53.34	53.00	52.14
	Rabi (Wheat)	" "	169.67	150.00	197.00
3. Distribution of other improved seeds	Kharif	'000 Qtls.	71.15	60.30	79.88
	Rabi	" "	50.17	46.50	57.48
4. Distribution of fertilizers	Kharif	'000 Tonnes	299.90	309.00	279.12
	Rabi	" "	342.65	418.60	424.46
5. Distribution of Rhyzobium culture packets	Kharif	Packets in Lakh Nos.	2.93	10.50	4.00
	Rabi		4.32	9.50	4.00
6. Area covered under plant protection measures	Kharif	Lakh Hect.	47.81	37.00	48.71
	Rabi	" "	40.00	35.00	36.00

5.4 <u>IRRIGATION</u>

Out of the total area cultivated in the State, only 29.00 percent area (on an average) is under irrigation. There are four major sources of irrigation viz. canal, tanks, wells and tube-

wells. Out of total irrigated area, 60.24 percent covered by wells and tube-wells, 34.31 percent by canals and 5.45 percent by other sources during 1994-95.

Details of source-wise area irrigated during 1992-93 to 1994-95 are given in the following table:

Table - 5.4.1 (Area in '000 Hectares)

Source of Irrigation	Net area irrigated			Gross area irrigated		
	1992-93	1993-94	1994-95	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5	6	7
1. Canals	1428	1373	1427	1990	1835	1995
2. Tanks	207	170	247	230	189	265
3. Wells & Tubewells	2803	3009	3134	3231	3523	3503
4. Others	33	45	50	35	48	52
5. Total	4471	4597	4858	5486	5595	5815

The Irrigation Department of the State is functioning for optimum utilisation of available surface water potential in the State through construction of various major, medium and minor irrigation projects. A sum of Rs. 264.45 crores has been made available for the irrigation sector excluding I.G.N.P. during the year 1996-97. Out of this, Rs. 30.00 crores have been kept for Mahi Bajaj Sagar Project, Rs. 15.00 crores for Bisalpur Project, Rs. 45.00 crores for Sidh-Mukh Nohar Project, Rs. 174.45 crores for other major, medium and minor projects as also for modernisation and Flood protection measures including Ghaggar flood protection work.

26 new minor irrigation works costing about Rs. 38.50 crores have been sanctioned during 1996-97 (upto November, 1996). An additional irrigation potential of 15,160 hectares is likely to be created in the State during the year 1996-97.

The work of Indira Gandhi Nahar Project is being executed in the districts of Churu, Hanumangarh, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur and Barmer to utilise 7.59 MAF waters out of total 8.6 MAF allocated to Rajasthan, out of surplus waters of rivers Ravi and Beas. For administrative convenience project work has been taken up in two stages.

An amount of Rs. 13.00 crore has been provided for the stage I of I.G.N.P. during 1996-97 by which 4000 hectares of irrigation potential would be added. Further, 280 km.distribution system creating irrigation potential of 41000 hectares has been taken up in stage II during 1996-97.

Water is thus, a very critical resource. Ground water is the principal source for irrigation and drinking purpose. 371 tube-wells and 238 hand-pumps have been constructed by the Ground Water Department during the year 1996-97 (upto December, 1996). Besides, 1805 wells have been deepened by rock drilling and blasting under various programmes during the same period.

5.5 **ANIMAL HUSBANDRY**

Animal husbandry plays an important role in the State's rural economy. A large number of small and marginal farmers, agricultural labourers and other local poors depend upon livestock for gainful employment. As per 1992 livestock census, there are 484.46 lakh livestock and 30.13 lakh poultry in the State. The western districts of the State are famous for indigenous cattle breeds.

1468 veterinary institutions and district level vety. polyclinics are functiong during 1996-97 in the State. Besides, 53 mobile veterinary units are also working in the districts to provide veterinary services to the Cattle Breeders at close proximity. 45 Sub-Divisional Mobile Units and 29 District Diagnostic Labs. are also functioning. At present one Veterinary institution is serving to 15,766 Cattle Units in the State.

Under the Integrated Cattle Development Programme, 749 sub-centres were established by re-structuring the existing institutions of Jaipur,

Bikaner, Ajmer, Kota and Udaipur divisions. This programme is being implemented in 21 districts of the State to provide animal health care within a radius of 5 to 8 kms. Cattle development work under "Gopal Scheme" continued in 40 selected Panchayat Samities of 12 districts of Southern and Eastern parts of the State. In these districts, 572 'Gopal' are working. For breed improvement of horses, 10 horse development centres are working in the State. One goat breeding centre has been working in Ramsar village of Ajmer district for goat development and goat feed production.

Piggery programme is also being implemented in the State under which foreign breed piggery farm was established in Alwar district. For poultry development, a new demonstration "Cage System" is being developed at State Poultry Farm, Jaipur. 6 Govt. poultry farms and 17 Intensive Poultry Development Blocks have been working. Under Feed and Fodder Development Programme, Fooder Seeds Production Farm has been established at Mohangarh in Indira Gandhi Nahar area.

5.6 **DAIRY DEVELOPMENT**

This programme is basically designed to link rural milk producers with urban consumers. The activities are organised by farmers owned and managed dairy cooperative societies. Its aim is to provide good quality milk and milk products to the consumers, ensure animal health care and renumerative return to the milk producers. 10 dairy plants with processing capacity of 9 lakh litres milk per day and 24 chilling plants with a capacity of 4.7 lakh litres of milk per day were functioning by the end of December, 1996 in the State.

Integrated Dairy Development Programme is being executed in all the districts of the State through 16 Milk Producers Cooperative Unions at the end of December, 1996. 70 new Milk Producers Cooperative Societies were constituted and 105 defunct societies were revived. By the end of December, 1996 the total number of functional societies was 3231. The total number of members increased to 3.76 lakhs. The average milk collection had been 4.96 lakh litres per day during 1996-97 (April, 1996 to December, 1996).

Dairy Federation is running 4 Cattle Feeding Plants to provide nutritious feed to the animals. 47535 tonnes cattle feed was produced and marketed during 1996-97 (upto December, 1996).

5.7 **SHEEP HUSBANDRY**

Sheep husbandry is fast becoming one of the most important components of rural economy as it provides additional income and employment opportunities to a large segment of population especially to the weaker sections of the society in Western and North-Western parts of the State. It is the main occupation of the weaker sections to earn their livelihood. According to Livestock Census of 1992, the sheep population was 124.91 lakhs which is about 25 percent of the Country's sheep population. As per available information about 170 lakh Kg. wool are being produced yearly in the State which is nearly 40 percent of the country's wool production. More than 2 lakh families are engaged in sheep rearing. As preventive measures dosing against internal parasites, spray and dusting against external parasites and vaccination programmes for sheep are being carried out on a large scale. Cross and selective breeding and training programmes are also being implemented with a view to produce better quality fine wool. Due to shortage of water and fodder, sheep migrate from Western Rajasthan to its border States like Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Gujarat. 41 permanent Migration Check Posts have been established to give proper and immediate treatment to the sheep during stay.

5.8 **FISHERIES**

Rajasthan is endowed with potential of 3.30 lakh hectares of water for development of fisheries. Out of which 1.20 lakh hectares is in the form of large and medium reservoirs, 1.80 lakh hectares in the form of small tanks and 0.30 lakh hectares in the form of rivers/canals. These resources offer immense scope and potential for fisheries development. The main objective of this programme is to increase fish production by way of producing and stocking of quality fish seed, impart training to fish farmers and provide employment through F.F.D.As.

The production of fish was 4500 tonnes upto December, 1996. 15 Fish Farmers Development Agencies are functioning through which each fish farmer is allotted one hectare of water area. Training is also imparted to such persons by these agencies. 8243 persons trained and 4834 hectare of water area has been allotted to them upto December, 1996.

Fish seed to the tune of 131 million fry was produced during the year 1996-97 (upto December, 1996). To encourage fish seed production in private sector, a scheme has been initiated since 1991 for setting up of fish seed hatcheries. Under this scheme 25 percent of capital cost subject to a maximum of Rs. 1.00 lakh is provided as subsidy by the State Government. For tribal beneficiary, the subsidy component is 50 percent of the capital cost subject to a maximum of Rs. 2.00 lakhs. So far 10 such hatcheries have been sanctioned out of which 5 are functioning.

5.9 **FORESTRY**

Forests are one of the important natural resources so far as environmental protection and ecological balance are concerned.

In Rajasthan, only 9 percent of the total geographical area of the State is classified as forest area against the recommended level of 33.33 percent under the National Forest Policy. In terms of area, Rajasthan is the second largest State. However, the scenerio of forest continues to be a cause of concern for the State.

The total forest area was 31753.57 sq.km. by end of the year 1995-96 in the State. Out of this, 12272.71 sq.km. was Reserve Forest, 16116.97 Sq. Km was protected forest and 3363.89 Sq. Km was unclassified forest area.

With a view to accelerate the pace of afforestation and pasture development, the works are being carried out in the State under specific projects. At present the Forest Department is executing three major afforestation projects with financial assistance from O.E.C.F. Japan.

Project of afforestation and pasture development in IGNP area i.e. Bikaner and Jaisalmer districts, was sanctioned in the year 1990-91 costing Rs. 107.65 crores. By the end of 1995-96 afforestation over 34045 hectares area has been carried out. During the year 1996-97, afforestation work carried out over 7563 hectares by the end of December, 1996. Further advance soil work over 13850 hectares was in progress.

Aravali afforestation project was started in the year 1992-93 in 10 districts of the State. This project envisages afforestation over 1.15 lakh hectares land with an estimated cost of Rs. 176.69 crores. By the end of 1995-96, afforestation over 77440 hectares have been carried out. Afforestation over 34500 hectares has carried out during the current financial year upto December, 1996. Advance soil work over 5900 hectares was in progress.

One more major afforestation project with the financial assistance from O.E.C.F. Japan for 14 districts of the State was sanctioned in the year 1995-96. Afforestation over 55000 hectares area with an estimated cost of Rs. 139.18 crore will be carried out under this project. During 1995-96, only advance soil work was carried out over 15000 hectares. During 1996-97, an amount of Rs. 10.21 crore has been utilised upto December, 1996 against a provision of Rs. 26 crore to carry out afforestation over 11000 hectares.

Besides above, afforestation and pasture development works are also being carried out by the Forest Department under State Plan Programmes and C.S.S. During 1996-97 afforestation over 82343 hectares have been carried out by the end of December, 1996 from the resources made available under various schemes. Further, 365.07 lakh seedling under Farm Forestry have been distributed.

The major thrust of Forest Department is on increasing the production of fuel-wood, fodder and timber so as to meet the growing demand of the rural masses and to reduce the increasing gap between the demand and supply of fuel-wood and fodder.

Ministry of Environment and Forests, Government of India, publishes satellite imaginary based "Forest Status Report" at an interval of every two years. The reports published during 1991, 1993 and 1995 shown an increase in the forest cover in the State of Rajasthan by 5 Sq. Km., 210 Sq. Km and 181 Sq. Km. respectively. Thus a total increase of 396 Sq. Kms. has been reported in the forest cover in Rajasthan during a period of six years.

5.10 **PRESERVATION OF WILD LIFE**

Rajasthan is very rich in wild fauna. Because of its size and geographical location, State provides a variety of habitats that support a number of rare and endangered animal and bird species, viz. Great Indian Bustard, Tiger, Leopard, Chinkara, Sloth Bear, Wolf, Floricans, Black Necked Storks, etc.

At present the State has 2 National Parks, 23 Wild-Life Sanctuaries spreading over 9282 Sq. Kms. That constitutes nearly 2.8 percent of the geographical area of the State. Besides these, there are 32 closed areas spreading over 1.48 million hectares.

Rajasthan has the World's unique habitat for birds at Bharatpur, which is a paradise for water birds.

Under the activity of preservation of wild-life, habitats improvement works, development of water resources, fire control measures and eradication of weeds etc. are being undertaken in the State.

*****

6. BASIC INFRASTRUCTURAL DEVELOPMENT

6.1 POWER

Rajasthan State Electricity Board is engaged in the investigation and execution of various electric projects, transmission and distribution of electricity. Kota Thermal Power Plant, Mahi Hydel Project, Beas, Chambal and Satpura project are the principal sources of power supply to the State. In addition to these, Rajasthan Atomic Power Project, Singrauli, Rihand, Anta, Auraiya, Narora and Dadari Gas, Uchahar Thermal and Tanakpur Project in Central Sector are also sharing power with the State. At the end of 1995-96, the installed capacity in the State was 3049 M.W. It is expected that 4.335 M.W. generating capacity would be added during the Year 1996-97. Further, action has also been initiated for creating generating capacity of 4034.5 M.W. of power in private sector.

The pattern of generation, purchase and consumption of electricity in the State during three years is depicted in the following table:

Table - 6.1.1

(In million units)

Item	1994-95	1995-96	1996-97 (Provisional)
1	2	3	4
1. Generation (Net)	8150.63	9185.68	9830.15
2. Purchase	8272.87	9985.56	8897.50
Total(1+2)	16423.50	19171.24	18727.65
3. Consumption:			
(a) To other State/ System	284.87	442.82	250.00
(b) To Common Pool Consumer & Power	147.85	165.57	165.00

1.		2.	3.	4.
(c)	To Consumers of Rajasthan	11853.09	13079.73	14213.43
(i)	Domestic	1658.88	1948.39	2063.10
(ii)	Non-Domestic	598.20	685.04	676.21
(iii)	Industrial	4827.25	4985.60	5854.79
(iv)	Agriculture	3738.65	4362.66	4377.45
(v)	Public Water Supply	478.29	526.10	557.00
(vi)	Street Lighting	60.76	72.38	68.91
(vii)	Others	491.03	499.76	615.92
(viii)	Consumption of power in grid sub-posts & 33 KV sub-posts	37.33	40.68	41.00

During the year 1996-97 (upto December, 1996), 13568 million units power was made available in the State from the different sources, which is more by 6.63 percent from the corresponding period of the last year. Although the State continued to face shortage of power, but for agriculutral operation, power was made available on an average of 8 hours a day from April to November, 1996 and 6 hours a day during December, 1996.

Under Rural Electrification Programme, 33827 villages (as per 1991 Census) were electrified by the end of 1995-96. In addition to these, 188 villages have been electrified during 1996-97 (upto December, 1996). Thus, total 34015 villages have been electrified so far. 23535 wells have been energised during 1996-97 (upto December, 1996) making a total of 5.26 lakh wells energised so far.

Power consumption is likely to be 14213.43 million units during 1996-97 as against 13079.73 million units during the last year. Thus, the per capita power consumption is likely to be 281 units during 1996-97 as against 265 units in the previous year.

6.2 NON-CONVENTIONAL SOURCES OF ENERGY - REDA

Under the programme of non- conventional energy sources various programmes viz.

Installation of Solar Power Pack, Strengthening of SPV Street Lights, Installation of SPV Pumps, Wind Energy, Solar Water Heating System, Solar Distillation Plants etc. were emphasised to produce additional energy in the State by Rajasthan Energy Development Agency (REDA). An amount of Rs. 200 lakhs has been made available for this programme during 1996-97. In addition to this Rs. 649.38 lakhs have also been provided for electrification of 50 villages through Solar Power Pack.

During the year 1996-97 (upto December, 1996) Solar Power Pack of 76.29 KW and 18 S.P.V. pumps have been installed. Strengthening work of 491 SPV lights were also done. Further , subsidy on sale of 547 Solar Cookers, and 552 Solar Lanterns were provided by REDA during the same period.

Under Bio Gas Development Programme, 857 Bio-Gas plants have been installed during 1996-97 upto December, 1996. Besides, 221 plants were under installation.

6.3 TRANSPORT AND COMMUNICATION

- ROADS

Roads are crucial infrastructure for the development of an area. Due importance has been attached to road construction since inception of the plan era. But Rajasthan is still far below the National average in respect of road length. The road length per 100 Sq. Kms is likely to be 40.31 Kms. by the end of 1996-97. It was 39.29 Kms. at the end of 1995-96, which was much below the national average of 62.1 Kms. per 100 Sq. Kms. Total road length administered by Public Works Department is likely to increase to 73729 Kms. by the end of 1996-97 from 70229 Kms. in 1995-96. Besides, 64220 Kms. of roads have also been

constructed by other the road length during 1994-95 to 1996-97 are given below :

Table - 6.3.1 (in Km.)

Roads	1994-95			1995-96			1996-97 (likely)		
	Surfaced	Unsur-faced	Total	Surfaced	Unsur-faced	Total	Surfaced	Unsur-faced	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. <u>P.W.D. Roads</u>									
1. National Highways	2846	-	2846	2846	-	2846	2846	-	2846
2. State Highways	9734	76	9810	9920	86	10006	9946	60	10006
3. Major District Roads	5372	177	5549	5533	174	5707	5557	150	5707
4. Other District Roads	10254	1889	12143	10860	1755	12615	10980	1635	12615
5. Village Roads	24460	8640	33100	26998	9818	36816	28728	11588	40316
6. Border Roads	2239	-	2239	2239	-	2239	2239	-	2239
Total (A)	54905	10782	65687	58396	11833	70229	60296	13433	73729
B. <u>Other Deptt. Roads</u>			46438			64220			64220
Total (A+B)			112125			134449			137949

To give more emphasis to the network of roads, "A Policy on Road Development" is being implemented in the State.

Out of 10 bridges, 4 by-passes and one tunnel sanctioned by HUDCO under institutional finances, 6 bridges have been completed and works on remaining 4 bridges are in progress.

Under the World Bank Assisted Programme, upgradation and widening works of 2 State Highways

viz. Udaipur-Dabok-Chittorgarh and Sirohi-Mount-Abu have been completed. Works on 2 State Highways viz. Alwar-Bhiwadi-Mandrayal and Ajmer-Chittorgarh are in progress and expected to be completed by the end of March, 1997. Widening of National Highway No - 8 to four lanes between Jaipur-Delhi is in progress. Railway over bridge at Bais Godown, Jaipur has already been completed and opened for traffic.

- **ROAD TRANSPORT**

The total number of motor vehicles registered was 17.21 lakh in 1995 which has gone to 19.29 lakh in 1996 showing an increase of 12.06 percent. Details of various categories of vehicles registered with State Transport Department during the years 1994 to 1996 are given below :

Table - 6.3.2 (Number)

Type of Vehicles	Cummulative Number in the Year			% increase in 1996 over 1995
	1994	1995	1996	
1	2	3	4	5
1. Motorised Rickshaws	90	90	90	-
2. Two Wheeler	1020054	1145295	1288411	12.50
3. Auto Rickshaws	23168	25218	28272	12.11
4. Tempos :				
(i) For carrying Goods	1371	1791	2258	26.07
(ii) For carrying Passengers	4182	4513	5057	12.05
5. Car & Station Wagons	68881	76940	88746	15.34
6. Jeeps	55822	62272	71095	14.17
7. Tractors	197386	217115	241009	11.01
8. Trailors	42701	43561	45613	4.71
9. Taxies	12171	13083	14192	8.48
10. Buses & Mini Buses	30870	33302	35627	6.98
11. Trucks & other Goods carriers	87232	95039	105285	10.78
12. Miscellaneous	2667	2771	2872	3.64
Total	1546595	1720990	1928527	12.06

During 1996-97 (April to December, 1996), permanet permits (including National permits) for 13689 luggage carriages, 2446 stage carriages and 4583 contract carriages were issued. 4 new routes covering 120.5 Kms have been opened.

*****

7. SOCIAL INFRASTRUCTURAL DEVELOPMENT

7.1 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

Rajasthan is educationally a backward State. The total literacy percent is 38.55 with 54.99 percent in males and 20.44 percent in females. The situation of female literacy is particularly alarming in the State. A wide gap exists between rate of literacy in urban and rural areas and among male and female.

Continuous efforts are being made for development of education in the State. A number of measures have been taken up to encourage women education.

Universalization of Elementary Education (UEE) for children upto 14 years of age is the main target. Hence elementary education has been covered under Minimum Needs Programme and 20-Point Programme.

During the current year 500 primary schools have been approved, out of which 182 primary schools have been opened. Upgradation of 600 primary schools to upper primary schools (UPS) has also been done this year with the ultimate objective that each Panchayat area should have atleast one UPS. In order to improve access to secondary education, 82 primary schools and 69 secondary schools have been upgraded to secondary and senior secondary schools respectively.

The categorywise breakup of the schools functioning in the State during 1996-97 are furnished below:-

Table - 7.1.1

Institutions	Number
1	2
1. Primary schools	33801
2. Upper primary schools	12692
3. Secondary schools	3501
4. Senior secondary schools	1404

For effactive achievement of UEE and qualitative improvement of elementary education, two externally aided projects, Shiksha-Karmi (SK) and Lok-Jumbish (LJ), are going on. Lok-Jumbish is operational in 132 clusters in 58 blocks. Under Shiksha-Karmi 1877 formal schools and 3520 non-formal education centres have been rejuvenated/ started in difficult rural areas of the State. It is estimated that 83 percent girls of age group 6-14 years have been enrolled with average attendence of 80.20 percent in the villages covered by Shiksha-Karmi Schools / Non-Formal Education Centres.

For increasing the enrolment and retaining the students at Elementary Education level, "Free Text Book Distribution Scheme" for girls studying in class I to VIII and for boys studying in class I to V is being implemented in the State. Under this Scheme, 58.50 lakhs student have been benefited during the year 1996-97.

"Saraswati Yojna" is being implemented through the educated women in the rural area of the State for encouraging the girls education. As against the target of 1000 Kendras during the year 1996-97, 650 new Saraswati Kendras have been opened by the end of December, 1996. The scheme has now been expanded to all the districts of the State.

"Guru Mitra Yojna" is also being implemented in ten districts of the State with a view to encouraging and trained teachers for joyful learning / teaching at the primary stage.

Students Insurance Scheme has been introduced during the current year for regular students of class I to XII in Government Schools. An amount of Rs. 22.50 lakhs has been paid by the State Government as lumpsum premium under the scheme. No premium will be charged from the students.

In order to ensure adequate availability of trained teachers, 39 Teacher's Training Colleges are functioning in the State wherein 7241 students were imparted training during the current year. Out of these, 2851 were women candidates. In addition to this, 27 District Education and Training Institutions are also functioning for

pre-service and in-service teachers training. Vocational Education Scheme is being implemented in 156 Senior Secondary Schools in the State.

Sanskrit and Indian culture are complementary to each other. The entire history of Indian culture and civilisation, the spiritualism and the whole gumut of knowledge are encapsulated in Sanskrit. In view of this, efforts are being made for development of sanskrit education in the State. A proposal pertaining to establishment of a Sanskrit University is under consideration of the Government.

The construction work of new building of the Directorate of Sanskrit Education has been completed during this year. Also 30 new Primary Sanskrit Schools were opened during the year 1996-97 upto December, 1996. Beside this, 2 Shastri Schools, 4 Upadhyay Schools and 10 Praveshika Schools have been upgraded.

The Directorate of Adult Education is implementing a State wide functional literacy programme with due emphasis on National Integration. The Total Literacy Campaign (TLC) is the dominant strategy adopted for this purpose. Presently, the campaign is in various stages in all the districts. In seven districts of the State (Ajmer, Dungarpur, Bharatpur, Pali, Tonk, Banswara and Sikar) the Post Literacy Campaign (PLC) is in operation.

Under the Total Literacy / Post Literacy Campaign, 46.98 lakh illiterates / neoliterates have been enrolled by the end of December, 1996 against the annual target of 52 lakh persons. Out of these enrolled persons 8.23 lakh are under PLC and 38.75 lakh persons are under TLC. About 9.10 lakh persons of scheduled castes and 11.13 lakh persons of scheduled tribes have been benefited so far.

The children of 6-14 year age group, who are unable to attend formal primary schools due to

their economic, social or other circumstances are sought to be covered under Non-Formal Education Programme. About 17,207 Non Formal Education Centres were functioning in the State at the end of December, 1996. Approximately 5.02 lakh children have been enrolled upto December, 1996 against the annual target of 5.65 lakhs, out of which 2.18 lakh are boys and 2.84 lakh are girls.

For imparting higher education, presently 6 Universities including one Agriculture University, 4 University level institutions, 211 colleges / Research Institutions (83 Post Graduate Colleges and 128 Graduate Colleges) are functioning in the State.

During the year 1996-97, 3 women Colleges at Dausa, Sawai Madhopur and Dungarpur and 2 Co-education colleges at Nokha and Merta City have been opened. The Government College, Neem-ka-Thana was upgraded to post-graduate level. Further, 14 new subjects were introduced at graduate / post-graduate level.

In academic session 1995-96 under higher education, 1,45,000 students were studying. Presently, this number has increased to 1,71,500 and the number of girl students has increased to 52,800 in 1996-97 from 44,000 in 1995-96, which indicates 20 percent increase in the number of girl students.

The Directorate of Technical Education has been providing technical education through Industrial Training Institutes and Polytechnics in the State.

7.2 MEDICAL & HEALTH

Medical and Health Department of the State is functioning to control and eradicate communicable and other diseases and to provide

curative and preventive services to the people in the State. Details relating to allopathic medical institutions functioning in the State are as follows :-

Table - 7.2.1

	Institutions	Number
1.	Hospitals	219
2.	Dispensaries	278
3.	Primary Health Centres	1616
4.	Community Health Centres	261
5.	Maternity and Child Welfare Centres	118
6.	Aid Posts (Urban)	13
7.	Sub-Centres	9400
8.	Inpatient Beds	36702

During the year 1996-97, against the target of 700 cases, 598 leprosy cases were detected under the "Leprosy Eradication Programme", and under "T.B. Eradication Programme" 51,749, new cases were detected against the target of 45,000 cases upto December, 1996. Under the "Blindness Eradication programme", 92961 eye operations were performed upto January, 1997.

Under Malaria Eradication Programme, 65.91 lakh blood slides were collected and examined during 1996-97 (upto December, 1996) against the target of 44 lakh. Under the "National Aids Control Programme" the blood of 82,591 persons was tested upto December, 1996.

In order to contol 'Infant Mortality Rate' and to provide safeguard against serious diseases, an intensive "Child Immunization Programme" is

being launched in the State. Progress of the same is given in the table below:-

Table - 7.2.2

Item	Target (1996-97)	Achievements (upto January, 1997)
1. D.P.T. Innoculations	15,66,100	10,64,214
2. B.C.G. Innoculations	15,66,100	11,51,793
3. Measel Innoculations	15,66,100	9,88,814
4. Titanous Injections	17,47,200	10,58,422

To attain the national goal of complete eradication of the Polio Disease, a special campaign "Pulse Polio" was launched during the current year in two phases, first on 7th December, 1996 and second on January 18th,1997.

Under the Employees State Insurance Scheme, 3 hospitals one each at Jaipur, Kota and Jodhpur, 60 dispensaries at various places and one homoeopathic dispensary at Jaipur are functioning in the State to provide medical facilities to the industrial labourers working in various industries and factories. During 1996-97 medical facilities were provided to 1580620 outdoor and 7846 indoor patients up to November,1996.

AYURVED:

Presently, under Ayurved Department, 3705 hospitals/ dispensaries are functioning in

the State which are depicted in the table given below:-

Table - 7.2.3

Therapy	Category °A' Hospital		Category °A' Dispensary		Category °B' Dispensary		Total		Grand Total
	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban	
1. Ayurved	22	56	493	70	2784	86	3299	212	3511
2. Homeo-pathy	-	2	-	7	54	47	54	56	110
3. Unani	-	3	3	6	36	32	39	41	80
4. Naturo-pathy	-	2	-	-	1	1	1	3	4

Apart from the above, 5 mobile Ayurvedic Medical Units in Kota, Banswara, Barmer, Jaisalmer and Bikaner are working. A Mobile Surgical Unit with 200 beds is also functioning under the Ayurvedic Department with its headquarter at Ajmer and medical facilities are being provided for specific disease in rural and remote areas.

4 Rasayan Shalas at Ajmer, Jodhpur, Bharatpur and Udaipur are also functioning under Ayurved Department. The medicines prepared in these Rasayan Shalas are supplied to Ayurved, Unani and Naturopathy Hospitals/ Dispensaries.

7.3 <u>FAMILY WELFARE</u>

An intensive Family Welfare Programme is being launched in the State for achieving the goal of small family, for which target free approach has been adopted during the year 1996-97. Upto December, 1996, 73,071 sterilization operations were performed, 1,15,670 I.U.D. inserted. Apart from this, 3,40,486 oral pills and 5,24,152 condoms were distributed upto December, 1996 which would lead to appreciable increase in the number of couples protected.

Apart from this, birth control measures have been provided in every Sub-Centre, Primary Health Centre, Community Health Centre, Dispensary and Hospital etc. The facility relating to birth control measures have also been arranged in every village by opening contraceptive depots. Emphasis is also being given to social marketing of contraceptives, community based distribution of contraceptives schemes. "Jan Mangal" has been extended to all the districts of the State. The new strategy adopted by the State will help in decline in birth and infant mortality rates.

Raj Lakshmi Bond Scheme has been simplified from June, 1996 wherein restriction of age limit of spouse has been eliminated. The amount of the bond is prescribed to Rs. 1500 for all. 48,229 families have been benefited under this scheme so far since 1992-93. In order to give a new dimension to Family Welfare Programme, a new scheme "VIKALP" has also been launched in two districts of the State namely Tonk and Dausa.

7.4 **WATER SUPPLY**

The problem of availability of safe drinking water in the State is very complex on account of geographical diversities, and limited availability of both ground water and surface water. The State Government has assigned a very high priority to the programme of providing safe drinking water to the people.

During the Year 1996-97, an amount of Rs. 301.80 crores was made available under State plan for drinking water supply. Out of which Rs. 157.30 crores were earmarked for urban areas, and Rs. 144.50 crores to rural areas.

Concerted efforts are being made to overcome drinking water problems in rural areas of the State. The number of villages covered under drinking water facilities through various water supply sources viz, tubewell, hand pump etc. and conventional water sources and water supply schemes up to 1995-96 is 37274.

During the year 1996-97 (upto December, 1996) drinking water facilities have been provided in 92 main habitations and 2690 other habitations and 553 partially covered villages were fully covered against a target of 5000 villages.

7.5 **HOUSING**

Due to the fast increase in population and limited resources, the housing problem is increasing day by day in the State. For solving this problem, houses for economically weaker sections, low income group and middle income groups are being provided by the Rajasthan Housing Board. Total number of registered applicants with the Rajasthan Housing Board since beginning stood at 207538 upto the end of November, 1996. Activities of the Housing Board are given in the following table:-

Table - 7.5.1

(Number)

Activities	Achievements upto 30.11.96 since beginning	Year 1996-97	
		Target	Achivement upto 30.11.96
1. Houses taken for construction	143612	9525	1141
2. Houses completed	137996	5933	850
3. Houses allotted	133114	-	1867
4. Possession given	118572	9050	2573
6. Houses under construction	5616	-	-

7.6 **WELFARE OF BACKWARD CLASSES**

Social Welfare Department of the State is functioning for the welfare of scheduled castes, scheduled tribes and other backward castes by way of providing them facilities such as free hostel facilities, scholarships, book banking, for their

educational development. The department is managing 611 hostels for the students of these classes including 20 new hostels opened this year by which 21298 boys/girls are being benefited in the State.

During the year 1996-97, an amount of Rs. 50 lakhs has been spent for developing infrastructural facilities in 67 sambal villages. Under "Justice to Scheduled Castes" scheme of 20 Point Programme. 1,10,774 scheduled caste families have been benefited upto December, 1996 against a target of 1.95 lakh for the year 1996-97.

Under welfare of scheduled tribes, various developmental programmes pertaining to socio-economic upliftment of tribals are being implemented by T.A.D. and other Departments in the State.

The declared tribal sub-plan area consists of 23 panchayat samities of district Banswara, Dungarpur, Chittorgarh, Udaipur and Sirohi. As per Census of 1991, the total population of tribals in Rajasthan is 54.75 lakhs, out of which 24.02 lakhs are residing in tribal sub-plan area.

A total provision of Rs. 45671.80 lakhs has been kept in 1996-97 for the development and welfare of scheduled tribes. Out of this Rs. 34221.67 lakhs have been provided under State plan, Rs. 2040.30 lakhs under Special Central Assistance, Rs. 1290.72 lakhs under Institutional Finance and Rs. 8119.11 lakhs under Centrally Sponsored Schemes.

An amount of Rs. 20966.85 lakhs has been spent upto December, 1996 against the annual provision of Rs. 45671.80 lakhs kept for 1996-97. The sectorwise allocations under Tribal Sub-Plan for the year 1996-97 and expenditure incurred upto

December, 1996 are depicted in the following table:-

Table - 7.6.1

(Lakh Rs.)

Sector	Allocation	Expenditure upto Dec., 1996
Agriculture and Allied Services	4993.13	1624.56
Rural Development	8619.82	2896.31
Irrigation	6789.46	4389.14
Electricity	9228.85	4707.40
Industries and Mines	1378.23	489.30
Transport and Communication	2175.74	750.46
Scientific Services	42.98	9.73
Social and Community Services	12165.53	6030.46
Economic Services	155.13	29.97
Other Services	122.93	39.52
Total	45671.80	20966.85

7.7 - **SOCIAL WELFARE**:

Various social welfare programmes like welfare of women, children and handicapped persons, pension to old aged and handicapped, probationary services and schemes relating to Children Act are being implemented by Social Welfare Department of the State.

In view of educational and economic upliftment of handicapped persons a number of facilities including economic assistance are being provided. A programme to identify the handicapped, the work of issuing Identity Cards to those whom assistance is being provided by the Government, has been initiated. The Identity Cards have been issued to handicapped persons in Jaipur District. Various programmes are also being implemented to improve the quality of life and cater to the special needs of vulnerable sections like children, women and handicapped.

7.8 - DEVELOPMENT OF WOMEN AND CHILDREN

Under Integrated Child Development Programme, at present 191 Rural and Urban Child Development Projects are being implemented in all the 31 districts of the State. Apart from these, five Child Development Projects are also being operated through non-Government organisations.

Financial progress of work in the field of 'Nutrition Programme' is given below:-

Table - 7.8.1

(Rs. in Lakh)

Scheme	Provision 1996-97	Expenditure upto Dec., 1996
1. Centrally Sponsored	3749.11	2005.73
2. State Plan	1650.00	654.30

During 1996-97 (upto December, 1996) 11.42 lakh children have been benefited under Nutrition and 5.93 lakh children have been benefited in Pre-School Non Formal Education programmes.

Various schemes like Mahila Mandal, Kishore Balika Scheme and DWCRA are also being implemented for welfare of women in the State.

*****

8. RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ

The main objectives of the rural development programmes are eradication of poverty among rural masses, generation of more employment and more investment in rural areas to enable them to lead better social and economic life. To achieve these objectives, various State and Centrally sponsored Schemes / Programmes remained under implementation during 1996-97 also.

8.1 POVERTY ALLEVIATION PROGRAMMES

Integrated rural development (IRDP) Trysem, and Jivan Dhara are the main schemes/programmes of poverty alleviation .

Under Integrated Rural Development Programme (IRDP) for which per family investment was Rs. 14,500 during the year 1995-96 for which a target upto Rs. 20,000 has been fixed during the year 1996-97 for effective improvement of the programme, 28,437 families have been benefited by providing subsidy amounting Rs. 17.87 crores and loan of Rs. 53.06 crore by the end of December, 1996 during the current year.

Under TRYSEM Scheme 2,261 youth were trained in different trades by spending an amount of Rs. 1.26 crore upto December, 1996 and 4,194 youth were under training. The training is being imparted to the youth looking to the local needs and to increase possibilities self employment.

Indira Awas Yojana which was previously the part of Jawahar Rojgar Yojana (JRY) is being implemented independently from the year 1996-97 for providing more houses in rural areas. 20,455 houses have been completed by the end of December, 1996 and 26,917 houses are under construction.

Jeevan Dhara Yojana (JDY) is also being implemented independently from the year 1996-97. Under this scheme cent percent Government subsidy

is being provided to small and marginal farmers of poor families for construction of irrigation wells. During the current year, 1,422 wells have been constructed by the end of December, 1996 and 6,249 wells were under construction.

8.2 **DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE AND GENERATION OF EMPLOYMENT PROGRAMME:**

Mainly Jawahar Rojgar Yojana (JRY), Employment Assurance Guarantee Scheme, Tees Zila Tees Kaam, Un-tied Fund, Apana Gaon Apana Kaam and Gramin Vikas Kendra Yojana etc. are covered under this programme.

The primary objective of Jawahar Rojgar Yojana (JRY) is to generate additional gainful employment opportunities for unemployed and under employed persons and to create public utillity assets through construction works in rural areas. 79.82 lakh mandays have been generated by spending Rs. 41.52 crore under this scheme upto December, 1996 during the current year.

Employment Assurance Guarantee Scheme was started in the year 1993-94 in 122 blocks. Under this scheme, employment is provided to atleast two persons of a family living below poverty line for 100 days during a year. At present this scheme is being implemented in 204 blocks. 159.67 lakh mandays employment have been generated by spending Rs. 75.99 crore upto December.1996 during the year 1996-97.

Apna Gaon Apna Kaam scheme was taken up from the year 1991 for creating additional employment through construction in rural areas. During 1996-97, an amount of Rs. 20.66 crore (including public participation) have been spent upto December, 1996 and 1390 works of basic public utilities were completed. In addition to this 2678 works were under progress.

Tees Zila Tees Kaam Scheme is being implemented since 1991-92 in all the districts of the State. During The year 1996-97, Rs. 16.11 crore have been spent for providing drinking water facilities upto december, 1996.

Under the scheme of Un-tied Fund, an amount of Rs. 17.31 crores have been spent upto December,

1996. The works costing upto Rs. 5 lakhs relating to public utility such as water supplies, link roads, bridges, schools, medical and health buildings etc. can be got done by the members of the Legislative Assembely in their constituencies during a year.

Gramin Vikas Kendra Yojana is being implemented since 1995-96 in the state. Under this scheme, the works relating to infrastructural development are being carried out in 1185 selected villages and 3.54 crores have been spent by the end of December, 1996 during the current year.

8.3 AREA DEVELOPMENT PROGRAMME:

Desert Development Programme (DDP), Drought Prone Area Programme (DPAP), Mewat Vikas, Dang Vikas, Border Area Development Programme are the main programmes/schemes of area development programme.

The Desert Development Programme (DDP) have been in operation since 1977-78 with basic objective to restrict the expansion of desert in the State. At present this programme is being implemented in 85 blocks of 16 districts of the State. During the year 1996-97, an amount of Rs. 14.46 crore have been spent upto December, 1996.

Drought Prone Area Programme (DPAP) was initially started in the year 1974-75. At present this programme is being implemented in 32 blocks of 10 drought affected districts and an amount of Rs. 1.35 crore have been spent for various watershed development works upto December, 1996 during the year under review.

Under Mewat Area Development Programme an amount of Rs. 2.00 crore have been kept for development of Meo Area in the districts of Alwar & Bharatpur. Rs.1.19 crore have been spent upto December, 1996 for development of roads, construction works of water supply, education, and medical and health institutions.

Dang Area Development Scheme is also being implemented since 1995-96 in 332 Gram Panchyats of

7 districts. During the current year Rs. 3.13 crores have been spent upto December, 1996 for various developmental works.

Revamped Boarder Area Development Programme is being implemented since 1993-94 in 13 developmental blocks of 4 districts situated on International Border of the State (Barmer, Jaisalmer, Bikaner and Ganganagar). At present these entire districts have been brought under the programme for maintaining security, law and order. During the year 1996-97, an amount of Rs. 9.09 crore have been spent upto December, 1996.

8.4 IRRIGATION POTENTIAL AND ENERGY DEVELOPMENT PROGRAMME :

Massive programme is being implemented in all the districts of the State since 1991-92. Under this programme, assistance is being provided by the State Government to small and marginal farmers for minor irrigation works, in view of increasing the agricultural production in the State. During the year 1996-97 an amount of Rs. 1.66 crore have been spent upto December, 1996 and 2210 small and marginal farmers have been benefited. The Community Water Lift Irrigation Scheme is also being implemented in the State with the assistance of World Bank.

For development of non-conventional sources of energy in the rural areas, Bio-Gas Development Programme is being implemented since 1981-82. Under this programme subsidy is provided for installation of bio-gas plants. 857 bio-gas plants have been installed by the end of December, 1996 and 221 plants were under construction during the current year.

An amount of Rs. 120.43 crores have been allotted to Community Development and Panchayats during the year 1996-97 for revitalisation of Panchayati -Raj, (Block level administration) and rural sanitation moderanisation of Zila Parishads and Panchayat samities buildings, Panchayat Bhawan (Chaupal) opening VLW Training Centre, Installation of computer,Development Grant for PRIS (TFC),grants for PRIS (SFC) and information communication and education etc. during the year 1996-97 under State Plan. Besides, Rs. 10 crores have also been made available to housing head for village housing and housing development projects.

*****

9. OTHER PROGRAMMES

9.1 TWENTY POINT PROGRAMME:

Alleviation of poverty and improving the quality of life of the people below poverty line is the primary objective of planned development. The 20 Point Programme (TPP) as a package for poverty alleviation and improvement in quality of life has been in operation since 1975. The package has since been restructured twice in 1982 and 1986.

In the changing economic scenario with greater emphasis on the decentralised planning and freedom for market forces, the Twenty Point Programme, 1986 provides the much needed safety net to the deprived and those living below the poverty line. The Twenty Point Programme thus has a vital role to play to ensure growth with equality and social justice in short raising the quality of life.

Rajasthan has evolved a strategy of effective implementation of the multi-dimensional programme that consists of allocation of plan funds, quantification of physical targets and assignment of responsibilities at various levels. A monitoring system has been devised for building up a reporting system from the grass root to the top.

9.2 FAMINE / FLOOD RELIEF:

The year 1995-96 witnessed delayed and un-evenly distributed rains and unfavourable weather conditions. Consequently, 25478 villages of 29 districts were declared as scarcity affected. The relief works which were started during 1995-96 continued upto July, 1996. An amount of Rs. 210.03 crores has been allotted to concerned departments for providing employment, drinking water and arrangement of fooder etc. during 1996-97.

The behaviour of the monsoon in Rajasthan is usually erratic and uncertain. The year 1996-97 experienced very good rains and even heavy and abnormal rains in some parts of the State and

created flood situation. During the year 1996-97, an amount of Rs. 33.12 crores has been allotted to concerned District Collectors and departments for providing relief to the flood affected persons and for reconstruction works.

9.3 **SMALL SAVINGS**

Role of small savings has become very important in State's economy, since 75 percent of the total collection can be taken back in the form of long term loans from the Government of India. Hence Small Savings contribute substantially to the financial resources of the State. The State Government has declared various incentives to create atmosphere for small savings which has resulted into an appreciable increase in small savings. The savings of households, individuals, corporates and the institutions are channelised into investments for the economic development of the State.

A target of Rs. 719 crores has been fixed for the year 1996-97, out of this Rs. 419.88 crores have been collected till December, 1996 which is 58.40 percent of the target. It is expected to achieve cent percent annual target i.e. Rs. 719 crores of net deposits by the end of March, 1997.

As against the target of Rs. 550 crores in B.E., 1996-97, the State Government, has already availed Central Government loans of Rs. 563.64 crores against net small saving collections upto December, 1996.

Collection position under various small saving schemes during 1995-96 and 1996-97 is given in the following table:

SMALL SAVING DEPOSITS

Table - 9.3.1 (Rs. in lakhs)

Securities	1995-96		1996-97 (upto December,96)	
	Gross	Net	Gross	Net
1	2	3	4	5
1. Post Office Saving Accounts	24386.29	1580.88	20720.05	2681.75
2. Recurring Deposits	30090.59	13387.80	26791.30	10172.89
3. Cumulative Time Deposits.	7.94	(-) 81.73	3.81	(-)14.05
4. Post Office Time Deposits	4452.34	(-)5384.24	2775.18	(-)1057.07
5. Monthly Income Scheme.	7391.01	4855.91	4697.78	2792.45
6. National Savings Certificate	743.68	(-)4982.68	442.77	(-)2014.19
7. Retired Employees Scheme	-	-	21.34	21.34
8. Indira Vikas Patra.	16532.22	5278.06	12531.51	6176.02
9. Kisan Vikas Patra	35623.15	24708.32	24340.10	15183.92
10. National Savings Certificates VIII Issue	18762.78	16431.85	7114.51	4698.44
11. Old Saving Certificates.	-	(-)1801.67	-	(-) 306.53
12. Public Provident Fund.	11341.58	9092.80	5759.98	3652.79
TOTAL	149331.58	63085.30	105198.33	41987.76

It is revealed from the above table that Post Office Savings Accounts, Recurring Deposits, Kisan Vikas Patra and Indira Vikas Patra continued to be the most popular schemes. These four schemes accounted for 71.04 percent of the total gross collection in 1995-96 and 80.21 percent during 1996-97 (upto December, 1996).

*****

10. ECONOMIC REFORMS IN RAJASTHAN

The State has made constant efforts to step up the investment in developmental activities, despite the constrained fiscal enviornment, by incorporating better fiscal management and by instituting structural economic reforms in the budgetary process.

As a result, there has been a 48 percent improvement in the revenue deficit during the current financial year over the last year. Further, there is a steady increase in the resources of the State which reflected 124.46 percent increase in tax revenue which has gone from Rs. 1216.50 crores in the year 1990-91 to Rs. 2730.60 crores in the year 1995-96. Similarly, the total revenue of the State has increased from Rs. 3647.89 crores in 1990-91 to Rs. 7629.69 crores in 1995-96 registering an increase of 109.15 percent over a period of five years.

10.1 COMMERCIAL TAXES:

The State has taken initiatives for re-structuring the State Sales Tax system through rationalisation of the complex multi-layered system to a simpler one. The number of tax slabs have been revised thoroughly and a new simplified and transparent Rajasthan Sales Tax Act, 1994 has been introduced w.e.f. October 1, 1995.

Self-Assessment Schemes have been introduced both in respect of Commercial Taxes and Land & Building Taxes. A Green Channel for Compounded Levy has been introduced for Sales Tax in case of Brick Kilns, Sarafa, Mini Cement Plants and Restaurants. A new Self-Assessment Scheme, 1995 has been introduced for the first time which is unique in the country. Value Added Tax (VAT) is under contemplation of the Government.

All check-posts of Commercial Taxes Department and Transport Department have already

been abolished with effect from 1st May, 1995 to ensure free flow of trade and commerce. Computerisation of the departments on a major scale is already underway.

10.2 **OTHER TAXES**:

Under Motor Vehicle Taxes, a proposal to simplify the relevant taxation law intended to tax Transport and strengthening of the State Transport Authority (STA) into an independent regulator are under active consideration of the State Government.

10.3 **POWER SECTOR**:

Government of Rajasthan has initiated number of reforms and is restructuring measures its power sector.

Action is well under-way for creating generation capacity of power for 4000 M.W. in private sector through International competitive bidding route.

Power Sector Reforms Legislation, that recasts Government of Rajasthan's role in the sector by separating policy making for commercial operations. This includes a Government of Rajasthan commitment to reduce and eventually eliminate subsidies through tariff reforms, by promoting system efficiency and by implementing demand side management. Reform Bill for establishment of an autonomous Rajasthan Electricity Regulatory Commission has also been sent to the Central Government for examination.

Rajasthan State Electricity Board is being restructured to achieve managerial autonomy, financial independence, enhanced operating efficiency and quality of service. This includes corporatization of R.S.E.B. under the Companies Act, 1956 as Rajasthan State Electricity Corporation Limited (RSEC).

Involvement of the private sector in electricity distribution through competitive bidding on pilot basis has been initiated.

******